{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
गुरूवार 20 अगस्त 2026
श्रावण शुक्ल 08 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 326
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स - 77,235.46
निफ्टी - 24,154.90
सोना - 1,64,849
चांदी - 2,50,000
डॉलर - 95.78

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 को उम्रकैद

औरैया। औरैया जिले के सबसे चर्चित और सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई व पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, भाई रामू पाठक समेत कुल 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पूर्व एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विनय प्रकाश ने सुनवाई पूरी करते हुए मामले से जुड़े सभी 10 आरोपियों कमलेश पाठक, संतोष पाठक, रामू पाठक, कुलदीप, विकल्प, आशीष दुबे, लला चौबे, शिवम अवस्थी, गनर अवनीश प्रताप सिंह और भागवत आचार्य राजेश शुक्ला को हत्या, हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया था।

पत्रकार तेजपाल की उम्रकैद की मांग

गोवा। गोवा सरकार ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग की। इसे लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल को उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उनका दो बार यौन उत्पीड़न किया था।

पांच मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 मौतें

कोलकाता। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित पांच मंजिला बिल्डिंग में मंगलवार रात करीब 1:45 बजे आग लग गई। बिल्डिंग के अंदर कई होटल थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल है। सभी बेहोशी की हालत में मिले थे। 6 लोग घायल हुए हैं। अब तक 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने के वक्त होटलों में ज्यादातर लोग सो रहे थे। बिल्डिंग में धुआं भरने के कारण उनका दम घुटने लगा। मरने वालों में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंचीं।

कुछ ना कहना

नीट परीक्षा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला

यूपीएससी जैसा मजबूत मॉडल बनाएं

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत बताई। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को यूपीएससी की तरह भरोसेमंद और मजबूत परीक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए। साथ ही टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ रखने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों को संस्था में शामिल करने और उन्हें बार-बार ट्रांसफर नहीं करने की बात कही। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नीट के लिए पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने दावा किया कि सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है।

ऐसे सुरक्षित रखा जाता है नीट का पेपर

नीट के प्रश्न बैंक कई मॉडरेटर तैयार करते हैं। इसके बाद 100-100 सवाल चुनकर चार अलग पेपर तैयार किए जाते हैं। इनमें से दो पेपर एनटीए महानिदेशक द्वारा चुने जाते हैं। अंतिम पेपर कौन-सा होगा, इसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं होती। करीब 500 सवालों का प्रश्न बैंक 13 भाषाओं में तैयार किया जाता है। सरकार के मुताबिक इसका अनुवाद मानव विशेषज्ञों के जरिए कराया जाता है। चयनित पेपर दो निर्धारित प्रिंटिंग प्रेस में भेजे जाते हैं। वहां सीसीटीवी और सीआईएसएफ की निगरानी रहती है। प्रिंटर को भी यह जानकारी नहीं होती कि वह किस परीक्षा का प्रश्नपत्र छाप रहा है। पेपर ले जाने वाले व्यक्ति के पास डिजिटल चाबी होती है, लेकिन बॉक्स खोलने का कोड उसके पास नहीं रहता। यह कोड एनटीए महानिदेशक की अनुमति के बाद जारी किया जाता है। प्रश्नपत्र ऐसे विशेष लोहे के बॉक्स में रखे जाते हैं, जिन्हें लॉक तोड़े बिना खोला नहीं जा सकता।24 प्रश्नपत्रों के पैकेट में सवालों का क्रम अलग-अलग रखा जाता है। पैकेट पर वॉटरमार्क नंबर, शहर, परीक्षा केंद्र और पैकेट नंबर दर्ज होता है। प्रश्नपत्रों के दो सेट अलग-अलग बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है और संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने वाले वाहन में जीपीएस लगाया जाता है। वाहन की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है और पुलिस सुरक्षा में प्रश्नपत्र केंद्र तक पहुंचाए जाते हैं। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले दो छात्रों की मौजूदगी में बॉक्स खोला जाता है। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाती है। प्रत्येक कक्षा में 24 छात्रों के लिए अलग पैकेट होता है। कक्षा समन्वयक पैकेट छात्रों को सौंपता है और छात्र स्वयं उसे खोलते हैं।

टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों पर कोर्ट का जोर

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को संकेत दिया कि केवल कागजी और प्रशासनिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। परीक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता को शामिल करना जरूरी है। कोर्ट ने टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों की नियुक्ति के साथ यह भी कहा कि ऐसे अधिकारियों का बार-बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ताकि परीक्षा प्रणाली में विशेषज्ञता और निरंतरता बनी रहे। कोर्ट की टिप्पणी का संदेश साफ है- नीट जैसी देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में सिर्फ पेपर की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा।

केन-बेतवा प्रोजेक्ट के प्रभावितों से मुलाकात का वीडियो जारी कर राहुल गांधी बोले

आदिवासी भाई-बहनों की लड़ाई में साथ हूं मैं

छतरपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बुंदेलखंड में चल रहे विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों के समर्थन का ऐलान किया है। परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों की समस्याओं और विस्थापन से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, भूमि अधिकार, आजीविका और वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे राहुल गांधी के सामने रखे गए। राहुल गांधी ने बुधवार को इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि अपने जायज हक की लड़ाई लड़ रहे बुंदेलखंड के लोगों को सम्मान और समर्थन मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आदिवासी परिवारों की इस लड़ाई में वे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं।

आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी को बताया कि केन-बेतवा परियोजना से पन्ना और छतरपुर जिले के कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि परियोजना के कारण आदिवासी समुदाय के सामने विस्थापन के साथ-साथ आजीविका का संकट भी खड़ा हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े मुद्दे भी उठाए। आंदोलनकारियों का दावा है कि कई प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले भूमि और कानून के तहत मिलने वाले पुनर्वास अधिकार पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाए हैं। मुलाकात के दौरान परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मुद्दा भी उठाया गया। आंदोलनकारियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के वन क्षेत्रों पर परियोजना के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उनका आरोप है कि परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। आंदोलनकारियों ने ग्राम सभा की सहमति और परियोजना से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठाए।

संसद से सड़क तक आवाज उठाने का भरोसा

राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनके पुनर्वास, भूमि अधिकार और विस्थापन से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाया जाएगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर खुद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर आंदोलनकारियों के साथ खड़े होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना को गरिमापूर्ण पुनर्वास, वैकल्पिक आजीविका और कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए बिना बेघर नहीं किया जाना चाहिए।

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 13041 करोड़ रुपये के रेल-रोड प्रोजेक्ट मंजूर, हावड़ा-चेन्नई रूट पर बढ़ेंगी लाइनें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 13,041 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और एक हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि तीन रेलवे परियोजनाएं हावड़ा-चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हावड़ा से चेन्नई तक लगातार चार रेलवे लाइन का कॉरिडोर तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे ज्यादा ट्रेनें चलाना आसान होगा और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।

हावड़ा-चेन्नई रेल रूट पर बढ़ेंगी लाइनें

हावड़ा-चेन्नई रेल मार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे कॉरिडोर में से एक है। इस रूट से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बीच बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियां चलती हैं। कैबिनेट ने इस रूट पर तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें खड़गपुर-भद्रक के बीच चौथी लाइन, भद्रक-हरिदासपुर के बीच चौथी लाइन और गुम्मिडिपुंडी-गुडूर के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।

किस रूट पर कितना पैसा होगा खर्च?

खड़गपुर-भद्रक (चौथी लाइन)= 173 किमी लंबे इस रूट पर 3,352 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ता है और सुवर्णरेखा नदी पर एक बड़ा पुल भी बनेगा।

भद्रक-हरिदासपुर (चौथी लाइन)= ओडिशा में 75 किमी के इस हिस्से पर 1,583 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें बैतरणी और ब्राह्मणी नदियों पर दो बड़े पुल शामिल हैं।

गुम्मिडिपुंडी-गुडूर (तीसरी और चौथी लाइन)= 90 किमी लंबे इस कॉरिडोर पर 2,229 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश, दिल्ली से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

वाहनों को बिना बीमा पेट्रोल नहीं

नई दिल्ली। बिना वैध बीमा के वाहन चलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऐसे पायलट प्रोजेक्ट को लागू करे, जिसमें वैध बीमा नहीं होने पर पेट्रोल पंपों से वाहन को ईंधन ही न मिले। कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत दिल्ली से की जा सकती है। बुधवार को यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के सामने आया। केंद्र की ओर से पेश वकील ने चार अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस व्यवस्था को लेकर कुछ चिंताएं हैं। इस पर पीठ ने साफ कहा कि आपको इसे लागू करना होगा। कोर्ट ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू किया जा सकता है।

केंद्र के वकील ने बताया कि इसके लिए तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल पंप डीलरों के साथ बैठक करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक ठोस प्रस्ताव पेश करने को भी कहा है। इसमें चार अगस्त के फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने की समयसीमा बतानी होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

बिना बीमा वाहनों की पहचान में मिलेगी मदद

सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था के दो बड़े फायदे बताए थे। पहला, इससे बिना बीमा या बिना पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दूसरा, वाहन मालिकों पर वैध बीमा कराने का दबाव बनेगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के प्रावधानों का जमीन पर पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए एएनपीआर यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

टोल प्लाजा पर भी ऑटोमैटिक व्यवस्था के निर्देश

चार अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों के असर पर भी ध्यान दिया था। कोर्ट ने कुछ कॉरिडोर पर पायलट प्रोजेक्ट लागू करने का निर्देश दिया था। इसमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रोकने के बजाय टोल प्वाइंट से गुजरने वाले वाहनों की ऑटोमैटिक पहचान की व्यवस्था करने की बात कही गई थी।

सस्ती दवा, महंगा ब्रांड और करोड़ों का खेल

4.91 करोड़ की नकली दवाएं जब्त

बंगलूरू। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के ड्रग एनफोर्समेंट विंग ने जांच अभियान के दौरान 4.91 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की नकली दवाएं जब्त की हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदादी स्थित कुरुबाराकेरेनाहल्ली के एक फार्महाउस में बिना लाइसेंस दवाओं की रीपैकेजिंग और रीलेबलिंग का काम चल रहा था। विभागीय टीम को 18 अगस्त को इस अवैध गतिविधि की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि फार्महाउस में दूसरे राज्यों से सस्ती दवाएं मंगाई जाती थीं। इसके बाद उन्हें नई शीशियों में भरकर ऐसे लेबल लगाए जाते थे, जिससे वे महंगी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयातित दवाओं जैसी नजर आएं। विभाग के कमिश्नर श्रीनिवास के. ने कहा कि नकली दवाओं में प्रभावी औषधीय सामग्री नहीं होती या उनमें गलत अथवा हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं।

दिल्ली के सीएनजी पंप पर ट्रक में सिलेंडर धमाका, 3 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास बुधवार को एक सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा हो गया। गैस भरवाने पहुंचे एक ट्रक में अचानक जोरदार धमाका हो गया। हादसे में तीन पंप कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के मुताबिक, हादसा दोपहर करीब 3 बजकर 37 मिनट पर हुआ। ट्रक में लगे सीएनजी सिलेंडर के फटने की आशंका जताई जा रही है। धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए। सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया। शुरुआत में तीन दमकल गाड़ियां भेजी गई थीं, बाद में कुल सात दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर तैनात की गईं।

धमाके की चपेट में आने वाले लोग ट्रक के आसपास मौजूद थे। मृतकों में पंप कर्मचारी होने की आशंका जताई गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें हादसे के कारणों की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक तौर पर सिलेंडर में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि विस्फोट की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

आप नेता सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में हुए थे गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने जल बोर्ड घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, एक आरोपी और अडीजेबी कर्मचारी अंकित श्रीवास्तव को दो दिन के लिए एसीबी की हिरासत में भेजा गया है। एसीबी ने सभी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार लोगों में जैन के अलावा अडीजेबी के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं। एसीबी ने कोर्ट में जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत 5 आरोपियों के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत और अंकित श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी मांगी थी।

जैन बोले- पंजाब चुनाव की वजह से गिरफ्तारी

कोर्ट ले जाते समय सत्येंद्र जैन ने अपनी गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से जोड़ते हुए कहा- यह पंजाब चुनाव की वजह से किया गया है। उनके वकील ने भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसके आधार पर सवाल उठाए। जैन के वकील ने कोर्ट में कहा कि एफआईआर मई 2024 में दर्ज हुई थी, लेकिन जैन को पहली बार 5 अगस्त 2026 को बुलाया गया और मंगलवार को फोन के जरिए दोबारा बुलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। उदित प्रकाश राय के वकील ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राय फिलहाल मिजोरम सरकार में सचिव के पद पर तैनात हैं।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की भरण-पोषण, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की भरण-पोषण, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा, उपेक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मान और संवेदनशील व्यवहार करता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की

सुरक्षा और गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास परिस्थितियों के अनुसार बेदखली का आदेश देने की शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता की अपील पर आया। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से बाहर निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिया था। यह मकान उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी। मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि गुप्ता की 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू को मकान से हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को एसडीएम के आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था बेदखली का आदेश

बेटे और बहू ने एसडीएम तथा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने माना था कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने की स्पष्ट शक्ति नहीं देता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल और जिला प्रशासन के आदेशों को रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

ट्रिब्यूनल को कार्रवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि कानून की व्याख्या केवल उसके शब्दों तक सीमित नहीं की जा सकती। कानून का मूल उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं, जबकि धारा 8 उन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्रदान करती है। वहीं धारा 27 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित करती है।

मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे

ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले- पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा

मुंबई। मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा, जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी कामचलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में एक महीने तक चलेगा।

ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा।

आरटीओ की टीमें जांच करेंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी

मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में इस एक महीने के अभियान की निगरानी करेंगे। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वॉड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेंगी और नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगी। जांच के दौरान वेरिफिकेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

पीएम आवास योजना में कई पात्रों को कर दिया अपात्र, अपात्रों को दिया योजना का लाभ

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में ऐसे कई हितग्राही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की राह देख रहे हैं लेकिन लाख जतन के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे हितग्राहियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ताजा मामला जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बकोड़ी का है ।जहां के कई हितग्राहियो को वर्षो के लंबे इंतजार के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही दिया गया है। जिसके चलते वे झोपड़ी और जर्जर कच्चे मकान में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। जिन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौपा है।उक्त मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत सत्यापन करने वालो ने गांव के कई पात्र ग्रामीणों को अपात्र की श्रेणी में डाल दिया है जबकि कई अपात्र लोगो को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है।जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्रामीणों

ने उनके घर का सर्वे कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। जहां ग्रामीणों ने जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न देते हुए ,गैर जरूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ देने, पीएम आवास योजना के तहत उनके मकान स्वीकृत ना कराने और योजना का लाभ देने के लिए जरूरतमंदों को तरह-तरह से गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं उन्होंने आवेदन निवेदन पर भी समस्या का समाधान न किए जाने की बात कहते हुए तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण कर उन्हें पक्के मकान के लिए आवास योजना की सौगात दिए जाने की गुहार लगाई है।

77 पात्र हितग्राहियों को कर दिया अपात्र- खेमनलाल

ग्राम पंचायत बकोड़ी उप सरपंच प्रतिनिधि खेमनलाल पंचेश्वर ने बताया कि उनके गांव में करीब 304 लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आया था जिसमें से 77 पात्र लोगों को अपात्र कर दिया गया है तो वही सूची में कई अपात्रों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्यापन करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी उन्होंने द्वेशपूर्ण भावना रखते हुए योजना के 13 नियमों का पालन नहीं किया जो पात्र हितग्राही थे उनमें से किसी के नाम पर पक्का मकान ,किसी के नाम से खेती, किसी के नाम से चार कमरे का मकान,तो किसी के नाम से कार दर्शाकर उन्हें अपात्र कर दिया गया है।जबकि उनके पास ये सब नही है। हमारी मांग है कि जिन्होंने गलत सत्यापन किया है इसकी जांच होनी चाहिए हमारे पंचायत के सरपंच ने तो साफ लिखित में दिया है कि जिन लोगों को अपात्र किया गया है अगर वे पात्र नहीं होंगे तो फिर ग्राम पंचायत में तालाबंदी कर दी जाएगी हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर पात्र सभी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए ताकि वे भी पक्के मकान में जिंदगी गुजार सके।

आईटीआई बालाघाट के पूर्व प्रशिक्षणार्थी शिवम विश्वकर्मा का असिस्टेंट लोको पायलट पद पर चयन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), बालाघाट के पूर्व प्रशिक्षणार्थी श्री शिवम विश्वकर्मा का असिस्टेंट लोको पायलट (Assistant Loco Pilot) के पद पर चयन एवं नियुक्ति हुई है। शिवम विश्वकर्मा, पिता दीपक विश्वकर्मा, ने आईटीआई बालाघाट से प्रशिक्षण सत्र 2016-2018 में टर्नर (Turner) ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। शिवम विश्वकर्मा का चयन साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR), हैदराबाद डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

बालाघाट की प्राचार्य श्रीमती सपना रहांगडाले एवं समस्त आईटीआई परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। संस्था परिवार ने कहा कि शिवम की यह सफलता उनकी मेहनत, लगन, समर्पण और आईटीआई में प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण का उत्कृष्ट परिणाम है। उनकी उपलब्धि से शासकीय आईटीआई बालाघाट का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। आईटीआई परिवार ने शिवम विश्वकर्मा के उज्ज्वल भविष्य, सफल सेवाकाल एवं निरंतर प्रगति की मंगलकामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए संस्था और जिले का नाम रोशन करेंगे।

डबल मनी मामले में पुलिस ने जारी की दसवीं सूची, 1582 निवेशकों के नाम हुए सार्वजनिक

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 19 अगस्त की देर रात निवेशकों की दसवीं सूची जारी की है। इस सूची में 78 नए निवेशकों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक सार्वजनिक किए गए निवेशकों की संख्या बढ़कर 1582 हो गई है। पुलिस ने सूची में शामिल सभी निवेशकों से अपील की है कि वे अपने चेक, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अन्य आवश्यक अभिलेख लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क पर पहुंचें और जांच में सहयोग करें।

डबल मनी मामले में पुलिस द्वारा एक-एक कर निवेशकों की पहचान की जा रही है और उनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि निवेशकों से उनके निवेश से संबंधित दस्तावेज और जानकारी मिलने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसी वजह से पुलिस लगातार सूची में शामिल लोगों से हेल्प डेस्क पहुंचने की अपील कर रही है। पुलिस द्वारा अब तक जारी सूचियों में पहली सूची में 113 निवेशकों के नाम शामिल थे। इसके बाद चार सूचियों में 150-150 निवेशकों के नाम सार्वजनिक किए गए। छठी सूची में 191 नाम जारी किए गए, जबकि सातवीं, आठवीं और नौवीं सूची में 200-200 निवेशकों के नाम शामिल किए गए। अब दसवीं सूची में 78 और नाम सामने आने के बाद सार्वजनिक किए गए निवेशकों की संख्या 1582 हो गई है। हालांकि पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती यह है कि सूची में नाम आने के बावजूद बड़ी संख्या में निवेशक अभी तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क तक नहीं पहुंचे हैं। इससे जांच की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। पुलिस स्पष्ट कर चुकी है कि जिन निवेशकों के नाम सूची में जारी किए गए हैं, वे ही अपने दस्तावेजों के साथ हेल्प डेस्क पर पहुंचे। जिन निवेशकों के नाम अभी सूची में नहीं आए हैं, उन्हें अपनी सूची जारी होने का इंतजार करना होगा। सूत्रों के अनुसार सूची में शामिल कुछ निवेशक शासकीय विभागों से जुड़े हो सकते हैं, हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में इस संबंध में स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस लगातार निवेशकों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें जांच के दायरे में ला रही है। डबल मनी मामले में लगातार सामने आ रहे नए नामों के बाद जिले में चर्चाएं भी तेज हैं। पुलिस की आगामी सूचियों और कार्रवाई पर निवेशकों के साथ-साथ आम लोगों की नजर बनी हुई है। वहीं, जिन निवेशकों के नाम सामने आ चुके हैं, उनके लिए अब अपने दस्तावेजों के साथ हेल्प डेस्क पहुंचकर जांच में सहयोग करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम रामेपुर में इसी ग्राम के एक युवक सुमित पिता ओमकार खैरवार 20 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इस युवक ने किस वजह से फांसी लगाई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है गढ़ी पुलिस जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था वह माता-पिता का इकलौता बेटा था जिसकी एक छोटी बहन है माता-पिता खेती किसानी करते हैं बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से सुमित मानसिक तनाव में चल रहा था। 18 अगस्त को सुमित घर में था दोपहर में माता-पिता गढ़ी साप्ताहिक बाजार आ गए थे। शाम को जब वे लोग घर पहुंचे तब उन्होंने घर के अंदर सुमित को फांसी पर लटके सूचना मिलते ही गढ़ी पुलिस ग्राम रामेपुर पहुंची और मृतक सुमित का शव अपने कब्जे में लिए। 19 अगस्त को सुमित का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है बताया गया कि सुमित मानसिक तनाव में था किंतु उसने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है ।

24 को कोटेश्वर धाम में विशाल रक्तदान शिविर

पद्मेश न्यूज। लांजी। रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। दुर्घटना, प्रसव, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन एवं आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर उपलब्ध रक्त किसी जरूरतमंद का जीवन

बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल लांजी के संयुक्त तत्वावधान में श्रावण माह के पावन अवसर पर 24 अगस्त 2026, सोमवार को कोटेश्वर धाम मंदिर लांजी में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का समय प्रात: 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।

आयोजकों ने बताया कि शिविर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा। स्वस्थ एवं पात्र व्यक्तियों द्वारा किया गया रक्तदान आपातकालीन परिस्थितियों में किसी के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आयोजक समिति ने क्षेत्र के नागरिकों, युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। समिति ने रक्तदान करें, जीवनदान करें का संदेश देते हुए सभी से इस सामाजिक एवं मानवसेवा के कार्य में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

बजट में अनुमान चूके तो विभागों से होगा जवाब-तलब

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू करने के साथ ही विभागों के बजट अनुमानों की जवाबदेही तय करने की तैयारी भी कर ली है। इस बार वित्त विभाग केवल अगले तीन वर्षों का रोलिंग बजट तैयार नहीं करेगा, बल्कि पिछले रोलिंग बजट में विभागों द्वारा लगाए गए अनुमानों की वास्तविक खर्च से तुलना भी करेगा। यानी विभागों ने जिस योजना, निर्माण कार्य या मद में जितनी राशि की जरूरत बताई थी, वास्तव में कितना खर्च हुआ और जरूरत का अनुमान कितना सही था, इसका बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 के साथ 2028-29 और 2029-30 का भी रोलिंग बजट तैयार करेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर प्रस्ताव मांगे हैं। विभागों को अपने बजट प्रस्ताव 7 सितंबर तक वित्त विभाग को भेजने होंगे। वित्त विभाग इस बार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में पिछले अनुमानों को आधार बनाकर उनकी सटीकता जांचेगा। किसी विभाग ने किसी योजना के लिए जितनी राशि प्रस्तावित की थी, उसके मुकाबले वास्तविक खर्च कितना रहा, इसे देखा जाएगा। इसी तरह विकास कार्यों, योजनाओं और अन्य मदों में अनुमानित जरूरत तथा वास्तविक जरूरत के बीच अंतर का भी आकलन होगा। यदि किसी विभाग के अनुमान में लगातार बड़ा अंतर पाया गया तो वित्त विभाग संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर सकता है। अधिकारियों को भविष्य में बजट अनुमान तैयार करते समय वास्तविक जरूरत, पिछला खर्च और योजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य बजट में कागजी जरूरत के बजाय वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान करना है।

हर प्रस्ताव के साथ बताना होगा पैसे का पूरा उपयोग

नए बजट में विभागों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि उन्हें कितनी राशि चाहिए। प्रस्ताव के साथ यह भी बताना होगा कि राशि कहां और क्यों खर्च की जाएगी। विभागों को योजना के तहत प्रस्तावित राशि, लाभार्थियों की संख्या, पिछले वर्षों में हुए खर्च, योजना से मिले परिणाम और भविष्य में संभावित वित्तीय आवश्यकता का विवरण देना होगा। इससे वित्त विभाग को यह तय करने में आसानी होगी कि किस योजना में वास्तव में कितने बजट की जरूरत है। बजट से जुड़ी जानकारी बीईएमएस पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। सरकार को मिलने वाले राजस्व और होने वाले खर्च को निर्धारित श्रेणियों में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व तथा विकास से जुड़े बड़े खर्चों को अलग-अलग दर्शाया जाएगा, ताकि बजट की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सके।

पहली बार नहीं, पिछले दो साल के डेटा से तय होगी जरूरत

वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 का बजट जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के आधार पर तैयार किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक योजना को पुराने बजट के आधार पर स्वत- राशि देने के बजाय नए सिरे से उसकी जरूरत और उपयोगिता का आकलन किया गया था। अब विभाग का मानना है कि पिछले दो वर्षों में योजनाओं की जरूरत, उपयोगिता और वास्तविक खर्च की व्यापक समीक्षा हो चुकी है। इससे पर्याप्त डेटा उपलब्ध है। इसी आधार पर 2027-28 का बजट तैयार किया जाएगा। इसलिए इस बार बजट को जीरो बेस्ड प्रणाली से तैयार नहीं किया जाएगा।

तीन साल आगे तक की जरूरत का भी देना होगा अनुमान

रोलिंग बजट का उद्देश्य सरकार को केवल एक वित्तीय वर्ष की जरूरत के बजाय आने वाले वर्षों की वित्तीय तस्वीर पहले से उपलब्ध कराना है। विभागों को 2027-28 के साथ 2028-29 और 2029-30 के लिए भी अपनी संभावित वित्तीय जरूरत बतानी होगी।

बरबसपुर में खुलेआम बिक रही कच्ची-पक्की शराबन्ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई रोक की गुहार

संस्थाओं के आसपास अवैध शराब बिक्री से छात्र-छात्राओं और युवाओं पर पड़ रहा असर

पद्मेश न्यूज। बालाघाट/लालबर्रा। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरिया के ग्राम बरबसपुर में कथित रूप से लंबे समय से चल रही अवैध कच्ची-पक्की शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शराब बिक्री पर रोक लगाने और अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ग्राम बरबसपुर में विगत कई वर्षों से हाथ भट्टी की कच्ची-पक्की शराब के साथ देसी-विदेशी शराब की बिक्री किए जाने की बात सामने आ रही है। उनका आरोप है कि गांव में शराब के कई अड्डे संचालित हैं, जहां आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शराब का सेवन करने पहुंचते हैं। इससे गांव के युवा वर्ग पर विपरीत असर पड़ रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि 17 अगस्त को ग्रामसभा में शराबबंदी को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके बावजूद शराब बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि ग्राम बरबसपुर के समीप शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं।जहां दूर-दराज से छात्र-छात्राएं आकर अध्ययन करते हैं और कई विद्यार्थी गांव में किराए के मकानों में रहते हैं।

शिक्षण संस्थाओं के पास ढाबों में शराब-मांस बिक्री का आरोप

शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थाओं के आसपास स्थित कुछ ढाबों में कथित रूप से अवैध रूप से मांस और शराब की बिक्री की जा रही है। इससे विद्यार्थियों के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात ग्रामीणों ने कही है। ग्रामीणों के अनुसार शाम के समय शराब के नशे में लोगों की आवाजाही और सड़क किनारे बड़े वाहनों के खड़े रहने से छात्राओं एवं महिलाओं को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव से लगे क्षेत्र में कालेज संचालित है। जिसके विद्यार्थी भी इन ढाबों पर पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की सहज उपलब्धता के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

गांव में टीबी मरीजों की संख्या का भी किया उल्लेख

शिकायतकर्ताओं ने गांव में करीब 30 से 35 लोगों के टीबी से पीड़ित होने का भी उल्लेख किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच शराब की अवैध बिक्री सामाजिक स्थिति को और प्रभावित कर रही है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने कहान्शराबबंदी के साथ विक्रेताओं पर हो कार्रवाई

ग्राम बरबसपुर निवासी सोहनलाल टेकाम ने बताया कि गांव में कच्ची-पक्की शराब की बिक्री हो रही है और शराब पीने के लिए बाहर से भी लोग पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान पास होने के कारण यहां पढ़ने वाले बच्चों और विशेषकर छात्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शाम के समय महिलाओं और बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है।वहीं ग्रामीण मोहरसिंह मुड़ताम ने कहा कि गांव में शराबबंदी किया जाना आवश्यक है। अवैध शराब बिक्री से युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर से शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कलेक्टर से ग्राम बरबसपुर के साथ-साथ आसपास के गांवों में भी कथित रूप से बिक रही देसी, विदेशी और हाथ भट्टी की कच्ची शराब पर रोक लगाने तथा मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

आवश्यकता है
अनुभवी महिला
कम्प्यूटर ऑपरेटर- 01 पद
हीरो शो रुम एजेंसी किरनापुर
संपर्क - 8308403437

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, बालाघाट

ईमेल- tobalaghat87@gmail.com दूरभाष- 07632-240226

क्रमांक/कोषालय/निविदा/2026/2351 दिनांक-14/08/2026

प्रेस विज्ञप्ति

अनुपयोगी अभिलेखों (रद्दी रिकॉर्ड) के विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कोषालय कार्यालय, बालाघाट में संधारित अनुपयोगी अभिलेखों रद्दी कागजात एवं रिकॉर्ड का जहाँ है, जैसा है (As Is Where Is Basis) के आधार पर विक्रय किया जाना है। उक्त सामग्री के विक्रय हेतु इच्छुक एवं अधिकृत स्क्रैप डीलरों/क्रेताओं से सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

1. निविदा जारी होने की तिथि एवं समय: 17.08.2026 को दोपहर 2:00 बजे से।
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 25.08.2026 को अपराह्न 4:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान- 27.08.2026 को सायं 4:00 बजे, जिला कोषालय अधिकारी, बालाघाट के कक्ष में।
4. धरोहर राशि (EMD)- रू.3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र), जो जिला कोषालय अधिकारी, बालाघाट के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
5. सामग्री का निरीक्षण: इच्छुक निविदाकार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालयीन समय प्रात: 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जिला कोषालय कार्यालय, बालाघाट में उपस्थित होकर विक्रय हेतु उपलब्ध अनुपयोगी अभिलेखों/सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं।
6. भुगतान एवं सामग्री उठाना: उच्चतम दर (H-1) वाले सफल निविदाकार को स्वीकृति/आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिवस के भीतर निविदा की संपूर्ण स्वीकृत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण राशि जमा करने के उपरांत विक्रय की गई सामग्री को अपने व्यय एवं उत्तरदायित्व पर कार्यालय परिसर से उठाना होगा।
7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर को सामग्री का निरीक्षण कर एवं उसकी स्थिति से पूर्णत: संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। बाद में सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता, स्थिति अथवा किसी अन्य आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत नियम एवं शर्तें जिला कोषालय कार्यालय, बालाघाट के नोटिस बोर्ड पर कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।

जिला कोषालय अधिकारी
बालाघाट (म.प्र.)

अपराध और जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस का धरना, सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसे विधायक

डबल मनी, चावल घोटाले और बिरसा में बच्चों की मौत का मुद्दा गरमाया

दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। अपराध और जनसमस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने 19 अगस्त को स्थानीय कालीपुतली चौक में धरना प्रदर्शन किया। धरने में कांग्रेस के चारों विधायक, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, विभिन्न ब्लॉकों के सरपंच, जनपद सदस्य और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंच से कांग्रेस नेताओं ने जिले के स्थानीय मुद्दों के साथ डबल मनी मामला, चावल प्रकरण, बस किराए में वृद्धि और बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले को लेकर जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गंभीर मामलों में प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है और रसूखदार लोगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है।

परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने मंच से डबल मनी मामले, हाल ही में बढ़ाए गए बस किराए और चावल प्रकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। चावल मामले को लेकर उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे पर सीधे सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि यदि जिले में ऐसे भाजपा जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाएगी तो इसका नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चावल प्रकरण में भाजपा जिला अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों के नाम सामने आने से भाजपा और सरकार की छवि धूमिल हुई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रही है। भगत ने सांसद भारती पारधी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे स्थानीय समस्याओं को लेकर धरातल पर सक्रिय होने के बजाय बड़े भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि सांसद को जिले के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरना चाहिए और सड़कों पर आकर समस्याओं की आवाज उठानी चाहिए।

देश का युवा बदलाव चाहता है - विक्की पटेल

वारासिवनी विधायक विक्की पटेल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से देश में माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने युवा वर्ग द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश का युवा अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रभावित गांवों में जाकर स्थिति देख चुके हैं। आज भी कई गांवों में शासन की योजनाएं पूरी तरह नहीं पहुंच रही हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने टीकाकरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी परेश उपलप की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। पटेल ने कहा कि चावल मामले में शुरुआत में एसआईटी ने कार्रवाई की, लेकिन बाद में पूरा मामला शांत हो गया। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून सभी के लिए समान है। यदि छोटे आरोपियों पर कार्रवाई की गई है तो बड़े और रसूखदार लोगों पर भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गरीबों का चावल हड़पने वालों को जेल भेजने की मांग की।

अनुभा मुंजारे ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने चावल प्रकरण को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चावल मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके परिजनों के नाम सामने आने के बावजूद वे शहर में बैनर, फ्लेक्स और होर्डिंग के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मुंजारे ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि चावल मामले में कुछ लोगों को एसआईटी ने जेल भेजा, जबकि रामकिशोर कावरे के भतीजे अविनाश कावरे के अस्पताल में भर्ती होने के मामले की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पुलिस अधीक्षक निष्पक्ष कार्रवाई की बात करते हैं तो चावल मामले में बड़े आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुंजारे ने आरोप लगाया कि छोटे आरोपियों के जुलूस निकाले जाते हैं, जबकि बड़े आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि रामकिशोर कावरे के भाई राजकुमार कावरे सहित अन्य बड़े आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी।

प्रभारी मंत्री के दौरे पर भी उठाए सवाल

अनुभा मुंजारे ने प्रभारी मंत्री उदयप्रताप सिंह के हालिया जिले के दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री आनन-फानन में जिले में आए और जिला चिकित्सालय पहुंचकर अधिकारियों से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, लेकिन प्रभावित गांवों में जाकर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकार को तत्काल मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए थी। मुंजारे ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने अपने ऊपर पूर्व में लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए भाजपा नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब उन पर आरोप लगाए गए थे, तब भाजपा के नेताओं ने उन्हें विधायक पद से हटाने तक की मांग की थी, लेकिन अब भाजपा से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों के नाम चावल तथा डबल मनी मामलों में सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मुंजारे ने गौरीशंकर बिसेन, मौसम बिसेन, रमेश भटेरे और रामकिशोर कावरे सहित अन्य भाजपा नेताओं को भी निशाने पर लिया। उन्होंने डबल मनी मामले में सामने आए नामों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा से भी ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

संजय उइके ने बिरसा में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरा

कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बैहर विधायक संजय उइके ने धरने के अंतिम उद्बोधन में बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पहले एक बच्चे की मौत हुई, फिर दूसरे और इसी तरह लगातार बच्चों की मौत होती रही। जब स्थानीय सरपंच ने मामले को उठाया और यह बात जिला प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारी-कर्मचारी एक-दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। किसी ने कुपोषण को कारण बताया तो किसी ने वैक्सीनेशन की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उइके ने कहा कि स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि प्रभावित क्षेत्रों में समय पर पानी, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने की मांग की।

अधिकारियों के तबादलों पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल

उइके ने आरोप लगाया कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के राजनीतिक प्रभाव के चलते तबादले करा दिए जाते हैं और उन्हें शहरी क्षेत्रों में पदस्थ कर दिया जाता है। उन्होंने प्रभारी मंत्री के कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और राजनीति करने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस राजनीति कर रही थी तो प्रभारी मंत्री को प्रभावित गांवों में जाकर वस्तुस्थिति देखनी चाहिए थी। उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि एक ही कर्मचारी को दो-दो पदों की जिम्मेदारी कैसे दी जा रही है और ऐसी व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग किस तरह प्रभावी ढंग से काम करेगा।

एसपी से पूछा- बड़े आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

धरने के दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की कार्यप्रणाली को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। संजय उइके ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से पूर्व में मुलाकात के दौरान कहा गया था कि जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निर्दोष को छोड़ा जाएगा। इसके बावजूद सवाल यह है कि बड़े मिल मालिकों, रसूखदार लोगों और भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उइके ने पुलिस अधीक्षक से सवाल किया कि आखिर ऐसे लोगों से उनका क्या संबंध है, जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने राजनांदगांव के एक व्यापारी का भी उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की कि यदि किसी कारण से कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसका कारण भी सार्वजनिक किया जाए।

न्यूज़ गैलरी

मोनू उर्फ निशांत सोनी की हत्या करने के आरोप में चार आरोपियों को उम्रकैद

नगर के बस स्टैंड स्थित शास्त्री पेट्रोल पंप में हुई थी वारदात

सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत का फैसला

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। नगर के बस स्टैंड स्थित शास्त्री पेट्रोल पंप के पास करीब दो वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या के मामले में विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वाले आरोपियों में राजेश पिता मादोलाल चामलाटे 40 वर्ष वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी बालाघाट, अंकित पिता किशनलाल चामलाटे 24 वर्ष ग्राम देवरी थाना हट्टा, तनवीर शेख पिता शेख रहीम 26 वर्ष वार्ड नंबर 14 बूढ़ी बालाघाट तथा कुलदीप उर्फ रजा पिता कुंजीलाल हरिनखेड़े 22 वर्ष वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट निवासी शामिल हैं।

पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर की थी मारपीट

अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2024 की रात करीब 11:30 बजे मोनू उर्फ निशांत सोनी अपने दोस्त विशाल परते के साथ बस स्टैंड स्थित शास्त्री पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने पहुंचा था। इसी दौरान मोनू पेट्रोल पंप के कार्यालय में चला गया इसी समय राजेश चामलाटे, तनवीर शेख, अंकित चामलाटे और कुलदीप हरिनखेड़े पेट्रोल पंप के कार्यालय में पहुंचे और मोनू के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान राजेश चामलाटे ने चाकू निकालकर मोनू के सीने और पेट में वार कर दिया। वारदात के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए।

इलाज के दौरान हुई थी मौत

चाकू के वार से मोनू सोनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे उसके दोस्त विशाल परते ने आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान मोनू मौत हो गई। यह वारदात आपसी पूर्व रंजिश के चलते घटित हुई थी घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 459/2024 दर्ज करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला कायम किया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने में पाई सफलता

मामले की सुनवाई विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफलता हासिल की।मामले की समस्त परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और विवेचना के निष्कर्षों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की।

छात्राओं की शिकायत पर छात्रावास की अव्यवस्थाओं की खुली पोल

गंदा पानी, बंद आरओ मशीन और महीनों से स्वास्थ्य परीक्षण नहीं, जनसुनवाई में पहुंची छात्राओं की शिकायत पर कलेक्टर ने कराई जांच, तीन दिन में सुधार के निर्देश

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। शहर के वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय संयुक्त आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं द्वारा 18 अगस्त को जनसुनवाई में छात्रावास की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया है। छात्राओं ने गंदे पानी, खानपान, छात्रावास कर्मचारियों के व्यवहार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। छात्राओं की शिकायत पर कलेक्टर बालाघाट ने तत्काल बालाघाट तहसीलदार छवि पंत को मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद तहसीलदार ने 18 अगस्त को ही छात्रावास पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों में कई बिंदुओं पर छात्रावास की व्यवस्थाओं में कमियां सामने आईं।

तहसीलदार छवि पंत ने पद्मेश न्यूज़ से दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि छात्रावास में निरीक्षण के दौरान करीब 12 से 13 पानी की टंकियां पाई गईं, जिनमें से दो टंकियां साफ नहीं मिलीं। छात्राओं द्वारा गंदे पानी को लेकर की गई शिकायत के संबंध में निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि बोरिंग मशीन के पास गंदा पानी जमा हो रहा था। पीने के पानी की आरओ मशीन बंद पायी गयी, इस स्थिति को देखते हुए नगर पालिका की टीम को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पानी के स्रोत के आसपास गंदगी और जलभराव की स्थिति समाप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि छात्रावास में सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायत भी सामने आई है। जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि बच्चों से सफाई किए जाने के नाम पर पांच-पांच रुपये की राशि ली जाती है। इस संबंध में भी प्रतिवेदन तैयार किया गया है। वहीं छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी गंभीर कमी सामने आई। तहसीलदार के अनुसार छात्रावास में छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण लंबे समय से नहीं किया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था नियमित रूप से किए जाने की आवश्यकता है, जिसे लेकर भी प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि छात्राओं की शिकायत के आधार पर छात्रावास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई हैं और संबंधित व्यवस्थाओं को तीन दिन के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तीन दिन की अवधि के बाद दोबारा छात्रावास का निरीक्षण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है या नहीं। छात्राओं द्वारा छात्रावास में भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार नहीं दिए जाने की शिकायत भी जनसुनवाई में की गई थी। इस संबंध में तहसीलदार ने छात्रावास प्रबंधन को निर्धारित मेनू के अनुसार ही भोजन तैयार कर छात्राओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दिन भोजन की व्यवस्था ठीक पाई गई, हालांकि छात्रावास प्रबंधन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि भविष्य में भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित मेनू का पालन सुनिश्चित किया जाए। तहसीलदार छवि पंत ने यह भी बताया कि छात्राओं द्वारा लगाए गए जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल से संबंधित आरोपों के संबंध में निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि छात्रावास में जातिसूचक व्यवहार से संबंधित कोई तथ्य जांच के दौरान नहीं मिला। हालांकि छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले को जांच प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। गंदे पानी की शिकायत के बाद प्रशासन ने पानी की गुणवत्ता की जांच की दिशा में भी कदम उठाया है। तहसीलदार के अनुसार छात्रावास में उपयोग किए जा रहे पानी के सैंपल लेकर पीएचई विभाग को भेजे गए हैं, जहां पानी की टेस्टिंग की जा रही है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पानी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। यदि पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि छात्राओं ने 18 अगस्त को जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन के सामने रखा था। छात्राओं का यह कदम इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर केवल शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी बात खुलकर प्रशासन के सामने रखी। देश के अलग-अलग हिस्सों में जेन अल्फा पीढ़ी के बच्चों द्वारा अपनी समस्याओं, मांगों और सुविधाओं को लेकर शासन-प्रशासन से सवाल किए जाने की तस्वीरें सामने आती रही हैं। इसी बदलते दौर की झलक बालाघाट में भी दिखाई दी, जहां आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में सीधे प्रशासन के सामने आवाज उठाई। अब प्रशासन की जांच के बाद छात्राओं द्वारा उठाए गए कई सवालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पानी की टंकियों की सफाई, बोरिंग के आसपास जमा गंदे पानी की समस्या, बंद आरओ पानी मशीन, स्वास्थ्य परीक्षण, सफाई के नाम पर राशि लिए जाने और भोजन की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने तीन दिन के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही है। ऐसे में अब अगली जांच में यह स्पष्ट होगा कि छात्रावास प्रबंधन ने इन निर्देशों का कितना पालन किया और छात्राओं की शिकायतों के बाद वास्तव में व्यवस्थाओं में कितना सुधार हुआ।

केश शिल्पी नाई समाज ने मनाया हरियाली महोत्सव, दिखाई प्रतिभा

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। जिला केश शिल्पी नाई समाज के तत्वाधान में महिला संगठन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन मास के अवसर पर 19 अगस्त को शहर मुख्यालय में हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर सावन झूला, सामूहिक नृत्य सहित विभिन्न प्रतियोगिता में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। महिलाओं ने सावन के गीतों में बेहतरीन नृत्य की प्रस्तुति दी। इस संबंध में महिला संगठन जिलाध्यक्ष दामिनी गोंडाने ने बताया कि महिलाओं को सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से एकजुट कर उन्हें प्रतिभा व कला कौशल दिखाने अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसी मंशा से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें समाज की महिलाओं ने शामिल होकर कार्यक्रमों में भाग लिया।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला केश शिल्पी नाई समाज महिला संगठन सचिव पूजा नागपुरकर, कोषाध्यक्ष सोनाली कुकडकर, प्रियंका नागपुरकर, उपाध्यक्ष सरस्वती झुझार, शिखा श्रीवास, मीडिया प्रभारी खुशी कुकडकर सहित सदस्य पूजा श्रीवास, दीपिका श्रीवास, सरिता अमरतकर, नेहा कुकडकर सहित अन्य मौजूद रहे।

ग्राम भीमा में युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। मलाजखंड थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम भीमा में इसी ग्राम के एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 18 अगस्त को 10:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह युवक अपने घर में अकेला था और परिवार के लोग खेत चले गए थे मलाजखंड पुलिस ने मृतक युवक तामेश पिता धरमलाल सोनेकर 23 वर्ष का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सोप दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तामेश सोनेकर अर्थ फोकस संस्था(एन जी ओ) में काम करता था।जिसके परिवार में माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है। परिवार के लोग खेती किसानी करते हैं। 18 अगस्त को सुबह तामेश सोनेकर घर में था।परिवार के लोग कृषि कार्य करने के लिए खेत चले गए थे। 10:30 बजे करीब तामेश का बड़ा पिता संतराम सोनेकर घर के बांधे चराने के लिए छोड़ने के लिए आया। तब उसने घर का दरवाजा खुला देखा। आवाज लगाने पर भी कोई नहीं बोल रहा था। घर के अंदर उसका भतीजा तामेश छप्पर में फांसी में लटका हुआ। तामेश ने पीले रंग की नायलॉन की रस्सी का फंदा बनाकर लकड़ी की म्याल बांध कर फांसी लगा दी थी और वह झटपटा रहा था। संतराम ने पासपड़ोस वालों को बुलाया और तामेश को नीचे उतारे और उसके पैरों को तेल लगाए किंतु कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसकर माता-पिता परिवार के अन्य लोग भी आ गए। संतराम सोनेकर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मलाजखंड पुलिस ने ग्राम भीमा पहुंचकर मृतक तामेश का शव अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कार्यवाही बाद पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। तामेश ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है किंतु किसी आर्थिक परेशानी की वजह से फांसी लगाने की संभावना व्यक्त की जा रही है ।मलाजखंड पुलिस धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर आगे जांच कर रही है।

खमरिया के पास क्षतिग्रस्त वॉटर कोस की पुलिया का निर्माण नही होने से किसानों में भारी आक्रोश

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

लालबर्रा से वारासिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम खमरिया के पास सर्राठी जलाशय के वॉटर कोस की पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त होकर बंद पड़ी है। पुलिया का निर्माण न होने से क्षेत्र की लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई बाधित हो गई है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि लंबे समय से खमरिया के किसानों के द्वारा कलेक्टर, एसडीएम, एमबीएल कंपनी के जिम्मेदारों को समस्या से अवगत करवाकर सडक के बीच से क्षतिग्रस्त वॉटर कोस पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया का निर्माण करवाने की मांग कर रहे है। ताकि सर्राठी जलाशय की माइनर नहर से निकले वॉटर कोस पुलिया से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। वहीं पुलिया बंद हो जाने से एक साइड में पानी जमा रहने से किसानों के खेतों में अत्यधिक पानी का जमाव से उनकी फसल खराब हो जाती है। तो वहीं दुसरे ओर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा खमरिया स्थित बैंक के साइड के किसानों के खेतों तक पानी नही पहुंच पाता है। वहीं जब बारिश नही होती है तो पानी के अभाव में सैकड़ों एकड़ खेती में लगी फसल प्रभावित हो जाती है जिससे किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही विगत दिवस किसानों ने जिला प्रशासन एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खमरिया के पास क्षतिग्रस्त वॉटर कोस की पुलिया का निर्माण करवाने की मांग की है एवं 24 अगस्त तक मांगे पूरी नही होने पर 25 अगस्त को लालबर्रा से वारासिवनी मार्ग खमरिया स्थित क्षतिग्रस्त वॉटर कोस पुलिया स्थल पर चक्काजाम एवं धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

खेतों तक पानी नही पहुंचने पर 100 एकड़ में लगी फसल होगी प्रभावित, जिम्मेदार मौन

आपकों बता दे कि लालबर्रा से वारासिवनी मार्ग स्थित खमरिया के समीप से सर्राठी जलाशय माइनर नहर गुजरी है और इस नहर के माध्यम से दर्जनों ग्रामों के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है। वहीं विगत वर्ष पुर्व एमबीएल कंपनी के द्वारा वारासिवनी से लालबर्रा पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया है। जिस समय ग्रामीणजनों एवं किसानों ने प्रशासन से खमरिया के समीप सड़क के बीच से गुजरे वॉटर कोस की पुलिया का नवीन निर्माण करवाने की मांग किये थे। लेकिन निर्माण कंपनी के द्वारा किसानों की मांगों को अनसुना कर तीव्र गति सड़क का निर्माण कर दिया गया है। इस तरह से सड़क निर्माण कर वॉटर कोस की पुलिया निर्माण करवाना भूल गया प्रशासन। वहीं पुराने पुलिया के ऊपर से ओवर लोड़ वाहनों के गुजरने के कारण वॉटर कोस की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में सर्राठी जलाशय की खमरिया माइनर नहर में पानी छोड़ने पर जिस वॉटर कोस से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए वह तक नही पहुंच पा रहा है और यह सब एमबीएल कंपनी के जिम्मेदारों एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण हो रहा है। जबकि एमबीएल कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के साथ ही वॉटर कोस पुलिया वाले स्थान पर नवीन पुलिया का निर्माण कर दिया जाता तो उक्त समस्या उत्पन्न नही होती। वहीं लंबे समय से खमरिया क्षेत्र के किसानों के द्वारा पूर्व में एम.बी.एल. कंपनी, परिवहन विभाग, कलेक्टर महोदय तथा क्षेत्रीय विधायक महोदया को भी लिखित रूप से अवगत करवा चुके है। इसके बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वहीं किसानों ने गत दिवस अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पुलिया निर्माण शुरू करवने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो समस्त किसान 25 अगस्त को प्रात: 11 बजे क्षतिग्रस्त स्थान पर उग्र चक्काजाम आंदोलन करेंगे। वहीं किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि चक्काजाम एवं धरना प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय स्थिति या अव्यवस्था निर्मित होती है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

पानी के अभाव में फसल हो जाती है प्रभावित - दिनेश

दिनेश चौहान ने बताया कि सर्राठी जलाशय माइनर नहर खमरिया से निकली वॉटर कोस की पुलिया के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है। लेकिन सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण के दौरान नवीन पुलिया का निर्माण नही किया गया। जिसके कारण वह क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में नहर का पानी खेतों तक नही पहुंचने से करीब डेढ़ एकड़ खेती में लगी फसल पानी के अभाव में प्रभावित हो जाती है। श्री चौहान ने बताया कि वॉटर कोस की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके है लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है, हमारी मांग है कि जल्द नवीन वॉटर कोस की पुलिया का निर्माण किये जाये ताकि किसानों के खेतों तक आसानी से नहर का पानी पहुंच सके।

मांगे पूरी नही होने पर 25 अगस्त को किया जायेगा आंदोलन - संतोष

किसान संतोष चौरे ने बताया कि लालबर्रा से वारासिवनी मार्ग खमरिया के समीप स्थित वॉटर कोस पुलिया क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बंद हो चुका है जिसके कारण नहर का पानी किसानों के खेतों तक नही पहुंच पाता है। जबकि जिस समय एमबीएल कंपनी के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा था, उस समय वॉटर कोस की पुलिया का निर्माण करवाने की मांग की गई थी। लेकिन उनके द्वारा नही किया गया और पुराने को ही यथावत रख दिया गया जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका है। श्री चौरे ने बताया कि वॉटर कोस की पुलिया क्षतिग्रस्त एवं बंद हो जाने से हो रही परेशानियों के संबंध में जिला प्रशासन, एमबीएल कंपनी के जिम्मेदारों एवं क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत करवा चुके है लेकिन समस्या का समाधन नही किया जा रहा है जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। गत दिवस एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 24 अगस्त का वॉटर कोस पुलिया का निर्माण करवाने की मांग की है, उक्त मांगे पूरी नही होने पर 25 अगस्त को किसानों के द्वारा चक्काजाम एवं धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

डोंगरगढ़ धाम के लिए घटोलगांव पदयात्रियों का जत्था हुआ रवाना

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से लगभग 7 किमी. दूर स्थित ग्राम पंचायत रमपुरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम घटोलगांव से डोंगरगढ़

(छत्तीसगढ़) स्थित प्रसिध्द माँ बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शनार्थ श्रध्दालुओं का जत्था मंगलवार को सुबह 11 बजे रवाना हुआ। पवन पुत्र सेवा समिति घटोलगांव के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा की शुरूआत ग्राम के स्थानीय मंदिर से हुई। रवानगी से पूर्व मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए सभी पदयात्रियों का श्रध्दालुओं द्वारा तिलक-वंदन कर स्वागत किया गया और उनकी मंगलमय एवं सफल यात्रा की कामना की गई। यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए पदयात्री संतलाल शेंडे ने बताया कि समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी युवाओं का यह दल माँ बम्लेश्वरी के दरबार के लिए रवाना हुआ है। पदयात्री लगभग 175 से 180 किमी. की दूरी ढाई दिनों में तय कर डोंगरगढ़ पहुंचेंगे। साथ ही यह भी बताया कि यात्रा का पहला मुख्य पड़ाव दरेकसा तय किया गया है। जिसके बाद डोंगरगढ़ पहुंचकर सभी श्रध्दालु विधि-विधान से माँ बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना एवं दर्शन करेंगे तथा क्षेत्र व जिले की सुख-समृध्दि एवं खुशहाली की कामना करेंगे। इस जत्थे में संजय नगपुरे, संतलाल शेन्डे, जीतू राणा, विशाल तिलकर, विजय सोलाखे, भवन, सुधीर, लक्ष्मी, वेद प्रकाश, रोहित, दलपत, अनिल, सुरेश, शांताबाई केवट, कीर्तन बाई सहित अन्य पदयात्री शामिल है।

उत्कृष्ट विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। 'नशा मुक्त भारत अभियान - विकसित भारत की ओर एक सशक्त कदम' के अंतर्गत प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र द्वारा गत 6 अगस्त से 20 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाने का एक बृहद महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बुधवार को नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में नशा मुक्ति अभियान पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रम्हाकुमारी उर्वशी दीदी, उज्जवला दीदी एवं एन. सोलंकी भाई के विशेष आतिथ्य, विद्यालय के प्राचार्य सनत दुबे की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थितजनों ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ब्रम्हाकुमारी सेवा केंद्र की दीदियों ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाने के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा केवल बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू-गुटखा का ही नहीं होता, बल्कि अत्यधिक मोबाइल चलाना, बेवजह घूमना और चाय का अत्यधिक सेवन करना भी एक प्रकार का व्यसन (नशा) ही है। दीदियों ने इन सभी प्रकार की आदतों से होने वाले शारीरिक, मानसिक और

सामाजिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए नशे से दुर रहने एवं अन्य लोगों को भी जागरूक करने प्रेरित किया।

सत्य के मार्ग पर चलने और बड़ों के सम्मान की मिली सीख

इस जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के अंत में सभी विद्यार्थियों को नशेली वस्तुओं व बुरी आदतों से दूर रहने तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलवाया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, जीवन में आगे बढ़ने, अपने से बड़ों का सम्मान करने और धार्मिक व नैतिक मूल्यों से जुड़कर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। ब्र.कु. उर्वशी दीदी ने बताया कि 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाने का एक बृहद महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक स्थानों तथा जिला जेल आदि में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं एवं विद्यार्थियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि नशा सही आदतों और उच्च विचारों का होना चाहिए जिसे अपनाकर अपने जीवन, चरित्र और संस्कारों को श्रेष्ठ एवं सुंदर बनाया जा सकता है। बुधवार को लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाकर नशेली वस्तुओं से दुर रहने एवं अन्य लोगों को भी जागरूक करने प्रेरित किया गया है। यदि नई पीढ़ी को सही ज्ञान और संस्कार दिये जाये तो भले ही 100 में से 100 लोग न बदलें, लेकिन यदि 5 लोग भी सही दिशा चुनते हैं, तो भारत को पुन: 'सोने की चिड़िया' बनाने का सपना साकार हो सकता है। इस अवसर पर ब्र.कु. दीदी, भाई, स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

महाविद्यालय में "नशामुक्त भारत अभियान" कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत नशा उन्मूलन गतिविधियों के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रम्हाकुमारी संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें स्वस्थ सकारात्मक एवं नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर ब्रम्हाकुमारी संस्थान द्वारा नाटक का प्रभावशाली मंचन किया गया और लघु नाटक के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा की प्रभारी प्राचार्य डॉ. संगीता मेश्राम ने कहा कि युवाओं को नशे जैसे समाजिक बुराई से बचाने के लिए निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आव्हान किया। मुख्य वक्ता के रूप में ब्रम्हाकुमारी संस्थान साधना भवन वारासिवनी की ब्र.कु. उर्वशी दीदी ने अपने प्रेरक व्याख्यान में कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके परिवार, शिक्षा करियर और सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकुल प्रभाव डालता है। आगे कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है और युवाओं को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यो, शिक्षा, खेल, योग एवं आध्यात्मिक साधना में लगाना चाहिए

क्योंकि ध्यान एवं सकारात्मक चिंतन आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाती है एवं इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति एवं नशे की लत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशा मुक्त जीवन अपनाने तथा समाज में जागरूकता फैलाने का आव्हान किया। ब्रम्हाकुमारी केन्द्र लालबर्रा की संचालिका उ'जवला दीदी ने कहा कि युवा स्वयं नशे से दूर रहकर और अपने साथियों को भी जागरूक करके नशामुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। ब्रम्हाकुमारी केन्द्र लामता से अलका दीदी ने अपने व्याख्यान में कहा कि नशे की प्रवृत्ति युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। हमारा दायित्व है कि हम विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. प्रदीपकुमार भिमटे ने कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशे से मनुष्य के व्यक्तित्व पर विपरित प्रभाव पड़ता है एवं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से जुझता है। अत: विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रहने के सलाह दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. कामाक्षा बिसेन एवं आभार प्रदर्शन डॉ. प्रदीपकुमार भिमटे के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्रम्हाकुमारी संस्थान लालबर्रा से नारायण सौलंकी, जगदीश भाई, श्रीमती सुषमा रहांगडाले एवं महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक सुमन बरवा, डॉ. सुरेन्द्रकुमार खण्डायत, डॉ. निर्मल कीर्ति गेडाम, नरेश सौलखे, श्रीमती संध्या भलावे, श्रीमती भूमेश्वरी ठाकरे, मनीष शिवहरे, डॉ. आशा कारे, श्रीमती अनिभा शरणागत, पीतम मुरते, यादोराव राजुरकर, श्रीमती सरिता एड़े, रामदयाल मथारे, लकेश गेडाम, श्रीमती वंदना कुर्वे, मिनेश पंचेश्वर, इकबाल खान सहित अन्य महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

किसान गर्जना संगठन किसानों की मांगों को लेकर सौंपेगें ज्ञापन आज

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। किसान गर्जना संगठन लालबर्रा अध्यक्ष रामचंद सिहोरे ने विज्ञप्ति जारी कर अपने वक्तव्य में बताया कि किसान गर्जना संगठन के द्वारा 20 अगस्त को किसानों की विभिन्न 'वंलत समस्या, भावांतर योजना एवं मांगों के संबंध में बालाघाट स्थित सर्किट हाउस में आवश्यक बैठक आहुत की गई है। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर सभी किसान रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेगें। श्री सिहोरे ने बताया कि किसान गर्जना संगठन की प्रमुख मांग है कि किसानों को उनकी उपज का उचित एवं सुनिश्चित मूल्य मिलना

चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिसमें किसान अपनी फसल बेचने के बाद भाव के अंतर के भरोसे रहे और बाजार में व्यापारी के सामने मजबूर हो। किसान को भावांतर नहीं, फसल का पूरा और लाभकारी दाम चाहिए। किसानों के हक और अधिकार के लिए किसान गर्जना संगठन मजबूती से आवाज उठाते रहेगा। इस अवसर पर क्षेत्रभर के किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारी एवं किसानों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील श्री सिहोरे ने की है।

खाद वितरण की नई प्रक्रिया से वारासिवनी खैरलांजी के किसान परेशान

किसानों ने शासन प्रशासन से पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की रोपाई पूरी हो चुकी है। वर्तमान में फसलों को बचाने और बेहतर पैदावार के लिए खाद उर्वरक के छिड़काव की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में शासन के द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सेवा सहकारी समितियों में सभी सहखातेदारों के शपथ पत्र, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता के कारण किसान खाद पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं।

टोकन सिस्टम बंद,नए नियमों ने बढ़ाया आक्रोश

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में टोकन सिस्टम के माध्यम से किसानों को सुगमता से खाद का वितरण किया जा रहा था। परंतु हाल ही में इस व्यवस्था को बंद कर समिति और मारफेट के माध्यम से ऑफ्लाइन बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के तहत यदि किसी किसान की भूमि पावती में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं तो उन सभी सदस्यों के शपथ पत्र, आधार कार्ड जमा करने और उनके बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद दी जा रही है। सोसाइटी के ऋण धारक किसानों के सामने सबसे बड़ी व्यावहारिक संकट खड़ी हो गई है। कई किसानों की पावती में दर्ज परिवार के सदस्य रोजगार या अन्य कारणों से बाहर निवास कर रहे हैं या परिवार की बेटियां विवाह उपरांत दूसरे स्थानों पर चली गई हैं। ऐसे में वर्तमान में उनका उपस्थित होना या दस्तावेज उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ परिवारों में आपसी मनमुटाव के कारण भी अन्य सदस्य दस्तावेज देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं जिससे वास्तव में खेती संभाल रहे किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। सोसायटी से केसीसी पर खाद बीज लेने वाले पंजीकृत किसान अब दोहरी मार झेल रहे हैं। फसल बचाने की जल्दबाजी में वे बाहर से कर्ज लेकर या अन्य तरीकों से रुपये की व्यवस्था कर मारफेट के गोदामों से नगदी में खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए किसानों को अन्य माध्यमों से ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। शासन की इस नई प्रक्रिया को लेकर क्षेत्र के किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस जटिल नियम में तत्काल ढील दी जाए और पूर्व की तरह केवल खेती का वास्तविक संचालन कर रहे खाताधारक के नाम पर ही खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था पुनःशुरू की जाए।

किसानों का कोई माईबाप नही है-जितेंद्र खांडेलकर

किसान जितेंद्र कुमार खंडेलकर ने बताया कि खेती में जितने लोगों के नाम है सभी की सहमति चाहिए यह सोसायटी में बोला जा रहा है। जिसका रिकॉर्ड ठीक है वह खाद ले रहा है जिसमें ज्यादा नाम है वह परेशान है यही कारण है कि हम लोग यहां पर आ रहे हैं। पिता के बाद जो वारसान थे तो उनके नाम पावती में चढ़ गए हैं भाइ बहन बाहर रहते हैं उनकी सहमति शपथ पत्र में लाने बोल रहे हैं जिसकी हमें परेशानी है की चार व्यक्ति जमा कब होंगे और यह होगा परंतु उसके लिए समय है। हम नारवांजपार रहते हैं १५ किलोमीटर से यहां आये हैं बारिश का मौसम है नगदी में भी खाद की व्यवस्था समिति में करना था। हम अपनी शाखा छोड़कर इतनी दूर आ रहे हैं हम चाहते हैं कि एक नाम से खाता संचालित हो ताकि किसान को समस्या ना हो।

सरकार के नये नये नियमों से किसाना परेशान है-शिवशंकर ठाकरे

शिवशंकर ठाकरे ने बताया कि हमारी जो एक पावती है वह शामिल शरीक की है हमारे यहां एक व्यक्ति हैदराबाद तो दूसरा नागपुर और हम दो व्यक्ति वारासिवनी में रहते हैं। अब हम कैसा करें यह समझ नहीं आ रहा है सहमति तक सोसायटी में खाद नहीं मिलेगा जबकि वहां से हमें उधारी मिलती है हमारा खाता है। ऐसे में हम नगदी खाद लेने के लिए कर्ज लेकर यहां आ रहे हैं शासन को इसका निराकरण करना चाहिए जो व्यक्ति बायोमेट्रिक करके खाद ले जा रहा है उससे वसूली करनी चाहिए और वह व्यक्ति जब पूरी खेती कर रहा है तो उसी आधार पर उसे कर्ज भी समिति ने दिया है।

पहले परमिट पर खाद मिलती थी जो किसानों के लिये अच्छा था-नरेंद्र बिसेन

नरेंद्र बिसेन ने बताया कि पहले परमिट पर खाद मिलती थी जो खाते का संचालन करता था उसे सब दिया जाता था। अभी पिता की मृत्यु के बाद चार नाम चढ़ गए हैं यह शपथ पत्र बनाकर लाने बोल रहे हैं इसमें लिखाई पढ़ाई और आर्थिक भार हम पर पढ़ना है। भाई बहन हमारे दूर है बहुत ज्यादा दिक्कत है यह स्थिति अभी ऑफलाइन हुआ है तब से है इसके पहले टोकन दे रहे थे वह भी बंद कर दिए हैं। पहले ही किसान खेती लगाने में लेट हो गया अब खाद के लिए लेट हो रहा है फसल पर नुकसान तो होगा इसी समस्या के निराकरण के लिए हम नकद में खाद ले जा रहे हैं।

टोकन सिस्टम में संबंधित व्यक्ति के नाम का ही खाद आवंटित हो रहा है-रविन्द्र पारधी

रविन्द्र पारधी ने दूरभाष पर बताया को शासन ने परिवार के समस्त सदस्यों की फार्मर आईडी बना दी है। शासन के निर्देश है कि खेती के लिए जो खाद दिया जा रहा है उसके लिए सभी सदस्य सहमत है या नहीं इसलिए शपथ पत्र और आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं,ताकि अन्य सदस्यों के हिस्से का खाद भी उसे दिया जा सके। टोकन सिस्टम में संबंधित व्यक्ति के नाम का ही खाद आवंटित हो रहा है यह शपथ पत्र वाली प्रक्रिया ऑफलाइन के लिए है ऑनलाइन में सभी सदस्यों को टोकन काटना पड़ेगा। शासन के नियम तहत जानकारियां समिति के सदस्यों को दी जा रही है पहले इसमें खाता मर्ज हो जाते थे उसे अब बंद कर दिया गया है जिस कारण यह स्थिति बनी है। खातेदार असुविधा से बचने दस्तावेज जमा करें।

नहर बंद होने से किसान परेशान, फ़सल अब बारिश पर निर्भर

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी के ग्रामीण अंचलों में राजीव सागर परियोजना की नहरों में अब तक पानी नही छोड़े जाने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। खरीफ सीजन का आगाज होने के बावजूद जल संसाधन विभाग की ओर से नहर में जल प्रवाह शुरू नहीं किया गया है। सिंचाई का कोई वैकल्पिक साधन नही होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के किसान पूरी तरह से प्राकृतिक बारिश के भरोसे खेती करने पर मजबूर हैं। वर्तमान में क्षेत्र में बारिश की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। रुक.रुक कर हो रही छिटपुट वर्षा के कारण खेतों में पर्याप्त नमी और पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। पानी के अभाव में खेतों की जुताई, रोपा और बोवनी जैसे महत्वपूर्ण कृषि कार्य पिछड़ गये हैं। जिन किसानों ने बारिश की उम्मीद में रोपा लगा दिया था अब वे बारिश पर आश्रित हैं। क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए राजीव सागर परियोजना की नहरें संजीवनी का काम करती हैं। यह नहर प्रणाली सीताकसा बांध से जुड़ी हुई है जहाँ से प्रतिवर्ष सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति की जाती है। इस वर्ष खरीफ सीजन के मुख्य चरण में पहुँचने के बाद भी विभाग के द्वारा सीताकसा से पानी नही छोड़े जाने से सीताकसा बांध से जुड़े गांवों में पानी की महती आवश्यकता बनी हुई है। पानी नही मिलने से किसान बीते वर्षों के अनुभवों को याद कर भारी मानसिक तनाव में हैं। किसानों को डर सता रहा है कि यदि विभाग ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो इस वर्ष भी उन्हें खरीफ की फसल में सिंचाई का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाएगा। क्षेत्र के कृषकों ने जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशासन से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजीव सागर नहर में तुरंत पानी छोड़े जाने की मांग की है।

नहर का पानी नही मिलने से किसानों को हो रही परेशानी-दुष्यंत जैतवार

किसान दुष्यंत जैतवार ने बताया कि नहर की स्थिति बहुत गंभीर है पानी हमें अभी तक नहीं मिला है। २ दिन के लिए बीच में नहर छोड़ा गया था परंतु उसके बाद फिर बंद कर दिया गया है। अभी हमारे खेतों की सिंचाई ऊपर के पानी से हो रही है या ज्यादा समस्या होने पर आसपास ट्यूबवेल वालों से अपनी मांग कर सिंचाई कर रहे हैं। बारिश के भरोसे हम बैठे हुए हैं यदि नहर नहीं छोड़े तो पूरा नुकसान है यदि फसलों को समय पर उचित पानी नहीं मिलेगा तो नुकसान होना निश्चित है।

नहर का पानी विभाग ने अभी तक चालू नहीं किया है-विजय रहांगडाले

किसान विजय रहाँगडाले ने बताया कि राजीव सागर नहर में आज तक पानी आया ही नहीं है और विभाग के द्वारा चालू भी नहीं किया गया है। अब भविष्य में देखना होगा कि यह पानी छोड़ते हैं या नहीं परंतु नहर चालू करना चाहिए। इस नहर के माध्यम से करीब ५० गांव आसपास के सिंचाई करते हैं यदि वहां पानी नहीं मिलेगा तो हर किसी को दिक्कत होगी। बीच में अधिकारियों को भी हमने बोले थे तो उन्होंने कहा था कि पानी देंगे पर अभी चालू नहीं किया है। शायद जरूरी समय पर शिकायत का ही सहारा किसानों को लेना पड़ेगा।

किसानों की उम्मीद है कि नहर का पानी खेतो में मिले- उम्मेद भलावी

किसान उम्मेद भलावी ने बताया कि नहर में पानी नहीं देने के कारण किसान पीछे हो गया है। क्योंकि हर कोई नहर का पानी नही मिलने से बारिश के पानी का इंतजार कर रहा था और वह आने के बाद लोगों ने अपने खेत में रोपाई सहित आवश्यक कार्य कर दिए हैं। यही कारण है कि किसान अब लेट चल रहा है बारिश भी रुक.रुक कर हो रही है आज बारिश हुई है तो कल का निश्चित नहीं है। हम नहर में पानी का रास्ता देख रहे हैं यही चाहते हैं की नहर से पानी मिल जाए और सभी किसानों का भला हो।

श्रद्धा बिसेन का राहुल प्रियंका गांधी विचार मंच जिलाध्यक्ष जावेद अली ने किया सम्मान

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नीट यूजी २०२६ परीक्षा में ऑल इंडिया ओबीसी श्रेणी में २४००० वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करने वाली होनहार बिटिया कु.श्रद्धा बिसेन का उनके निवास स्थान पर गरिमामय वातावरण में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस राहुल प्रियंका गांधी विचार मंच के जिलाध्यक्ष जावेद अली ने साथी अतुल पारधी के साथ अधिवक्ता आनंद बिसेन के निवास पहुँचकर श्रद्धा बिसेन को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान के दौरान जिलाध्यक्ष जावेद अली ने बिटिया श्रद्धा के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि २० लाख अभ्यर्थियों की कठिन परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलता का परचम लहराना बिटिया के अटुट परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। क्षेत्र की ऐसी होनहार बेटियों का सम्मान करना पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। श्रद्धा की यह सफ़लता अन्य छात्र छात्राओं को भी अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देगी। श्रद्धा के पिता अधिवक्ता आनंद बिसेन एवं उनकी माताजी को बधाई देते हुए कहा कि माता.पिता के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से ही बच्चे इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। वहीं ईश्वर से प्रार्थना की कि श्रद्धा मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूर्ण कर एक सफल एवं संवेदनशील चिकित्सक बनें और जीवन के हर मोड़ पर मानवता की सेवा करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करें।

प्रदेश के 55 में से 41 जिले बारिश में पिछड़े

भोपाल । इस साल मानसून मध्यप्रदेश से रुठा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 55 में से 41 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। सिर्फ 13 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जबकि एक जिले में बारिश सामान्य रही। प्रदेश में कुल बारिश सामान्य से 12 प्रतिशत कम है। पूर्वी मध्यप्रदेश में कमी 16 प्रतिशत और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 9 प्रतिशत है। भोपाल मौसम केंद्र द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार बारिश की कमी के मामले में मैहर सबसे पीछे है। यहां सामान्य से 58 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इसके बाद इंदौर संभाग के आलीराजपुर में 47 प्रतिशत, रीवा में 46 प्रतिशत, मुरैना में 38 प्रतिशत, नर्मदापुरम में 34 प्रतिशत, पांढुर्णा में 33 प्रतिशत और टीकमगढ़ में 31 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है। सागर और धार में 29 प्रतिशत, जबकि जबलपुर में सामान्य से 28 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इंदौर भी बारिश की कमी वाले जिलों में शामिल है। जिले में सामान्य से 13 प्रतिशत कम बारिश हुई है। सामान्य से कम बारिश वाले जिलों की सूची में इंदौर 27वें नंबर पर है। प्रदेश के 55 में से सिर्फ 13 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इनमें इंदौर संभाग का ही बुरहानपुर सबसे आगे है, जहां सामान्य से 39 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। वहीं खरगोन में 26 प्रतिशत, राजगढ़ में 24 प्रतिशत, भिंड और भोपाल में 18 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज हुई। गुना में 14 प्रतिशत और सिंगरौली में 12 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है।

सामान्य से सबसे कम बारिश वाले 5 जिले

1 मैहर 10.9 इंच 58 प्रतिशत कम

2 आलीराजपुर 12.6 इंच 47 प्रतिशत कम

3 रीवा 14.2 इंच 46 प्रतिशत कम

4 मुरैना 11.0 इंच 38 प्रतिशत कम

5 नर्मदापुरम 22.3 इंच 34 प्रतिशत कम

सामान्य से सबसे ज्यादा बारिश वाले 5 जिले

क्रम जिला बारिश अधिक

1 बुरहानपुर 27.1 इंच 39 प्रतिशत ज्यादा

2 खरगोन 24.3 इंच 26 प्रतिशत ज्यादा

रामदेव बाबा मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ जारी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर के लालबर्रा रोड़ स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा रामदेव बाबा मंदिर में श्रावण मास के पावन अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। सद्गुरु श्री श्री १०८ हरिओम ब्रह्मचारी महाराज के सूक्ष्म संरक्षण में श्रावण महोत्सव के तहत संगीतमय श्री सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन अपनी निरंतरता का अखंड १२वां वर्ष पूर्ण कर रहा है,जिसमें प्रतिदिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्मलाभ उठा रहे हैं। यह धार्मिक आयोजन श्रावण मास के प्रारंभ ३० जुलाई से शुरू होकर मास के समापन यानी २७ अगस्त २०२६ तक निरंतर जारी रहेगा। रोजाना सायंकाल मंदिर परिसर में भक्ति का अनुपम वातावरण निर्मित हो रहा है। जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित होकर प्रतिदिन निर्धारित समय शाम ७.१५ बजे से रात्रि ९.३० बजे तक आयोजित होने वाले इस पाठ में संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। श्रद्धालु रामभक्ति में लीन होकर सुंदरकांड की चौपाइयों का गान कर रहे हैं। रामदेव बाबा मंदिर समिति एवं भक्तगणों ने समस्त श्रद्धालुओं से अपने परिवार एवं इष्ट.मित्रों सहित पधारकर संगीतमय श्री सुंदरकांड पाठ में सहभागिता करने अपील की हैं।

सेलोटपार में तालाब की शिकायत को लेकर दो पक्ष आमने-सामने

वार्ड पंच ने सरपंच पति पर लगाए मारपीट के आरोप : दूसरे पक्ष ने दो ग्रामीणों पर हमला करने की शिकायत की

पद्मेश न्यूज।बालाघाट।रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सेलोटपार में तालाब एवं पुलिया निर्माण से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जांच के दौरान विवाद का मामला सामने आया हैं। 18 अगस्त 2026 को पंचायत में शिकायत की जांच के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद, गाली-गलौज और मारपीट के आरोप लगाए गए। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

वार्ड पंच ने सरपंच पति पर लगाए आरोप...

पहला मामला ग्राम सेलोटपार निवासी एवं वर्तमान वार्ड पंच मंशाराम दादरे ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने गांव के तालाब में कथित गड़बड़ी को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। इसी शिकायत की जांच के लिए 18 अगस्त को दोपहर करीब 3.30 बजे अधिकारी गांव पहुंचे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच के दौरान सरपंच पति राही पाण्डे ने उससे शिकायत करने को लेकर नाराजगी जताई और कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। मंशाराम का आरोप है कि उसने गाली देने से मना किया तो राही पाण्डे ने हाथ-थप्पड़ से उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान मोतीराम ठाकरे ने बीच-बचाव किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मारपीट के बाद राही पाण्डे ने दोबारा कहीं शिकायत करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। मारपीट के कारण गाल में दर्द होने की बात मंशाराम ने अपनी शिकायत में कही है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में शैलेष दांदरे का नाम भी पुलिस को बताया गया है। वार्ड पंच मंशाराम दादरे की शिकायत पर सरपंच पति राही पांडे के विरूद्ध पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया हैं।

सरपंच पति ने दो ग्रामीणों पर लगाया हमला करने का आरोप

दूसरा मामला इस विवाद में दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सरपंच पति की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार 18 अगस्त को ग्राम पंचायत सेलोटपार में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की सुनवाई एवं जांच के लिए अतिरिक्त समन्वय अधिकारी मुकेश खाण्डेकर पहुंचे थे। इस दौरान सरपंच, उपसरपंच, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित शिकायतकर्ता मंशाराम दादरे और मोतीराम ठाकरे मौजूद थे। शिकायत में बताया गया है कि मजदूरी भुगतान, तालाब एवं पुलिया निर्माण से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। सचिव द्वारा मस्टर रोल, मेजरमेंट बुक सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। सरपंच पति राही पांडे का आरोप हैं कि दस्तावेज देखने के दौरान मंशाराम दादरे द्वारा सरपंच और सचिव से गाली-गलौज की गई। इसी दौरान स्थिति बिगड़ने पर जांच अधिकारी मौके से चले गए। इसके बाद सरपंच पति ने अपनी पत्नी को गाली देने का विरोध किया तो कथित तौर पर मंशाराम दादरे और मोतीराम ठाकरे ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मारपीट में उसके बाएं और दाएं कंधे में अंदरूनी चोट आई है तथा दर्द हो रहा है। आरोप है कि दोनों ग्रामीण वहां से जाते समय यह धमकी भी देकर गए कि यदि उनके बीच में बोलोगे तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के दौरान पंचायत सचिव महेश हेडाऊ, उपसरपंच कमला भलावी और पंच मुन्नालाल रिनायत के मौजूद होने तथा बीच-बचाव करने की बात शिकायत में कही गई है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ दूसरा मामला

पुलिस ने राही पांडे की शिकायत पर मंशा राम दादरे व मोती राम ठाकरे के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296(बी), 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया हैं। पुलिस अब दोनों पक्षों के बयान, मौके पर मौजूद लोगों के कथन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पंचायत की शिकायत से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद गांव के तालाब एवं पुलिया निर्माण से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जांच के दौरान सामने आया। शिकायत की जांच के लिए अधिकारी पंचायत पहुंचे थे, जहां पंचायत के दस्तावेज और निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई।

फिलहाल, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों को अलग-अलग दर्ज कर लिया है। दोनों मामलों में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक स्थिति और घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही, यह स्पष्ट हो सकेगा।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ता भारत

पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो अर्थात् अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाता है। आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात से ही पूरा हो रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया। देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अब बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है। भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी।

राष्ट्र-प्रगति के लिए जागे युवा, भविष्य की पीढ़ियों का भी रखें ध्यान

युवा शक्ति ही राष्ट्र के वर्तमान को दिशा और भविष्य को आकार दे सकती है

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। जिस देश में युवाओं की संख्या अधिक हो, वहां विकास की संभावनाएं भी व्यापक होती हैं। लेकिन युवा शक्ति तभी राष्ट्र की ताकत बनती है, जब उसमें विवेक, संस्कार, पुरुषार्थ, कर्तव्यबोध और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में 'हमारा तिरंगा हमारी शान' कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए इसी जिम्मेदारी की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज के युवा तीस साल बाद बुजुर्ग होंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने वर्तमान के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका यह विचार युवाओं को तत्काल लाभ से आगे बढ़कर दूरगामी दृष्टि अपनाने का संदेश देता है।

भागवत ने युवाओं को देश का 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' बताते हुए कहा कि यदि युवा शक्ति को सही दिशा मिले तो देश को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन यदि यह शक्ति दिशाहीन हो गई तो भविष्य में यही समाज के लिए बोझ बन सकती है। रोजगार का अर्थ केवल दफ्तर की नौकरी नहीं है। मेहनत और श्रम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और उसके श्रम का सम्मान होना चाहिए। युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार तलाशने के साथ-साथ नए अवसर पैदा करने और कारोबार तथा उद्यमिता की ओर भी बढ़ना चाहिए।

भारत की परिस्थितियां दुनिया के दूसरे देशों से अलग हैं। भागवत ने इसी बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अमेरिका, चीन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की नकल करके अपनी विकास नीति तय नहीं करनी चाहिए। भारत की अपनी जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक संरचना, संस्कृति और आवश्यकताएं हैं। इसलिए विकास का भारतीय मॉडल भी हमारी परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। भारत के लिए केवल अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग ही प्रगति का अंतिम मानक नहीं हो सकता। हमारी सोच में मनुष्य, समाज, प्रकृति, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों का हित भी शामिल होना चाहिए।

युवा अवस्था जीवन का वह काल है जिसमें मनुष्य केवल अपने भविष्य का निर्माण नहीं करता, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी प्रभावित करता है। बचपन सीखने का समय है, वृद्धावस्था अनुभव बांटने का समय है, लेकिन युवावस्था सर्जन की अवस्था है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने सपनों को कर्म में बदल सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि दयानन्द सरस्वती और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपनी युवा ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देकर समाज को नई राह दिखाई।

गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरक है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से अशोक वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर लाने को कहा। आनन्द ने पत्ता तोड़कर उन्हें दे दिया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अब इस पत्ते को उसी डाल पर फिर से लगा दो। आनन्द ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब बुद्ध ने समझाया कि तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना कठिन है। यही शिक्षा आज राष्ट्र और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी परिवार को तोड़ना आसान है, समाज में विभाजन पैदा करना आसान है और अविश्वास की दीवार खड़ी करना भी आसान है, लेकिन टूटे संबंधों को जोड़ना अत्यंत कठिन होता है।

आज आवश्यकता इसी जोड़ने वाली शक्ति को मजबूत करने की है। जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्र की एकता सर्वोपरि रहनी चाहिए। भारत ने विभाजन का दर्द देखा है। इसलिए युवाओं को इतिहास से सीख लेकर ऐसी हर प्रवृत्ति से सावधान रहना चाहिए जो समाज में दूरी और अविश्वास बढ़ाती है। राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों के आपसी विश्वास और सहयोग से बनती है।

युवक शब्द को यदि भावार्थ की दृष्टि से देखें तो इसमें युग निर्माण, वचन और कर्तव्य का संदेश दिखाई देता है। युवक का पहला दायित्व है कि वह अपने समय को समझे और युग निर्माण में योगदान दे। उसकी वाणी में सत्य, संयम और सकारात्मकता होनी चाहिए। शब्दों में समाज को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। महात्मा गांधी का जीवन भी यही सिखाता है कि केवल बोलने से परिवर्तन नहीं आता, उसके लिए कर्म आवश्यक है। युवा जितना अधिक बोलने के बजाय अपने कार्य से उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उतना ही उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा।

युवाओं का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्तव्यबोध। अधिकारों की चर्चा सहज होती है, लेकिन कर्तव्यों का पालन कठिन होता है। राष्ट्र केवल सरकार से नहीं बनता। राष्ट्र उसके करोड़ों नागरिकों के छोटे-छोटे कर्तव्यों से बनता है। विद्यार्थी ईमानदारी से अध्ययन करे, श्रमिक निष्ठा से श्रम करे, व्यापारी अपने व्यवहार में विश्वास बनाए रखे, कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन करे और युवा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बने, तो यही राष्ट्र निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया है।

वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। तकनीक, सोशल मीडिया, त्वरित सफलता और उपभोग की संस्कृति ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ एकाग्रता, धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा भी बढ़ी है। युवाओं को यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल अधिक धन कमाना या अधिक सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है। सफलता का वास्तविक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने ज्ञान, समय और क्षमता का उपयोग समाज के हित में करे।

मोहन भागवत ने युवाओं को भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचने की बात कहकर इसी व्यापक दृष्टि की ओर संकेत किया है। यदि आज का युवा केवल अपने सुख-सुविधाओं के बारे में सोचेगा तो आने वाली पीढ़ियों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण, जल बचाना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर और सामाजिक सद्भाव ऐसे विषय हैं जिन पर आज के युवाओं को गंभीरता से विचार करना होगा। आज लिए गए निर्णयों का प्रभाव आने वाले दशकों तक रहेगा।

युवाओं को दिग्भ्रमित होने से भी बचना होगा। विरोध और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन हिंसा, अराजकता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युवा ऊर्जा को रचनात्मक आंदोलन, नवाचार, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, उद्यमिता, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाना अधिक उपयोगी है। समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं की प्रतिभा को अवसर मिले, उनकी बात सुनी जाए और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सकारात्मक भागीदारी का स्थान दिया जाए।

विनोबा भावे से जुड़ा एक प्रसंग भी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। कागज के टुकड़ों से भारत का मानचित्र जोड़ने का प्रयास कई युवक कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। एक युवक ने कागज के पीछे बने मानव के चित्र को देखा और पहले मनुष्य के अंगों को जोड़ दिया। उसके साथ ही भारत का मानचित्र भी सही बन गया। संदेश स्पष्ट था कि राष्ट्र को जोड़ना है तो पहले मनुष्य को जोड़ना होगा। समाज में प्रेम, सम्मान और सद्भाव बढ़ेगा तो राष्ट्र स्वतः मजबूत होगा।

आज के युवा को अपने भीतर पुरुषार्थ और स्वाभिमान जगाना होगा। धन कमाना बुरा नहीं है, सफलता प्राप्त करना भी गलत नहीं है, लेकिन सफलता का उपयोग केवल निजी सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के हित के लिए भी होना चाहिए। युवा उद्यमी बने, वैज्ञानिक बने, शिक्षक बने, सैनिक बने, किसान बने, कलाकार बने या किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन अपने कार्य में ईमानदारी और उत्कृष्टता को स्थान दे।

राष्ट्र निर्माण किसी एक व्यक्ति या संस्था का कार्य नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवा इस जिम्मेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि उनमें चरित्र, अनुशासन, संवेदना, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति का समन्वय हो जाए तो भारत की विकास यात्रा को नई गति मिल सकती है। आने वाला भारत कैसा होगा, इसका उत्तर आज के युवा के आचरण में छिपा है।

युवाओं को यह संकल्प लेना होगा कि वे केवल अपने लिए नहीं, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन जिएंगे। वे जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं; सृजन करेंगे, विनाश नहीं; संवाद बढ़ाएंगे, वैमनस्य नहीं; कर्तव्य निभाएंगे, केवल अधिकार नहीं मांगेंगे। यही युवा जागृति राष्ट्र-प्रगति का आधार बनेगी। आज का युवा यदि संस्कार, ज्ञान और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ता है तो वह केवल अपना भविष्य नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपना देश कह सकेंगी।

-कांतिलाल मांडोत

धर्मस्थलों पर अव्यवस्था-संकट में श्रद्धालुओं की जान

-मनोज कुमार अग्रवाल

सावन का तीसरे सोमवार 17 अगस्त 2026 श्रद्धालुओं के जीवन पर भारी पड़ गया। इस दिन विभिन्न राज्यों में धार्मिक स्थलों पर हुई भगदड़ और हादसों में कुल 27 लोगों की मौत हो गई। बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि कई अन्य हादसों में कम से कम बीस जान गयीं हैं जबकि हताहतों की तादाद सैकड़ों की संख्या में है। घायल हुए। दरअसल यह हादसों की पहली बार नहीं है हिन्दू धर्म स्थानों पर कुप्रबन्ध अव्यवस्था रखरखाव में गड़बड़ी संकीर्ण गलियारे और श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद असंयमित व्यवहार के साथ ही अफवाहों की साजिशें हर पर्व त्योहार दर्शन स्नान मेलों में हादसों की श्रृंखला बना रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के अशोकधाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के दौरान बिजली का खंभा गिरने और अफवाह फैलने से मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत और 19 से अधिक घायल हुए। वहीं मध्य-प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित चार राज्यों में विभिन्न हादसों और भीड़ के दबाव के कारण कुल 27 लोगों की जान चली गई।अभी दो माह पहले ही महाराष्ट्र के परभणी जिले की मानवत तहसील स्थित यशवाड़ी मारुति मंदिर में शनिवार को हुआ दर्दनाक हादसा पूरे देश को झकझोर दिया । मंदिर परिसर के सामने बना सभा मंडप अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके कारण कई श्रद्धालु मलबे में दब गए छह लोगों की मौत हो गई थी। आपको याद होगा कि महाकुंभ मेला, प्रयागराज जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम में पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए थे। अखाड़ा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के अत्यधिक दबाव से अचानक बैरिकेड्स ढह गए। इस दर्दनाक हादसे में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए।इसी तरह तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश में जनवरी 2025 वैकुंठ एकादशी त्योहार के दौरान वीआईपी और सामान्य दर्शन टिकट लेने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हुई। इस भीड़ के अनियंत्रित होने से मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं हाथरस सत्संग, उत्तर प्रदेश 2 जुलाई 2024 को एक धार्मिक आयोजन में बरती गयी लापरवाही सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान ले गयी। यह हाल के वर्षों की सबसे भीषण घटनाओं में से एक है। क्षमता से तीन गुना अधिक यानी करीब 2.5 लाख लोग एक अस्थायी टेंट में जमा हो गए थे। बाबा के जाने के बाद धूल छूने की होड़ और अत्यधिक गर्मी व उमस के कारण मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। पिछले दिनों यूपी के वृन्दावन में इस्कॉन मंदिर के गेट पर नगर निगम द्वारा लगाए गए शॉवर कूलर में अचानक करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से एक 21 वर्षीय श्रद्धालु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़, कुप्रबंधन, और उचित कतारें न होने के कारण अक्सर भगदड़ और विवाद जैसी स्थितियां सामने आती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के समीप एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है। मंदिर के गेट नंबर 5 के पास स्थित एक गली में अचानक एक पुराने मकान का छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। भारत आस्था और श्रद्धा का देश है। यहां प्रतिदिन लाखों लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में इन स्थानों की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों पर भगदड़, दीवार गिरने, छत ढहने करेंट उतरने और अन्य दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले में भी मंदिर परिसर से जुड़ी एक दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि समस्या किसी एक स्थान या एक राज्य तक सीमित नहीं है।

भारत के चुनावी मॉडल का अमेरिका में बजा डंका!

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनावी व्यवस्था को लेकर देश के भीतर भले ही चुनाव-दर-चुनाव राजनीतिक बहस,आरोप-प्रत्यारोप और चुनाव आयोग कीकार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हों,लेकिन 18 अगस्त 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली और विशेष रूप से मतदाता पहचान व्यवस्था की सार्वजनिक प्रशंसा ने एक बिल्कुल अलग अंतरराष्ट्रीय तस्वीर सामने रख दी है।उन्होंने 2024 के भारतीय लोकसभा चुनाव में लगभग 64.6 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी का उदाहरण देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए अमेरिका में चुनाव सुधारों के लिए सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट यानी सेव एक्ट को आगे बढ़ाने की अपील की। ट्रंप ने भारत के विशाल चुनावी पैमाने का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब भारत इतनी बड़ी आबादी और करोड़ों मतदाताओं के साथ पहचान-आधारित चुनाव करा सकता है, तो अमेरिका में मतदाता पहचान को लेकर अधिक सख्त और एकसमान व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि भारत की चुनावी विशालता अमेरिका के लिए मिसाल बन गई है,भारत का चुनाव मॉडल इसलिए असाधारण है क्योंकि यहां चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विशाल भौगोलिक, भाषाई,सामाजिक और जनसंख्या विविधता के बीच संवैधानिक लोकतंत्र को संचालित करने का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सात चरणों में मतदान कराया गया था। साथियों, निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए ईपीआईसी यानी वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड,आधार सहित कई निर्धारित फोटो पहचान दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। यानी भारत में मूल सिद्धांत यह है कि मतदाता की पहचान मतदान केंद्र पर सत्यापित होनी चाहिए, हालांकि यह समझना जरूरी है कि केवल वोटर आईडी ही एकमात्र स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है।यही वह बिंदु है जिसने अमेरिकी राजनीतिक बहस को भारत की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है। ट्रंप ने 18 अगस्त की सुबह अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया था कि अमेरिका वैध फोटो पहचान के बिना चुनाव कैसे कराता है। ट्रंप ने भारत के पिछले आम चुनाव का उल्लेख करते हुए लगभग 64.6 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा सामने रखा और कहा कि एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया तथा प्रत्येक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज था। इसी तुलना को आधार बनाकर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से सेव एक्ट पारित करने की मांग की। साथियों बात अगर हम भारत और अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसको समझने की करें तो, भारत और अमेरिका दोनों विश्व के महत्वपूर्ण लोकतंत्र हैं, लेकिन उनकी चुनावी संरचना एक जैसी नहीं हैभारत में चुनावों के संचालन के लिए एक केंद्रीयसंवैधानिक संस्था,निर्वाचन आयोग,की प्रमुख भूमिका है, जबकि अमेरिका में चुनावों का प्रशासन काफी हद तक राज्यों और स्थानीय चुनावी संस्थाओं के हाथ में है। यही कारण है कि अमेरिका में मतदाता पंजीकरण, पहचान संबंधी नियम,अर्ली वोटिंग एब्सेंटी वोटिंग और मेल - इन वोटिंग जैसी व्यवस्थाओं में राज्य-दर-राज्य अंतर दिखाई देता है।इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि अमेरिका में कोई एक समान राष्ट्रीय मतदान प्रक्रिया नहीं है, जबकि भारत में चुनाव संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिक केंद्रीकृत संवैधानिक ढांचा मौजूद है। भारत में मतदाता पंजीकरण के बाद मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान की जांच होती है। दूसरी ओर, अमेरिका में संघीय चुनावों के लिए पहचान और नागरिकता संबंधी नियमों का ढांचा अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है। यही अंतर ट्रंप के सेव एक्ट अभियान का मूल राजनीतिक मुद्दा बन गया है। व्हाइट हाउस स्वयं दावा करता है कि भारत और ब्राजील जैसे देश मतदाता पहचान को अधिक मजबूत पहचान-प्रणालियों से जोड़ते हैं, जबकि अमेरिका में नागरिकता के संबंध में व्यापक रूप से सेल्फ-अटेस्टेशन कीव्यवस्था पर निर्भरता रही है। हालांकि इस तुलना को सावधानी से समझना जरूरी है,भारत में भी आधार को अनिवार्य मतदाता पहचान के रूप में इस्तेमाल करने का अर्थ नहीं है; निर्वाचन आयोग मतदान के लिए कई वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज स्वीकार करता है। साथियों बात अगर हम क्या है सेव अमेरिका एक्ट ? इसको समझने की करें तो,यहां एक महत्वपूर्णतथ्यात्मक स्पष्टता आवश्यक है। इसका आधिकारिक नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट , संक्षेप में सेव एक्ट है। यह कोई स्वास्थ्य संबंधी सेव कानून नहीं, बल्कि अमेरिकी चुनावों में मतदाता पात्रता और नागरिकता सत्यापन से जुड़ा प्रस्तावित संघीय कानून है। इसका मूल उद्देश्य संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करना है। आधिकारिक विधायी रिकॉर्ड के अनुसार एच.आर.22 को 3 जनवरी 2025 को प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया और 10 अप्रैल 2025 को सदन ने इसे 220-208 मतों से पारित कर दिया। इसके बाद यह सीनेट को भेजा गया। इसलिए इसे यह कहना सही नहीं होगा कि सेव एक्ट पहले ही पूर्ण संघीय कानून बन चुका है।प्रस्तावित कानून में अमेरिकी नागरिकता साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की व्यवस्था की गई है, जिनमें वैध अमेरिकी पासपोर्ट, कुछ प्रकार के रियल आईडी -अनुरूप पहचान दस्तावेज, सैन्य पहचान एवं संबंधित रिकॉर्ड तथा सरकार द्वारा जारी कुछ अन्य दस्तावेज शामिल हैं। कानून का मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संघीय चुनावों में केवल पात्र अमेरिकी नागरिक ही पंजीकृत हों। साथियों बात अगर हम मेल-इन वोटिंग पर भी सख्ती का प्रस्ताव को समझने की करें तो,सेव एक्ट की बहस केवल फोटो पहचान तक सीमित नहीं है। व्हाइट हाउस के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में सामान्य मेल-इन बल्लोंट्स को सीमित करने और बीमारी, विकलांगता,सैन्य सेवा अथवा यात्रा जैसे विशेष मामलों में उन्हें अनुमति देने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों को मतदाता सूचियों से गैर-नागरिकों के नाम हटाने के लिए व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई है।यहीं से अमेरिका की चुनावी बहस अधिक संवेदनशील हो जाती है। समर्थकों का तर्क है कि मतदान प्रक्रिया में नागरिकता और पहचान की मजबूत पुष्टि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाएगी। विरोधियों की चिंता है कि अत्यधिक दस्तावेजी बाध्यताएं उन वैध मतदाताओं के लिए मतदान कठिन कर सकती हैं जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अमेरिकी बहस का वास्तविक प्रश्न केवल यह नहीं है कि वोटर आईडी होना चाहिए या नहीं? बल्कि यह है कि पहचान और नागरिकता सत्यापन की व्यवस्था ऐसी कैसे हो जो चुनावी सुरक्षा भी बढ़ाए और पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार में अनावश्यक बाधा भी न डाले। साथियों बात अगर हम ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट अब इंडिया इलेक्शन मॉडल से जुड़ता दिखाई दे रहा है,ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी फर्स्ट की राजनीति केसमर्थक रहे हैं। लेकिन इस बार उनके चुनावी सुधार अभियान में भारत का उदाहरण सामने आना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस भारत की चुनावी प्रणाली को लेकर भारतीय राजनीति में लगातार बहस होती रहती है, उसी व्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश में चुनावी सुधारों के पक्ष में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहअत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना अमेरिकी चुनावी बहस का संदर्भ 18 अगस्त 2026 की ट्रंप टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत-अमेरिका संबंधों की चर्चा को व्यापार,रक्षा,तकनीक और रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्थाओं तक पहुंचा दिया है। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित सवाल का हवाला देकर अपने सेव एक्टअभियान को मजबूत करने की कोशिश की है और भारत के विशाल चुनावी अनुभव को अमेरिकी मतदाता पहचान बहस के केंद्र में ला दिया है।लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से कुछ सीखने की बात करे।आज सवाल केवल यह नहीं है कि अमेरिका भारत से क्या सीखेगा;बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी इस अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा को आत्ममुग्धता के बजाय अपनी चुनावी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के अवसर में बदलेगा? यही वह बिंदु है जहां अमेरि?ी फर्स्ट की बहस में भारत का चुनावी मॉडल एक नई कड़ी जोड़ता दिखाई देता है डेमोक्रेसी फर्स्ट ,वोटर फर्स्ट और ट्रस्ट फर्स्ट। भारतीय लोकतंत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उल्लेखनीय क्षण है।यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है।भारत में प्रत्येक बड़े चुनाव के बादईवीएम मतदाता सूची, चुनाव आयोग की निष्पक्षता मतदान प्रतिशत और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद उठते हैं। विपक्ष कई बार चुनाव आयोग से सवाल करता है और सत्ता पक्ष चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता का बचाव करता है। लेकिन उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत की मतदाता पहचान व्यवस्था को अमेरिकी चुनाव सुधार के संदर्भ में उद्धृत किया जाना यह संकेत देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन केवल घरेलू राजनीतिक चश्मे से सटीकता से नहीं किया जाना चाहिए। साथियों बात अगर हम क्या अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए? इसको समझने की करें तो इस प्रश्न का उत्तर न तो पूरी तरह हां है और न ही पूरी तरह नहीं। भारत और अमेरिका की संवैधानिक संरचना, संघीय व्यवस्था,चुनावी इतिहास, मतदान पद्धति और प्रशासनिक ढांचे अलग हैं। इसलिए भारत की पूरी चुनाव प्रणाली को ज्यों का त्यों अमेरिका में लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन कुछ सिद्धांत अवश्य साझा किए जा सकते हैं,जैसे मतदाता की पहचान की विश्वसनीय पुष्टि, मतदाता सूची का नियमित शुद्धिकरण, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदान की ऑडिटेबिलिटी, मजबूत चैन ऑफ कस्टडी और मतदाता पात्रता की स्पष्ट पुष्टि।भारत का अनुभव यह दिखाता है कि विशाल पैमाने पर चुनाव कराना केवल कानून बनाने से संभव नहीं होता; इसके लिए चुनावी प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी प्रणाली, प्रशिक्षित कर्मचारियों, मतदाता सूची प्रबंधन और चरणबद्ध मतदान की विशाल मशीनरी चाहिए। यही भारत की वास्तविक चुनावी क्षमता है। साथियों, दूसरी ओर अमेरिका की चिंता भी समझना जरूरी हैं, अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि लोकतंत्र में सबसे पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि चुनाव का फैसला उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जाए जिन्हें कानूनन मतदान का अधिकार प्राप्त है। व्हाइट हाउस ने इसी उद्देश्य से नागरिकता सत्यापन, मतदाता पहचान और मेल - बैलट सुरक्षा को प्रमुख चुनाव सुधार मुद्दा बनाया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्च 2026 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से संघीय चुनावों में नागरिकता सत्यापन और मेल /एब्सेंटी बैलट प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम भी उठाया था।लेकिन अमेरिकी व्यवस्था में राज्यों की संवैधानिक भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए संघीय स्तर पर एक समान कठोर नियम लागू करना राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से जटिल विषय है। सेव एक्ट के समर्थक इसे चुनावी सुरक्षा की जरूरत बताते हैं, जबकि आलोचक इसे मताधिकार पर संभावित अतिरिक्त बोझ के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि यह कानून अमेरिका में सिर्फ चुनाव सुधार का विषय नहीं बल्कि मताधिकार, संघवाद और नागरिक स्वतंत्रता की बहस भी बन गया है। साथियों बात अगर हम भारत के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है इसको समझने की करें तो,ट्रंप की टिप्पणी को केवल भारत की प्रशंसा मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा।यह भारत के लिए भी आत्ममंथन का अवसर है। यदि विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश भारत की चुनावी पहचान प्रणाली से कोई तत्व सीखने योग्य मानता है,तो भारत को भी अपनी चुनावी व्यवस्था को लगातार अधिक पारदर्शी तकनीकी रूप से सुरक्षित और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत केवल इस बात में नहीं होती किचुनाव समय पर हो जाए; असली ताकत तब होती है जब मतदाता को विश्वास हो कि उसका नाम सही है, उसकी पहचान सुरक्षित है, उसका वोट सही तरीके से दर्ज हुआ है और परिणाम निष्पक्ष प्रक्रिया से निकला है। भारत ने दुनिया को सबसे बड़े पैमाने पर चुनाव कराने की क्षमता दिखाई है। अब अगली चुनौती इस क्षमता के साथ विश्वास की गहराई बढ़ाने की है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। राखी पूर्व की लेवाली से बुधवार को किराना बाजार में नारियल उछल गया। शक्कर में तेजी का रूख कायम रहा। खाद्य तेल व तिलहनों में टिकाव रहा। दलहनों में बाजार बने रहे। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार नारियलों में आवकें सामान्य है। राखी पूर्व की लेवाली से बाजार उछाल पर रहे। शक्कर में भी तेजी का रूख रहा। खाद्य तेलों में व्यापार अच्छा रहा। तिलहनों में सोयाबीन बाजार नरमी पर रहे। दलहनों में चना 6600-6650 रू. प्रति क्विंटल पर मजबूत रहा। तुअर-उड़द में बाजार सुर्ख रहे। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 5700-5800, खोपरा गोला 370-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 775-785, गारबल्ड 755-760, मटरदाना 800-900, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची शंकर 3500-3800, मीडि?यम 4000-4200, बेस्ट 4400-4600, एक्ट्रा बेस्ट 4600-4800, पानबार 3000-3500, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 500-525, काजू (240) 925-950, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 850-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 850-900, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 1050-1100, अमेरिकन 975-1075, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 900-1000, बेस्ट 1250-1300, खारक एवरेज 75-80, मीडियम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 3400, (160) 3800, (200) 4400, (250) 5000,

तेल- सींगदाना 1730-1750, मुम्बई 1770, राजकोट तेलिया 2730, सोया साल्वेंट 1400-1410, सोया रिफाइंड 1460-1465, कपास्या 1620, धूलिया 1610, कड़ी 1625,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1675-1700, मुम्बई पाम 1495, मुम्बई सोया 1500,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2690, देवास-उज्जैन 2690, खंडवा-बुरहानपुर 2660, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8000-8200, रायडा 7200-7400, सोयाबीन 6300, टोली (महुआ बीज) 5500-5600, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6600-6650, एवरेज 6300-6400, विशाल 6375-6475, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6000-6050, एवरेज 5900-5950, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7000-7300, मूंग पुराना बोल्ड 7400-7600, मीडियम 7300-7400, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9300-9500, उड़द गर्मी 8600-9300, ग्रेविटी क्लीन 9700-10000, हल्की 5000-7000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000-9500, बासमती दुबार 8000-8500, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11800, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। बुधवार को स्थानीय सराफा बाजार में व्यापार की मात्रा सामान्य ही रही। दोनों ही मूल्यवान धातुओं में बाजार नरमी के रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चाँदी (9999) 229800, चाँदी (99) 229600, टंच 228900, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 149500,

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.57 पर बंद हुआ। वही गत दिवस रुपया 95.74 पर बंद हुआ। आज सबह रुपया 95.72 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला रुपया सोमवार को 19 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.61 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 फीसद टूटकर 99.63 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत के करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से संबंधित डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुंबई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट रही। वहीं गत दिवस भी ये गिरा था। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भी घरेलू बाजार पर दबाव पड़ा है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। आज कारोबार के दौरान पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, आईसीसी के शेयर गिरे हालांकि, कुछ आईटी शेयरों ने बाजार की इस गिरावट को थामा। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 325.78 अंक की गिरावट के साथ ही 76,909.68 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 76.60 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,078.30 अंकों पर बंद हुआ। बाजार की व्यापक स्थिति कमजोर रही। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से केवल 8 के शेयर ही लाभ के साथ बंद हुए। वहीं 21 अन्य में

गिरावट रही। इसी तरह, निफ्टी की 50 कंपनियों में से 34 के शेयर नीचे आये जबकि केवल 16 में तेजी दर्ज की गई। सरकारी बिजली कंपनी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.00 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जो सेंसेक्स के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके विपरीत, आईटी क्षेत्र से एचसीएल टेक का शेयर 1.73 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा। गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, आईसीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि रहे जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, टाइटन, टीसीएस, इन्फोसिस और ट्रेंट के शेयरों में तेजी रही। बजाज फिनसर्व के शेयर बिना किसी बदलाव के सपाट रहे। इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स करीब 94.57 अंक की गिरावट के साथ 77,140.89 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी50 भी 38.30 अंक फिसलकर 24,116.60 पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार को नैस्डैक कंपोजिट 1.33 फीसदी और एसएंडपी 500 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी लगभग 0.2 फीसदी नीचे बंद हुआ।

ओपनएआई ने किशोरों के लिए शुरु किया नया चैटजीपीटी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

नई दिल्ली। एजेंसी। ओपनएआई ने 13 से 17 साल की उम्र के किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी सेवा शुरू की। कंपनी के मुताबिक इसमें ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और अभिभावकों के नियंत्रण की सुविधा होगी यानी वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। यदि चैटजीपीटी के सिस्टम को शक होता है कि उपयोगकर्ता की उम्र 18 साल से कम है, तो यह नया फीचर अपने आप सक्रिय हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि ऐसे उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से किशोरों के लिए चैटजीपीटी अनुभव में रखा जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा तय की जा सके।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओपनएआई ने कहा कि किशोरों के लिए चैटजीपीटी फीचर सीखने और सुरक्षा सुविधाओं को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य कक्षा के बाहर सक्रिय और सहयोगात्मक सीखने में मदद करना और एआई के ज्यादा सोच-समझ कर और उम्र के अनुरूप उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में ऐसी सामग्री से सुरक्षा शामिल है, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाने, हिंसा, खतरनाक गतिविधियों या किसी भी तरह की यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का चित्रण हो। ओपनएआई इंडिया में स्ट्रैटजी और वैश्विक मामलों की प्रमुख ने यह जानकारी दी।

डिजिटल भुगतान की बढ़त के बीच नगदी के प्रचलन में नहीं आई गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच व्यक्तिगत लेन-देन में नकदी की हिस्सेदारी भले ही कम हो रही है, लेकिन प्रचलन में नकदी की मात्रा दो अंकों की दर से लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि इससे न केवल भविष्य के लिए नकदी की मांग का अनुमान लगाना कठिन हो गया है बल्कि बैंक नोटों के उत्पादन एवं वितरण क्षमता के लिए आरबीआई की योजना भी जटिल होती जा रही है। मुर्मू ने कहा कि पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाना क्रांतिकारी रहा है, लेकिन प्रचलन में नकदी की मात्रा में कोई गिरावट नहीं आई है। ऐसा खास तौर पर ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में, कम आय वाले लोगों, बुजुर्गों और छोटे कारोबारियों के बीच देखा जा रहा है। मुर्मू ने बताया कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने छह मूल्य वर्गों में सालाना 28 से 30 अरब बैंक नोटों की छपाई की है और सालाना करीब 21 अरब बैंक नोटों का निपटान किया है। फिलहाल देश में 176 अरब बैंक नोट प्रचलन में हैं। इसके मुकाबले पिछले साल के आखिर में करीब 56 अरब डॉलर बिल और 30 अरब यूरो के बैंक नोट प्रचलन में थे। उन्होंने कहा कि भारत में यह संख्या कुछ हद तक कम मूल्य वाले नोटों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से है। इसका मतलब साफ है कि समान मूल्य के लेनदेन के लिए ज्यादा नोटों का आदान-प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने फील्ड ट्रायल के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के 1 अरब पॉलिमर बैंक नोट लाने को मंजूरी दे दी है। अगर फील्ड ट्रायल और परिचालन संबंधी आकलन के नतीजे संतोषजनक रहे तो आरबीआई वित्त वर्ष 2028 की शुरुआत से परीक्षण के आधार पर पॉलिमर बैंक नोटों को प्रचलन में लाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय बैंक ने पॉलिमर सबस्ट्रेट की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन आरबीआई बड़े पैमाने पर जारी करने का फैसला लेने से पहले भारतीय जलवायु और उपयोग की परिस्थितियों में इन नोटों का परीक्षण करेगा।

मेष- आज किस्मत आपका पूरा साथ देती नजर आ रही है। व्यापार में सफलता के अच्छे संकेत हैं और नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। आपकी मेहनत अब लोगों की नजर में आएगी और काम की तारीफ भी मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों का जनसमर्थन बढ़ सकता है। नए घर का सपना भी अब पूरा होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है।

वृषभ- आज मन को सुकून देने वाली खबर मिल सकती है। लंबे समय से चल रही कोई चिंता धीरे-धीरे खत्म होती नजर आएगी। ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे चेहरे पर खुशी आएगी। सरकारी दफ्तरों में अटके काम भी गति पकड़ सकते हैं। हालांकि, हर मामले में अपनी राय देना जरूरी नहीं है। आज समय और धन का सही इस्तेमाल करेंगे तो दिन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

मिथुन- आज किसी नई शुरुआत के लिए माहौल बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। दिल की कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। परिवार के साथ खास समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी तथा बच्चों के साथ रिश्ते और मधुर होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता सबसे जरूरी रहेगी।

कर्क- आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार और अपनों का साथ इसे खास बना देगा। घर में साफ-सफाई, सजावट या मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। कानूनी मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें और किसी कागज या प्रक्रिया को हल्के में न लें। पड़ोसियों के साथ अपनी निजी बातें साझा करने से बचना बेहतर होगा। शांति बनाए रखेंगे तो दिन आराम से बीतेगा।

सिंह- आज आपके लिए चमकने और आगे बढ़ने का दिन है। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए भविष्य के नए रास्ते खोल सकती है। परिवार और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछली गलतियों से सीख लेकर आप इस बार ज्यादा समझदारी से कदम बढ़ाएंगे। कला, रचनात्मकता और किसी खास हुनर में निखार आएगा। पुराने कर्ज से राहत मिलने के भी संकेत हैं।

कन्या- आज आपकी मीठी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे। आप जिस तरह अपनी बात रखेंगे, उससे लोग आसानी से आपकी ओर आकर्षित होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार रह सकता है और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से अटके काम अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। घूमने या यात्रा के दौरान कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे आपके काम आए।

तुला- आज धन और आत्मविश्वास दोनों आपका साथ देंगे। आपकी रचनात्मक सोच आपको किसी नई उपलब्धि तक पहुंचा सकती है। साझेदारी में किए गए कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं। हालांकि, किसी को उधार पैसा देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि वापसी में परेशानी हो सकती है। आज दूसरों की सलाह से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करना आपके लिए सही रहेगा। यही अनुभव आपको सही दिशा दिखाएगा।

वृश्चिक- आज आपका आकर्षण और आत्मविश्वास लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। मेहनत का पूरा फल मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंता भी कम हो सकती है। हालांकि, पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी के बहकावे में आकर बड़ा जोखिम लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में दबाव जरूर रहेगा, लेकिन आपकी क्षमता आपको हर स्थिति को संभालने में मदद करेगी।

धनु- आज का दिन कुछ खुशियां और कुछ सीख लेकर आएगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। हालांकि, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपकी उम्मीद से थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन इसे असफलता न समझें। यह समय आपको आगे के लिए तैयार कर रहा है।

मकर- आज दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और दिल की कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने पर ध्यान देने का सही समय है। मां की सेहत से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा या कोई हलचल हो सकती है। दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा उलझने के बजाय अपने काम और लक्ष्यों पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा।

कुंभ- आज नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के सामने कोई अच्छा अवसर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत से बॉस प्रभावित होंगे और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दूसरों की मदद करने की आपकी आदत आपको लोगों के बीच खास बनाएगी, लेकिन इसके साथ अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है।

मीन- आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। वाणी में संयम रखें, क्योंकि आपकी कही कोई बात गलत समझी जा सकती है और मामला बिगड़ सकता है। मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी भी जानकारी को बिना जांचे-परखे आगे साझा न करें, वरना परेशानी हो सकती है।

शब्दजाल - 8355

श	रा	कै	फी	आ	ज	मी	ट	झ	क	न
नौ	च	र	ह	रिं	लै	ता	दि	शा	को	र
शा	र	श	बा	ना	आ	ज	मी	अ	ल	गि
द	म	दा	च	ल	क	ड़	हा	मि	र	स
व	क	र	ष	अ	मि	री	चि	ता	र	ट
ह	ह	मा	व	दा	भि	ला	ती	भ	न	ती
ट	ट	बु	ल	र	म	जी	ह	ब	ह	क
बा	जी	वा	ला	अ	छ	स	त	च्च	जू	ट
स	थो	शे	व	ह	म	दा	ने	न	र	द
र	ल	लें	ति	रं	ट	रो	बें	न	रु	थो
र	वीं	द्र	जै	न	ख	बौ	ही	स	मी	र

शब्द जाल में उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख सिने व्यक्तित्व के नाम ढूंढिए, नाम ऊपर से नीचे एवं तिरछे भी हो सकते हैं.

नौशाद, कमाल अमरोही, कैफी आजमी, नरगिस, शैलेंद्र, समीर, अभिजीत, रवींद्र जैन, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन

शब्दजाल - 8354 का हल

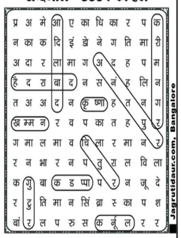

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली - 7299

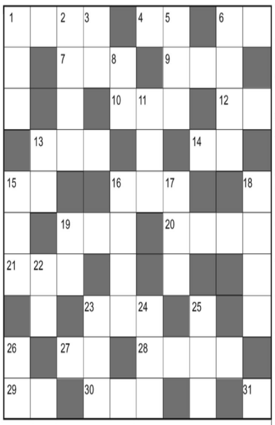

बायें से दायें:-

१. ऋषिकपूर, मनीषा की 'दिल की कही ना जाए' गीत वाली फिल्म-४
४. 'मैं नाचूँ बिन पायल' गीत वाली रितिक, करिश्मा, नेहा की फिल्म-२
६. कृतिका, सोनू की 'सुबह सुबह जब खिड़की' गीत वाली फिल्म-२
७. 'तेरी गलियों में ना' गीत वाली अनिल धवन, नीतूसिंह की फिल्म-३
९. फिल्म 'चोरी चोरी' में राजकपूर के साथ नायिका कौन थी-३
१०. फिल्म 'रणभूमि' में ऋषिकपूर के साथ नायिका कौन थी-३
१२. ऋषिकपूर, डिम्पल की 'मैं शायर तो नहीं' गीत वाली फिल्म-२
१३. 'पिया तू अब तो आजा' गीत वाली फिल्म 'कारवाँ' का नायक-३
१४. प्रशांत, ऐश्वर्या की 'कोलंबस कोलंबस' गीत वाली फिल्म-२
१५. 'बाबा मेरी ये जवानी' गीत वाली मनोज वाजपेयी, तब्बू की फिल्म-२
१६. जैकी, जूही, अमृता की 'गोरिया रे गोरिया रे' गीत वाली फिल्म-३
१९. 'दम भर जो उधर मुँह फेरे' गीत वाली राजकपूर, नर्गिस की फिल्म-३
२०. धर्मेन्द्र, हेमा की 'ए बी सी डी छोड़ो' गीत वाली फिल्म-२,२
२१. 'यादें' में रितिक की नायिका -३
२३. अमिताभ, मौसमी की 'यारा ओ यारा' गीत वाली फिल्म-३
२७. 'मेरी जाँ प्यार करो' गीत वाली मिथुन, पद्मिनी, रंजीता की फिल्म-२
२८. शत्रुघ्न, मिथुन, हेमा, अनिल राज की 'बचके मेरी जान बचके' गीत वाली फिल्म-४
२९. 'कोई सोने के दिल वाला' गीत वाली देवआनंद, माला की फिल्म-२
३०. 'अगर जिंदगी हो तेरे संग हो' गीत वाली फिल्म-३
३१. 'चंदा ने दी चाँदनी' गीत वाली जीतेंद्र, जयाप्रदा की फिल्म-१

ऊपर से नीचे:-

१. 'हँसदे हँसदे' गीत वाली कमल हासन, रवीना, मनीषा की फिल्म-३
२. अमिताभ, शाहरूख, उदय चोपड़ा, ऐश्वर्या, किम शर्मा, प्रीति की फिल्म-४
३. 'आजा आजा गिव मी ए' गीत वाली सलमान, रेवती की फिल्म-२
५. 'दिल क्यों धड़कता है' गीतवाली फिल्म-३
६. 'सुनिये तो रूकिये तो' गीत वाली शाहरूख, जूही चावला की फिल्म-२,२
८. फिल्म 'सवेरे वाली गाड़ी' में नायक-२
११. मिथुन, आदित्य, रेखा की 'मेरा नाम बिल्लू' गीत वाली फिल्म-३
१३. 'अभी साँस लेने की' गीत वाली सलमान, सनी, करिश्मा की फिल्म-२
१५. सनी, मीनाक्षी, ममता की 'कोई जाए तो ले' गीत वाली फिल्म-३
१६. 'मेरे सपनों की रानी' गीत वाली राजेश खन्ना, शर्मिला की फिल्म-४
१७. मिथुन, अतुल, पूजाभट्ट की 'तेरे बिन मैं कुछ' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'जीवन के सफर में राही' गीत वाली देवआनंद, नूतन की फिल्म-४
१९. 'कभी हाँ कभी ना' में सुचित्रा कृष्णामूर्ति के चरित्र का नाम-२
२२. 'सनम तेरी कसम' में नायिका कौन-२
२३. सनी, अमृता की 'तेरी तसवीर मिल गई' गीत वाली फिल्म-३
२४. 'प्यार कोई खेल नहीं' की नायिका-३
२५. 'रूके रूके से' गीत वाली फिल्म जिसमें संजीव, शर्मिला थे-३
२६. फिल्म 'संन्यासी' में नायिका कौन थी-२

फिल्म वर्ग पहेली - 7298

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

20 अगस्त 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ	समय
सूर्य	सिंह में	सिंह	05.25 बजे से
चंद्र	वृश्चिक में	कन्या	07.41 बजे से
मंगल	मिथुन में	तुला	09.52 बजे से
बुध	कर्क में	वृश्चिक	12.07 ब.से
गुरु	कर्क में	धनु	14.23 बजे से
शुक्र	कन्या में	मकर	16.28 बजे से
शनि	मीन में	कुंभ	18.14 बजे से
राहु	कुंभ में	मीन	19.47 बजे से
केतु	सिंह में	मेष	21.18 बजे से
		वृष	22.58 बजे से
		मिथुन	00.56 बजे से
		कर्क	03.09 बजे से

राहुकाल 1.30 से 3.00 बजे तक

गुरुवार 2026 वर्ष का 232 वा दिन
दिशाशूल दक्षिण **ऋतु** वर्षा।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास श्रावण **पक्ष** शुक्ल
तिथि अष्टमी 21.19 बजे को समाप्त।
नक्षत्र विशाखा 09.08 बजे को समाप्त।
योग इन्द्र 04.26 बजे को समाप्त।
करण विष्टि 08.16 बजे तदनन्तर बव 21.19 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 7.3 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 12° 30'
सूर्य दक्षिणायन
कलि अहर्गण 1872807
जूलियन दिन 2461272.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1448
महीना रवि उलावल
तारीख 06
विशेष मासिक दुर्गाष्टमी।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
शुभ	05.54 से	07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से	07.11 बजे तक
रोग	07.22 से	08.51 बजे तक	चर	07.11 से	08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से	10.19 बजे तक	रोग	08.43 से	10.15 बजे तक
चर	10.19 से	11.47 बजे तक	काल	10.15 से	11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से	01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से	01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से	02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से	02.51 बजे तक
काल	02.43 से	04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से	04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से	05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगत: जीवन की सार्थकता

हकीम लुकमान का बचपन अभावों में बीता था। उन्हें भरण-पोषण के लिए गुलामी भी करनी पड़ी। एक बार उनके मालिक ने ककड़ी खानी चाही। उसने लुकमान को ककड़ी लाने का आदेश दिया। लुकमान ककड़ी ले आए। मालिक ने ज्यों ही ककड़ी मुंह से लगाई उसे पता चल गया कि ककड़ी अत्यंत कड़वी है। मालिक ने ककड़ी लुकमान की ओर बढ़ा दी और कहा, 'ले, इसे तू खा ले!' लुकमान ने ककड़ी ले ली और बिना मुंह बिचकाए उसे खा गए। लुकमान के मालिक को बेहद आश्चर्य हुआ। वह तो यह मानकर चल रहा था कि इतनी कड़वी ककड़ी कोई खा ही नहीं सकता, इसलिए लुकमान इसे फेंक देंगे। लेकिन जब लुकमान ने पूरी ककड़ी सहजता से खा ली तो मालिक ने पूछा, 'तू इतनी कड़वी ककड़ी कैसे खा गया?' लुकमान ने हंसते हुए कहा, 'मेरे अच्छे मालिक! आप मुझे रोज स्वादिष्ट खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं। आपके द्वारा दी गई चीजों का मैं मजा लेता हूं। ऐसे में अगर आपने एक दिन कड़वी ककड़ी दे भी दी तो मैं क्या उसे नहीं खा सकता? मैंने उसे भी और चीजों की तरह ही अच्छा मानकर लिया और खाया।' लुकमान का मालिक समझदार और दयालु था। उसने लुकमान की इस बात का आदर किया। वह बोला, 'आज तुमने मुझे जीवन का बड़ा सच बताया है। परमात्मा हमें अनेक प्रकार के सुख देता है, उसी के हाथ से यदि कभी दुख भी आए तो उस दुख को हमें खुशी-खुशी स्वीकार करना चाहिए। इसी से जीवन सार्थक हो सकता है। आज से तुम गुलाम नहीं रहोगे।'

सूडोकु नवताल- 7608

★☆☆☆☆ सरल

7	8				2	6		3
			4					
1	3	5		8				
	2			1			7	8
6	7			9			2	
				6		5	9	2
					3			
2		8	5				6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -7607 का हल

4	3	2	9	5	6	1	7	8
6	8	5	7	1	4	9	2	3
9	1	7	3	8	2	4	5	6
3	4	8	6	2	7	5	1	9
5	6	1	8	4	9	2	3	7
2	7	9	5	3	1	6	8	4
1	9	3	4	7	5	8	6	2
8	2	4	1	6	3	7	9	5
7	5	6	2	9	8	3	4	1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

शब्द पहेली - 8823

बाएँ से दाएँ

1. ओस की बूंदे (उर्दू-4)
3. आसमान, गगन-3
5. निम्न, जो स्तरीय न हो-4
8. रात्रि, निशा-2
10. सिलना, छाती
11. नश, नाड़ी-2
13. एक समाज सुधारक जिनके दोहे काफी प्रसिद्ध हैं-2
15. इसे आंखों में लगाते हैं-3
16. प्रभाव-3
17. समीप, पास, नजदीक-3
19. भगवान, खुदा-2
20. जानवर इसे खाते हैं-2
21. होठ, अधर-2
23. लूटपाट, डाका-4
25. प्रकार-3
26. बेबस, लाचार-4

ऊपर से नीचे

1. चिंगारी, अंगारा-3
2. मस्ती में चूर-2
3. इज्जत, साख-2
4. तलवार (उर्दू-4)
6. रसदार, रस से भरा-3
7. मेहंदी, ऋषि कपूर की फिल्म-2
9. सब्जी, भाजी-4
13. कमी-3
14. अकबर के एक हिंदू सलाहकार-4
17. अचरज भरा कार्य-4
18. वायुसेना के एक विमान का नाम-3
20. चाहत, प्रेम-2
22. ऋतुराज, मौज-मस्ती-3
23. रास्ता, डगर-2
24. एक पेड़ जिसकी टहनी से दातुन करते हैं-3

शब्द पहेली -8822 का हल

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

13 पेटी शराब जब्ती मामले में जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे ने आबकारी विभाग पर उठाए सवाल

कोचेवाही में इतनी बड़ी मात्रा में शराब पहुंची कहां से? सप्लाई करने वाले ठेकेदार और संबंधित दुकान पर कार्रवाई कब?

पद्मेश न्यूज। लांजी।

ग्राम कोचेवाही में आबकारी विभाग द्वारा दो घरों से करीब 13 पेटी देशी एवं अंग्रेजी शराब जब्त किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक एवं सामाजिक तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ज्योति ईश्वर उमरे ने मामले को लेकर आबकारी विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे ने कहा कि गांव-गांव में बड़ी मात्रा में शराब पहुंचने के पीछे केवल स्थानीय स्तर पर शराब बेचने वाले लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि यह पता लगाना भी जरूरी है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब की सप्लाई आखिर कहां से हो रही है। उन्होंने आबकारी विभाग से सवाल किया कि कोचेवाही में जब्त 13 पेटी शराब किस लाइसेंसी दुकान अथवा ठेकेदार के माध्यम से गांव तक पहुंची?

उन्होंने कहा कि यदि शराब किसी लाइसेंसी दुकान या ठेकेदार के माध्यम से अवैध रूप से गांव तक पहुंची है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलने के बाद संबंधित शराब दुकान की जांच, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई तथा दुकान को सील करने की प्रक्रिया क्यों नहीं की गई?

पुराने मामले का भी उठाया मुद्दा

ज्योति उमरे ने पूर्व में मीरिया ग्राम पंचायत के टेकेपार में पकड़ी गई करीब 103 लीटर शराब के मामले का हवाला देते हुए भी कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि उस मामले में ठेकेदार के नाम पर एफआईआर दर्ज होने तथा गांव-गांव शराब वितरण से संबंधित रजिस्टर जब्त किए जाने के बावजूद रजिस्टर में दर्ज संबंधित लोगों और रिसीवर दुकान के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए।

सरकारी शराब दुकान के आसपास शराब पिलाने पर भी सवाल

जिला पंचायत सदस्य ने सरकारी शराब दुकानों के आसपास शराब पिलाए जाने की शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर दुकानों के आसपास लोगों को शराब पिलाई जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार

अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

ज्योति उमरे ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई केवल छोटी मछलियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि शराब की सप्लाई के वास्तविक स्रोत तक जांच पहुंचनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आबकारी विभाग और प्रशासन द्वारा मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तथा केवल जब्ती की कार्रवाई तक मामला सीमित रहा, तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला स्तर पर जन-आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कोचेवाही में जब्त शराब के स्रोत की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए।

अग्रवाल समाज महिला मंडल ने मनाया हरियाली तीज

पद्मेश न्यूज। लांजी। अग्रवाल समाज महिला मंडल लांजी द्वारा हरियाली तीज के पावन अवसर पर सिंजारा झूला एवं हरियाली तीज उत्सव का आयोजन स्थानीय अग्रसेन भवन लांजी में उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। आयोजन में अग्रवाल समाज की महिलाओं एवं युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक संस्कृति, आपसी प्रेम और सामाजिक एकजुटता की सुंदर झलक देखने को मिली। हरियाली तीज के अवसर पर अग्रसेन भवन को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान एवं श्रृंगार के साथ उत्सव में भाग लिया। सिंजारा झूले पर झूलते हुए महिलाओं ने तीज के पारंपरिक गीतों का आनंद लिया और एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं। आयोजन के दौरान विभिन्न मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं। महिलाओं ने गीत-संगीत, नृत्य एवं अन्य कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में पारंपरिक रीति-रिवाजों और आधुनिक मनोरंजन का सुंदर संगम देखने को मिला। अग्रवाल समाज महिला मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक एकता को मजबूत करने वाला उत्सव भी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा करते हुए तीज पर्व की परंपरा को जीवंत किया। अग्रसेन भवन में देर तक उत्सव का माहौल बना रहा और पूरा परिसर हंसी-खुशी एवं उल्लास से सराबोर नजर आया।

डोरली में शराबबंदी को लेकर महिला समूह व ग्राम संगठन के नेतृत्व में हुई बैठक-अवैध शराब बिक्री पर लगाई रोक

पद्मेश न्यूज। लांजी। ग्राम पंचायत डोरली में शराबबंदी को लेकर महिला समूह एवं ग्राम संगठन के नेतृत्व में 19 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत डोरली की सरपंच श्रीमती सुकीबाई नाकतोड़े ने की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जप सदस्य रेवाजी करहाटकर उपस्थित रहे। बैठक में स्व-सहायता समूह ग्राम संगठन की अध्यक्ष अनीताबाई करहाटकर, महिला पंच एवं समूह की सदस्यों सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम डोरली में शराब की बिक्री पर रोक लगाने तथा ग्रामीणों को शराब के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान पैकारों को ग्राम पंचायत भवन में बुलाकर समझाइश दी गई। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे आगे से शराब का विक्रय नहीं करेंगे और न ही ठेकेदारों से शराब खरीदकर बेचेंगे। उपस्थित लोगों ने इस बात पर सहमति जताते हुए संकल्प लिया कि आज के बाद वे शराब नहीं बेचेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा शराब का विक्रय किया जाता है, तो महिला समूह एवं ग्रामीणजन मिलकर ग्राम स्तर पर उचित निर्णय लेंगे।

शराब से होने वाले नुकसान पर भी हुई चर्चा

बैठक में शराब के सेवन और अवैध बिक्री से होने वाले सामाजिक एवं पारिवारिक नुकसान पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि शराब के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, घरेलू विवाद बढ़ते हैं तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से यकृत, हृदय और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं, हिंसा और सामाजिक अपराधों की आशंका भी बढ़ती है। महिलाओं और बच्चों पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए गांव में शराबबंदी के लिए सामूहिक जागरूकता और सामाजिक सहयोग जरूरी है।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

बैठक में ग्राम पंचायत डोरली की सरपंच श्रीमती सुकीबाई नाकतोड़े, सचिव कुमारी जागृति तिवारी, रेवाजी करहाटकर, अनीताबाई करहाटकर, गीताबाई करहाटकर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिशुकला बंसोड़, करुणा नाकतोड़े, कौशलबाई नाकतोड़े, लक्ष्मीबाई ठाकरे, वैशाली नाकतोड़े, संगीता वाकड़े, भुवनेश्वरी भांडे, श्याम पिलारे, तुलसीबाई भज्जे, ममता मिश्रा, गीता नाकतोड़े, सीतारामजी सिसोदिया, मेहतर लुटे, मोहन लुटे, किशोर करहाटकर, देवेंद्र बागमारे एवं शोभाराम कोरे सहित महिला समूह की सदस्य और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। बैठक के अंत में ग्रामीणों एवं महिला समूह के सदस्यों ने ग्राम डोरली को शराबमुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

शारदा महिला मंडल ने मनाया हरियाली तीज एवं सावन झूला उत्सव

पद्मेश न्यूज। लांजी। सावन मास की हरियाली और उल्लास के बीच शारदा महिला मंडल लांजी द्वारा हरियाली तीज एवं सावन झूला उत्सव हर्षोल्लास और धार्मिक वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल जी अध्यक्ष श्रीमती उषादेवी पशीने जी के निवास पर आयोजित किया गया, जहां महिला मंडल की सभी सदस्यों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उत्सव में सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सावन के पारंपरिक गीतों के साथ झूला उत्सव का आनंद लिया तथा हरियाली तीज के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की। महिलाओं ने एक-दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सावन की खुशियों को साझा किया। पूरे आयोजन में उत्साह, उमंग और आपसी सौहार्द का माहौल बना रहा। उत्सव के उपरांत सभी सदस्यों के लिए प्रीतिभोज का आयोजन किया गया। महिला मंडल की सदस्यों ने सामूहिक रूप से आयोजन को सफल बनाने में सहभागिता निभाई।

सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में अग्रणी है शारदा महिला मंडल

शारदा महिला मंडल लांजी द्वारा समय-समय पर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्था महिलाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के साथ ही भारतीय परंपराओं और संस्कृति को जीवंत रखने की दिशा में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रही है। हरियाली तीज एवं सावन झूला उत्सव भी इसी श्रृंखला की एक सुंदर कड़ी रहा, जिसने महिलाओं को एकजुट होकर पर्व की खुशियां मनाने का अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष उषा देवी पशीने ने कहा— इस पावन अवसर पर शारदा महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती उषादेवी जी ने कहा कि हरियाली तीज हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति,

परंपरा और नारी शक्ति का सुंदर पर्व है। ऐसे आयोजनों से महिलाओं को आपस में जुड़ने, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर मिलता है। शारदा महिला मंडल हमेशा धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए प्रयासरत है। सावन की हरियाली की तरह सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशहाली बनी रहे, यही हमारी कामना है। आयोजित कार्यक्रम मे श्रीमती उषादेवी पशीने, श्रीमती सुशीला दुग्गड़, श्रीमती अंजू पशीने, श्रीमती कल्पना पशीने, अधिवक्ता बबिता पशीने, श्रीमती नम्रता आसटकर, कुमारी आराध्या आसटकर, श्रीमती भगवती करहि, नव्या बिलगौर, श्रीमती किरण तिवारी, श्रीमती अनीता रामटेककर, श्रीमती अनीता अग्रवाल, श्रीमती अंजलि रैंच, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, श्रीमती मीना बिलगौर, श्रीमती पद्मा शर्मा, श्रीमती उर्मिला अग्रवाल, श्रीमती उमा तिवारी, श्रीमती सुनीता रॉय, श्रीमती मंजू नारंग श्रीमती शिखा गोस्वामी, श्रीमती मनीषा दुग्गड़ सहित सभी महिला सदस्य उपस्थित रहे ।

श्रद्धा और आस्था के साथ साडरा में सम्पन्न हुआ अखण्ड श्री रामचरित मानस पाठ

पद्मेश न्यूज। लांजी। लांजी-किरनापुर क्षेत्र के ग्राम साडरा में अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ समिति, स्थानीय ग्राम समितियों एवं अभिनंदन लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ का 18 अगस्त से शुभारंभ होकर 19 अगस्त को विश्रांति के साथ समापन हुआ। अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ के शुभारंभ अवसर पर भगवान श्रीराम, माता सीता एवं लक्ष्मण की पूजा अर्चना की गई। नगर कीर्तन साथ निकली यात्रा ने पूरे गांव का भ्रमण किया।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर से एवं दवाई वितरण ग्रामीणों को मिला स्वास्थ्य लाभ

अखण्ड श्री रामचरित मानस पाठ एवं सेवा गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य एवं नेत्र संबंधी जांच का लाभ लिया। स्वास्थ्य शिविर में लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ विभिन्न बीमारियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में यूनाइटेड हॉस्पिटल हॉस्पिटल गोंदिया, एवं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर देव जी नेत्रालय जबलपुर द्वारा सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 145 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। वहीं निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर में 75 लोगों की जांच की गई, जिनमें 15 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। चिन्हित मरीजों को नियमानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देवजी नेत्रालय की ओर से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

योग शिविर – स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन की ओर एक कदम

योग अपनाएं, निरोग रहें- स्वस्थ जीवन की यही पहचान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना हर उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आयोजित योग शिविर में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं सभी आयु वर्ग के लोगों को योग और प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गांव का संदेश

कार्यक्रम के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। लोगों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने तथा कपड़े एवं जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई। स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया गया।

पौधारोपण अभियान–हर पौधा, धरती के भविष्य की उम्मीद

एक पौधा लगाएं, प्रकृति बचाएं — स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन अपनाएं। अखण्ड श्री रामचरित मानस पाठ एवं सेवा गतिविधियों के अंतर्गत पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और अधिक से अधिक पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं ग्रामीणजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पौधारोपण किया। सभी ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं सुरक्षा का संकल्प भी लिया महिलाओं ने हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम से दिया संस्कार और समरसता का संदेश भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महिला मंडल द्वारा हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं ने एक-दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार में प्रेम, संस्कार, सहयोग एवं आदर्श व्यवहार बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में परिवार की सुख-समृद्धि एवं सामाजिक सद्भाव की कामना की गई।

बच्चों ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को सांस्कृतिक गतिविधियों से संदेश दिया गया कि आज बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति दी ग्राम के ही बच्चे ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत । कार्यक्रम में सहयोगी सदस्य ग्रामीणजन सर्व श्री कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी का पूर्ण सहयोग रहा।

ग्राम कुम्हारीकला में अखण्ड पाठ का शुभारंभ

इसी क्रम में ग्राम कुम्हारीकला में स्थानीय नागरिकों, ग्राम समितियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से 19 अगस्त 2026 को संगीतमय अखण्ड श्रीरामचरित मानस पाठ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का समापन 20अगस्त को विश्रांति के साथ स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच शिविर, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान एवं महाप्रसाद के साथ किया गया। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से धार्मिक एवं सामाजिक सेवा के इस आयोजन में सहभागिता का आग्रह किया।

पूर्व सरपंच मोहनलाल येड़े का दुःखद निधन

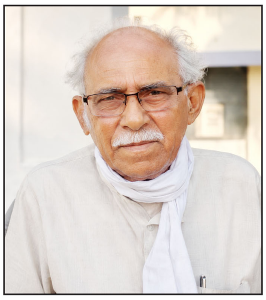

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत कलपाथरी निवासी व पूर्व सरपंच मोहनलाल पिता कुंवरलाल येड़े का 74 वर्ष की आयु में बुधवार 19 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि लगभग 2.30 बजे अस्वस्थता के चलते निधन हो गया। आप अपने पीछे दो पुत्र एवं दो पुत्रियों नाती पोतों से भरा-पूरा परिवार छोड़ स्वर्ग सिधार गए। पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज 20 अगस्त को स्थानीय मोक्ष धाम कलपाथरी मे सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किया जायगा। आपके निधन पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, नाते रिस्तेदारों के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए. ईश्वर से मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने तथा इस दुःख की घड़ी मे परिजनों को संबल प्रदान करने

लांजी में ''पद्मेश''

इंटरनेट (ब्राडबेंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें

Mo. 8319969927

मप्र में 15 प्रतिशत बढ़ेगा टैक्सियों का किराया, प्राइवेट नंबर प्लेट गाड़ियों पर लगेगी पूरी रोक

भोपाल। राजधानी भोपाल में दो दिनों से जारी कैब और टैक्सी चालकों की हड़ताल आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गई। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यूनियनों की मांगों पर सहमति बनने के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति सम्पूर्ण भारत के प्रतिनिधियों के साथ ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारी भी शामिल हुए।

परिवहन मंत्री ने एग्रीगेटर कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक राज्य में नई किराया प्रणाली लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी कंपनियों को चालकों के वर्तमान किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऐप से प्राइवेट नंबर प्लेट वाले वाहनों (कार और बाइक) को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया गया है।

20 दिनों में तैयार होगी नई किराया प्रणाली

बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम लागू किया जाएगा, जिससे एग्रीगेटर कंपनियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो सकेगा। चालकों के हित में राज्य सरकार द्वारा एक नई किराया प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग और टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों को मिलाकर एक विशेष कमेटी का गठन किया जा रहा है। यह कमेटी अन्य राज्यों में लागू किराया प्रणालियों का अध्ययन करेगी और 15 से 20 दिनों के भीतर सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के लिए नई किराया नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगी।

सभी एग्रीगेटर कंपनियों को इस कमेटी द्वारा तय दरों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। साथ ही कंपनियों को भोपाल में अपने आधिकारिक कार्यालय भी खोलने होंगे, ताकि चालकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निवारण किया जा सके।

यूनियनों ने जताई खुशी, बोले- चालकों को मिलेगी आर्थिक राहत

भोपाल टैक्सी चालक संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) के महामंत्री राजेश कुमार नागले ने बताया कि यह हमारे संघ और संयुक्त मोर्चे के संघर्ष की बड़ी जीत है। परिवहन मंत्री ने हमारी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। प्राइवेट वाहनों को कमर्शियल तौर पर चलाने से हमारे वैध टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा था, जिस पर अब रोक लगेगी। किराए में 15त्न की तत्काल वृद्धि से चालकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

टैक्सी यूनियन कल्याण समिति सम्पूर्ण भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव नफीस उद्दीन ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य कैब चालकों के अधिकारों की रक्षा करना और एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाना था। सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम लागू करने और नई किराया नीति के लिए कमेटी बनाने के फैसले से अब कंपनियों पर शासन का नियंत्रण रहेगा। कमेटी में यूनियन के सदस्य भी शामिल रहेंगे, जिससे चालकों के हित में पारदर्शी किराया तय हो सकेगा। मांगें पूरी होने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है।

हड़ताल के दौरान निजी वाहनों के पहियों की निकाली हवा

हड़ताल के दूसरे दिन बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास यूनियन सदस्यों ने नियम विरुद्ध चल रहे कुछ निजी नंबर प्लेट वाले व्यावसायिक वाहनों के पहियों की हवा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि, दोपहर को परिवहन मंत्री के साथ बैठक में मांगें माने जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई और कैब सेवाएं बहाल कर दी गईं। कैब चालकों की हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर कमलापति और भोपाल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले यात्री परेशान रहे। उन्हें ऑटो बुक कर गंतव्य तक जाना पड़ा।

300 दिन का पोषण आहार देना था, बच्चों को मिला सिर्फ 170 दिन

मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ भाजपा सरकार की नीयत और नीति दोनों सवालों के घेरे में - जीतू पटवारी

भोपाल। प्रदेश में बच्चों के पोषण को लेकर सामने आई भयावह स्थिति पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कुपोषण अब केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलता और संवेदनहीनता का जीवंत प्रमाण बन चुका है।

प्रदेश के सभी 7 पोषण आहार प्लांट बंद पड़े हैं, नई व्यवस्था के लिए अब तक टेंडर तक नहीं हुए हैं। प्रदेश की करीब 97 हजार आंगनवाड़ियों में बच्चों और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को साल में 300 दिन पोषण आहार मिलना चाहिए था, लेकिन जुलाई तक केवल लगभग 170 दिन ही नियमित पोषण आहार मिल पाया। यानी बच्चों के हिस्से का लगभग 130 दिन का पोषण आहार गायब है।

पटवारी ने कहा कि यह स्थिति उस समय सामने आ रही है जब हस्न ।।स्-6 के आंकड़े मध्य प्रदेश की पोषण व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट की दर 31.8, वेस्टिंग 19 और स्टंटिंग 29.3 है। इसके मुकाबले मध्य प्रदेश में अंडरवेट बच्चों की दर 39.7, वेस्टिंग 23.8 और स्टंटिंग 31.4 है। यानी मध्य प्रदेश में हर 10 में लगभग 4 बच्चे कम वजन के हैं और लगभग हर चौथा बच्चा वेस्टिंग से प्रभावित है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि NFHS-5 से NFHS-6 के बीच देश में अंडरवेट और वेस्टिंग के आंकड़ों में सुधार हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों संकेतक बिगड़ गए। प्रदेश में अंडरवेट बच्चों का प्रतिशत 33 से बढ़कर 39.7 और वेस्टिंग 18.9 से बढ़कर 23.8 हो गई। ग्रामीण मध्य प्रदेश में अंडरवेट बच्चों की संख्या 42 तक पहुंच गई है।

सरकार के अपने आंकड़े भी भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हैं

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2025 में विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रदेश में लगभग 1.36 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें 29,830 गंभीर रूप से कुपोषित और करीब 1.06 लाख मध्यम रूप से कुपोषित हैं। प्रदेश की गंभीर एवं मध्यम कुपोषण दर 7.79 बताई गई थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.40 था।

इतना ही नहीं, विधानसभा में सरकार ने यह भी बताया कि आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए महज ?8 प्रतिदिन और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए ?12 प्रतिदिन का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर, प्रदेश में गौशालाओं में एक गाय के आहार के लिए ?40 प्रतिदिन की राशि निर्धारित की गई है।

सवाल सीधा है—जब सरकार एक गाय के चारे पर ?40 खर्च कर सकती है, तो कुपोषित बच्चे के भोजन पर ?8 और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे पर ?12 क्यों?

पटवारी ने कहा कि ?12 में दूध तक नहीं आता, पौष्टिक भोजन तो दूर की बात है। जिस प्रदेश में दूध की कीमत लगभग ?70 लीटर तक पहुंच चुकी है, वहां ?8-12 प्रतिदिन में बच्चे को संतुलित पोषण देने का दावा करना गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ मजाक है। विधानसभा में सरकार की ओर से स्वयं यह स्वीकार किया गया कि वर्तमान राशि कम है और केंद्र से अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।

भाजपा सरकार के लिए बच्चों का पोषण प्राथमिकता नहीं, सिर्फ प्रचार का विषय है

पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार पोषण 2.0, पोषण अभियान और तमाम योजनाओं के नाम पर प्रचार तो खूब करती है, लेकिन जमीन पर बच्चों के निवाले की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है।

यह सिर्फ कुपोषण नहीं है, यह भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं का कुपोषण है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, श्योपुर सहित आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। हस्न ।।स्-6 के अनुसार ग्रामीण मध्य प्रदेश में करीब 42 बच्चे अंडरवेट हैं।

कांग्रेस के सवाल

पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और महिला एवं बाल विकास विभाग से पूछा—

1. जब बच्चों को 300 दिन पोषण आहार देना तय है तो 170 दिन ही क्यों दिया गया?
2. प्रदेश के सभी 7 पोषण आहार प्लांट बंद क्यों हैं?
3. नई व्यवस्था का टेंडर अब तक क्यों नहीं हुआ?
4. बच्चों के हिस्से के 130 दिन के पोषण आहार की भरपाई कौन करेगा?
5. जब हस्न ।।स्-6 में प्रदेश का अंडरवेट आंकड़ा 39.7 और वेस्टिंग 23.8 हो चुका है, तब सरकार की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
6. कुपोषित बच्चे के लिए ?8 और गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए ?12 की राशि में पौष्टिक भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा?
7. सरकार बच्चों के पोषण के लिए राशि बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार से अतिरिक्त पैसा मांगकर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है?

पटवारी ने कहा— भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि मध्य प्रदेश के बच्चों को पोषण चाहिए या सिर्फ भाषण? बच्चों का निवाला 130 दिन गायब है, सातों प्लांट बंद हैं, नई व्यवस्था का टेंडर नहीं हुआ और हस्न ।।स्-6 में कुपोषण के आंकड़े बिगड़ रहे हैं। यह डबल इंजन की सरकार नहीं, बच्चों के पोषण पर डबल विफलता की सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के सवाल पर सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक जवाबदेह बनाएगी। बच्चों के हिस्से का पोषण किसी भी कीमत पर नहीं छीना जाना चाहिए और सरकार को तत्काल सभी पोषण आहार केंद्र शुरू कर 300 दिन का पोषण आहार सुनिश्चित करना चाहिए

प्रदेश के जिला न्यायालयों में होगी 1174 पदों पर सीधी भर्ती

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक ग्रेड-तीन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1174 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधारने की सुविधा 19 सितंबर दोपहर 12 बजे से 21 सितंबर शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस भर्ती से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी।

स्नातक के साथ कम्प्यूटर योग्यता जरूरी

सहायक ग्रेड-तीन पद के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। इसके साथ कम्प्यूटर संबंधी निर्धारित योग्यता भी जरूरी है। अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा भी मान्य होगा। भर्ती विज्ञापन में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी मप्र हाईकोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विनोद/ 19 अगस्त /2026

ओटी टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

भोपाल)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन, संबंधित विभागों और कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ओटी टेक्नीशियन पद की पात्रता शर्तों में किए गए बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने कोर्ट में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के मूल नियमों में बदलाव कर नए अभ्यर्थियों को लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में मिले समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है।

भर्ती के बाद बदले पात्रता नियम

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के समय ओटी टेक्नीशियन पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण-पत्र संबंधी शर्तें तय थीं, अभ्यर्थियों ने उन्हीं के आधार पर आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके बाद शासन ने 10 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पात्रता संबंधी प्रावधान में बदलाव कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता, जिससे वे अभ्यर्थी भी पात्र हो जाएं जो विज्ञापन जारी होने के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला भी दिया गया।

निजी संस्थानों की योग्यता को लेकर आपत्ति नहीं

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि निजी संस्थानों से प्राप्त योग्यता को भविष्य की भर्तियों में मान्यता दिए जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति केवल यह है कि बाद में किए गए संशोधन को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया जा रहा है। इससे मूल विज्ञापन की शर्तों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती की मेरिट लिस्ट 31 मार्च 2026 को जारी हो चुकी थी, जबकि पात्रता संबंधी संशोधन 10 अगस्त 2026 को किया गया। संशोधित प्रावधानों के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है।

मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों पर अंतरिम रोक

मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्मचारी चयन मंडल सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे की नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी।

भोपाल में ही क्यों लागू है कमर्शियल लाइसेंस शुल्क

कमर्शियल लाइसेंस शुल्क का विरोध, व्यापारियों का धरना, बोले

भोपाल। भोपाल में लागू कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए वे आईएसबीटी स्थित निगम दफ्तर पहुंचे और धरना दिया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनरतले व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वे महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से भी मिले। उन्होंने कहा कि सालों से व्यापारी यह टैक्स दे रहे हैं, जबकि प्रदेश में यह टैक्स कहीं भी नहीं वसूला जा रहा है। बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधियों ने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में यह कमर्शियल लाइसेंस शुल्क लागू नहीं है, केवल भोपाल शहर के व्यापारियों पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। व्यापारियों का स्पष्ट सवाल है कि जब प्रदेश के अन्य शहरों में व्यापारियों पर ऐसा शुल्क लागू नहीं है, तो भोपाल के व्यापारियों के साथ यह भेदभावपूर्ण एवं सौतेला व्यवहार क्यों? भोपाल प्रदेश की राजधानी है और यहां का व्यापारिक समुदाय शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे में व्यापारियों को राहत देने के बजाय उन पर अतिरिक्त शुल्क का भार डालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। व्यापारिक संगठनों ने कहा कि यदि प्रदेश के अन्य शहरों में व्यापारिक गतिविधियां बिना इस प्रकार के शुल्क के संचालित हो सकती हैं तो भोपाल के व्यापारियों पर अलग से यह आर्थिक भार डालने का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

शहर की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की बड़ी भूमिका

व्यापारियों ने कहा कि भोपाल का कारोबारी वर्ग शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है। व्यापारी अलग-अलग करों और शुल्क के माध्यम से सरकार को राजस्व भी देते हैं। ऐसे में कारोबार को आसान बनाने और व्यापारियों को राहत देने के बजाय अतिरिक्त शुल्क लगाना उचित नहीं है।

9.26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत... बिल में मिली 20 प्रतिशत तक छूट

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में जुलाई में 9 लाख 26 हजार 737 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ का लाभ मिला। सोलर आवर्स यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर पात्र उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जुलाई में भोपाल रीजन के 7 लाख 59 हजार 792 उपभोक्ताओं को 8 करोड़ 39 लाख 90 हजार रुपए और ग्वालियर रीजन के 1 लाख 66 हजार 945 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 56 लाख 53 हजार रुपए की छूट मिली।

पुरानी पेंशन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगा कर्मचारी मंच

भोपाल । मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश सरकार से राजस्थान सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त एनपीएस धारक कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने की मांग की है। कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राजस्थान सरकार ने राज्य के लाखों एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा। मंच का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश के करीब 4.50 लाख एनपीएस धारक कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग पर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है। इससे एनपीएस धारक कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारी मंच ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से प्रदेशभर के कर्मचारियों का समर्थन जुटाया जाएगा और हस्ताक्षरयुक्त मांग-पत्र सरकार को सौंपकर ओपीएस लागू करने की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। मंच ने सरकार से कर्मचारियों के हित में राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।

60 मीटर ऊंची इमारतें बन सकेंगी, बढ़े हुए एफएआर का भी मिलेगा लाभ

बड़े शहरों में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हाईराइज बिल्डिंगें बनवाएंगे, भूमि विकास नियम में शासन करने जा रहा है महत्वपूर्ण संशोधन

भोपाल। नगर निगम और फायर ब्रिगेड के पास भले ही ऊंची इमारतों की आग बुझाने के लिए फिलहाल कोई साधन ना हो, मगर शहरभर में बहुमंजिला इमारतें अवश्य तनी हुई हैं, जिनमें अब फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए प्रशासन और निगम लगातार जांच करने और सील करने की कार्रवाई कर रहा है। अब भूमि विकास निगम में संशोधन कर अब 60 मीटर ऊंचाई तक की बिल्डिंग बनाने की अनुमति भोपाल-इंदौर जैसे प्रमुख बड़े शहरों में दी जाएगी, जिसके चलते 20 मंजिला तक ऊंची बिल्डिंगें बन सकेंगी, जिसके लिए अतिरिक्त एफएआर का भी लाभ दिया जाएगा।

किसी भी बहुमंजिला इमारत में सामान्य रूप से तीन से साढ़े 3 मीटर की एक फ्लोर रहती है। अभी भोपाल में 8-10 मंजिला इमारतें तो कई बनी हैं, जो हाईराइज कमेटी से मंजूर होती है। वहीं अब वर्टिकल ग्रोथ यानी ऊंचाई में विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मुंबई की तर्ज पर गगनचूंबी इमारतें भी बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल का मास्टर प्लान भले ही अभी अधर में अटका हो और मेट्रो पॉलिटन अथॉरिटी रीजन के ढोल पीछले दो साल से पीटे जा रहे हैं। मगर नए मास्टर प्लान के अते-पते तो नहीं है, साथ ही जो आवश्यक संशोधन मास्टर प्लान से लेकर भूमि विकास नियम में करना है, उसे लेकर भी शासन कोई निर्णय नहीं ले पाता है। अब भूमि विकास नियम में संशोधन कर 60 मीटर ऊंचाई तक की बिल्डिंगों को अनुमति देने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके लिए नियमों में संशोधन चल रहा है। हालांकि शहर में अभी भी इससे अधिक ऊंची इमारतें मौजूद हैं, जिनमें आईटी पार्क से लेकर कई अन्य कॉर्पोरेट और रेसीडेंशियल बिल्डिंगें शामिल हैं। सुपर कॉरिडोर पर ही प्राधिकरण ने जो स्टार्टअप पार्क प्रोजेक्ट बनवाया उसकी ही ऊंचाई ज्यादा है। मगर एमओएस, पार्किंग नॉम्स और अन्य प्रावधानों के चलते उसमें भी संशोधन करना पड़ा, क्योंकि शासन ने नियमों में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी।

20 मंजिला तक इमारतों का निर्माण आसान

अब हाईराइज बिल्डिंगों के निर्माण को आसान करने के लिए भूमि विकास नियम के साथ-साथ एफएआईर में भी राहत देने का प्रस्ताव चल रहा है। अब 15 मंजिल या उससे ऊंची हाईराइज बिल्डिंगों को न्यू नॉर्मल कहा जाएगा और अन्य शहरों में भी 20 मंजिला तक उक्त इमारतों का निर्माण आसान होगा। अभी भोपाल-इंदौर में तो 20 मंजिला से ऊंची इमारतें बन रही है, लेकिन अन्य शहरों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। चूंकि भूमि विकास नियम पूरे प्रदेश में लागू रहता है। इसके चलते 14 साल पुराने नियमों में परिवर्तन कर बिल्डिंग की ऊंचाई, फ्लोर एरिया रेशो सहित अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्ष-2012 के अलावा भूमि विकास नियम 2026 लागू करने की तैयारी है और जो नया प्रस्ताव बनाया है उसमें हाईराइज बिल्डिंगों की ऊंचाई, फ्लोर एरिया रेशो यानी एफएआर और जिस जमीन या भूखंड पर निर्माण होना है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाना है। शासन का कहना है कि प्रदेश के बड़े शहरों में 15 से 20 मंजिला तक ऊंची इमारतों का निर्माण अब पहले की तुलना में आसान हो जाएगा और इसके लिए शासन ने लगभग 200 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे उच्च स्तरीय बैठक के बाद अनुमोदित कर दिया जाएगा। फिलहाल 30 मीटर यानी 10 मंजिल से ऊंची इमारतों के लिए विशेष अनुमति यानी हाईराइज कमेटी से मंजूरी लेना पड़ती है, जिसमें शहर के साथ-साथ पंचायतों के लिए भी अलग-अलग कमेटी बनी है। निगम में हाईराइज कमेटी के प्रमुख निगमायुक्त रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायत में हाईराइज कमेटी के प्रमुख का जिम्मा कलेक्टर निभाते हैं। अभी जो सवा या डेढ़ एफएआर मिलता है उसे बढ़ाकर 3 से 4 करने का प्रावधान भी है। अभी सडक् चौड़ाई या अन्य प्रोजेक्टों के लिए जो मकान-दुकान तोड़े जाते हैं और उसके बदले टीडीआर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका भी इस्तेमाल इन हाईराइज बिल्डिंगों में अतिरिक्त एफएआर के लिए किया जा सकेगा।

टीईटी के नाम पर शिक्षकों से वसूला जाएगा 15 करोड़ शुल्क

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन परीक्षा शुल्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा के लिए 1,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। प्रदेश में करीब 1.50 लाख सेवारत शिक्षक इसके दायरे में आने का अनुमान है। यदि सभी शिक्षक परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो केवल परीक्षा शुल्क के रूप में करीब 15 करोड़ रुपए जमा होंगे। शिक्षक संगठनों ने इस शुल्क को लेकर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग शुरू कर दी है। उनका तर्क है कि ये शिक्षक किसी नई नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में अपनी वर्तमान सेवा में बने रहने के लिए पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में परीक्षा का खर्च

सरकार को उठाना चाहिए।

कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक वर्ग के शिक्षकों के लिए टीईटी की आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से 9 सितंबर तक निर्धारित की है। अभ्यर्थियों को 1,000 रुपए परीक्षा शुल्क के अलावा एमपी ऑनलाइन और कियोस्क का शुल्क भी देना होगा। शिक्षक संगठनों ने इसी शुल्क का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से 26 अगस्त तक दोनों से मुलाकात कर शुल्क माफ करने की मांग रखने का प्रयास किया जा रहा है। संगठनों ने तब तक शिक्षकों से फॉर्म नहीं भरने की अपील भी की है।

1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों पर असर

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में निर्देश दिया था कि प्रदेश में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सेवा में बनाए रखा जाएगा। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के करीब 1.50 लाख शिक्षक परीक्षा के दायरे में आने का अनुमान है। यही वजह है कि शिक्षक संगठन परीक्षा शुल्क को सामान्य भर्ती परीक्षा की फीस से अलग मान रहे हैं।

मानव सुथार की घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया

गॉल । युवा स्पिनर मानव सुथार की घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम ने यहां खेले गये पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंकाई टीम को 165 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही दो मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम को 1- 0 की बढ़त मिल गयी है। भारतीय टीम की जीत में सुथार की अहम भूमिका रही। सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम की सभी उम्मीदों को तोड़ते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दी। इस मैच में श्रीलंकाई टीम को जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला था, इसके जवाब में वह अपनी दूसरी पारी में 206 रन ही बना पायी। इस प्रकार उसे 165 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

सुथार ने पहली पारी में भी चार विकेट लिए थे। इस प्रकार उन्होंने मैच में कुल 10 विकेट लिए। इस महत्वपूर्ण जीत के साथ ही भारत ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में 12 अंक हासिल किए हैं, जिससे टीम की फाइनल खेलने की उम्मीदों को नया बल मिला है।

मैच के अंतिम दिन लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 4 विकेट पर 84 रनों से आगे खेलना शुरु किया। भारतीय टीम द्वारा दिए गए 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए धनंजय डी सिल्वा ने 59 रन रन और सोनल दिनुशा ने 84 रन बनाये। इन दोनो ने पांचवें विकेट के लिए साझेदारी कर भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया पर सुथार की सटीक गेंदबाजी के सामने ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाये। इनके आउट होते ही श्रीलंकाई पारी सिमट गयी। लंच के बाद के सत्र में श्रीलंका की टीम 206 रन पर ही आउट हो गयी।

वहीं इससे पहली भारतीय टीम ने दूसरी पारी में ऋषभ पंत के 69 गेंदों पर तेजी से बनाये 66 रनों की सहायता से दूसरी पारी में 193 रन बनाये और श्रीलंका के सामने 372 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा गया। श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या और असिथा फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट हासिल किए, जबकि लाहिरू कुमारा ने भी महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत के निचले क्रम को ज्यादा रन बनाने से रोका।

वहीं भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी, वहीं केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन का योगदान दिया था। जवाब में, श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमट गई थी। इससे भारतीय टीम के पास 178 रनों की अच्छी खासी बढ़त थी।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नंबर एक पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया

नई दिल्ली । यहां जारी दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी20 के तीसरे सत्र में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नंबर एक पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है। वहीं अन्य कोई भी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पायी है। वहीं कुछ टीमें अंतिम चार में जगह बनाने की दौड़ में हैं। इस सत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन सेंट्रल दिल्ली किंग्स का रहा है। किंग्स ने अब तक अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अब तक खेले गए 9 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है और वह 16 अंक लेकर अंक तालिका में नंबर एक पर बनी हुई है।

वहीं, कुछ टीमों के लिए यह सीजन अच्छा नहीं रहा है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स से हारने के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स के प्लेऑफ्स में पहुंचने की संभावनाएं समाप्त हो गयी हैं। गत वर्ष की विजेता राइडर्स इस बार 8 में से केवल एक मैच ही जीती है और उसके केवल 3 अंक हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली टाइगर्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो गयी है, वह इस सीजन में केवल एक मैच जीती है और उनके खाते में केवल 2 अंक हैं। इन दोनों टीमों के अभी दो-दो मुकाबले बाकी हैं, लेकिन इनका परिणाम इनकी प्लेऑफ की संभावनाओं पर कोई असर नहीं डालेगा।

अंक तालिका में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बाद, पुरानी दिल्ली 6 टीम दूसरे स्थान पर है, जिसने 9 मैचों में 5 जीत और एक मैच का परिणाम नहीं आया। जिससे उसके 11 अंक हैं। तीसरे स्थान पर आउटर दिल्ली वॉरियर्स है, जिनके भी 11 अंक हैं, हालांकि उन्होंने पुरानी दिल्ली से एक मैच कम खेला है। इन दोनों टीमों के भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने की काफी संभावनाएं हैं। चौथे स्थान पर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम है, जिसने 8 में से 4 मैच जीते हैं और एक मैच का परिणाम नहीं आया। जिससे उनके खाते में 9 अंक हैं। पांचवें और छठे स्थान पर क्रमश: नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर और वेस्ट दिल्ली लायंस टीमें हैं, जिनके पास 7-7 अंक हैं। इन टीमों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना अभी भी संभव है, लेकिन उन्हें अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे।

2004 में हुए पाकिस्तान दौरे पर टीम इंडिया पर हमले का था खतरा

नई दिल्ली। भारतीय टीम पर साल 2004 में हुए पाकिस्तान दौरे के दौरान हमले का खतरा था पर एक खुफिया जानकारी से ये टल गया था। अब 22 साल के बाद ये खुलासा उस समय भारतीय सुरक्षा दस्ते के अधिकारी रहे यशोवर्धन आजाद ने अपनी प्रकाशित पुस्तक 'पुलिसिंग द रिपब्लिक- एन इनसाइड व्यू ऑफ हाउ इंडिया फाइट्स करप्शन एंड क्राइम, एंड प्रोटेक्ट्स राइट्स' में किया है। ये दौरा अपने तय समय में हुआ। ये मार्च में कराची में वनडे मैच के साथ शुरू हुआ यह दौरा अप्रैल तक चला।

आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कराची में टेस्ट मैच की मेजबानी के अनुरोध को सुरक्षा कारणों से ठुकरा दिया था। मुशर्रफ चाहते थे कि 2004 के भारत दौरे की शुरुआत कराची में टेस्ट मैच के साथ हो, जिसके लिए उन्होंने भारत से अनुमति भी मांगी थी।

गौरतब है कि आजाद उस तीन सदस्यीय सुरक्षा दल के प्रमुख थे, जिसने पाकिस्तान के सभी क्रिकेट स्थलों का विस्तृत सुरक्षा जायजा लिया था। उनकी टीम ने दौरे की सिफारिश तो की, लेकिन कराची और पेशावर जैसे शहरों में टेस्ट मैच न कराने की स्पष्ट सलाह दी थी। सुरक्षा दल का मानना था कि इन जगहों पर खतरे की आशंका अधिक थी और लंबे समय तक टीम के रुकने से जोखिम काफी बढ़ सकता था। दल ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर को टेस्ट मैचों के लिए सुरक्षित माना था।

अपनी रिपोर्ट सौंपने के कुछ समय बाद आजाद को आडवाणी का फोन आया, जिन्होंने सीधा सवाल किया, कराची में क्या हम टेस्ट मैच नहीं करा सकते हैं?卐 आजाद ने उन्हें पूरी स्थिति समझाते हुए बताया कि सुरक्षा कारणों से कराची और पेशावर को सूची से बाहर रखा गया है। आडवाणी ने उनसे सुरक्षा आकलन पर दोबारा विचार करने और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के सामने मामले को रखने को कहा।

इस मामले में गहराई से जानने पर आजाद को विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान मामलों के तत्कालीन संयुक्त सचिव अरुण सिंह ने बताया कि कराची में टेस्ट मैच कराने का अनुरोध स्वयं राष्ट्रपति मुशर्रफ की ओर से आया था, जिसे तत्कालीन विदेश मंत्री के माध्यम से भारत तक पहुंचाया गया था। आजाद ने लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी चाहते तो सुरक्षा अधिकारियों के फैसले को आसानी से पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा संबंधी सलाह को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सुरक्षा दल द्वारा मंजूर कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। मार्च में कराची में वनडे मैच के साथ शुरू हुआ यह दौरा अप्रैल तक चला।

ऋषभ डब्लयूटीसी में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक के बाद एक नये रिकार्ड बनाते जा रहे हैं। ऋषभ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में अर्धशतक लगाने के साथ ही विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्लयूटीसी) में सबसे अध्रिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज होने की उपलब्धि भी हासिल की है। इससे पहले ये रिकार्ड सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा के नाम था। ऋषभ ने केवल 69 गेंदों में ही 8 चौके और 2 छक्के लगाकर 66 रन बनाये। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे किये।

वह पहली पारी में 39 रन ही बना पाये थे पर दूसरी पारी में अर्धशतक लगाते ही उनके डब्ल्यूटीसी में 2885 रन हो गये। वहीं शुभमन अब 2867 रनों के साथ ही दूसरे जबकि रोहित 2716 रनों के साथ ही तीसरे नंबर पर खिसक गये हैं।

हालांकि डब्यलूटीसी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की शीर्ष 10 सूची में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। इस सूची पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का ही कब्जा है। एशियाई बल्लेबाजों में, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो शीर्ष 10 में अपनी जगह बना पाए हैं; वे इस सूची में सातवें पायदान पर हैं। वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट 77 मैचों में 6651 रनों के साथ इस सूची में नंबर एक स्थान पर हैं।

ऋषभ ने अब तक डब्लयूटीसी के 41 मैचों की 73 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए कुल 2885 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 146 रन रहा है, जबकि बल्लेबाजी औसत 41.81 का प्रशंसनीय है। कुल 3870 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 74.54 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं। उनके बल्ले से 6 शानदार शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 314 चौके और 80 छक्के भी लगाये हैं। उनसे ज्यादा छक्के सिर्फ इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 88 छक्के लगाये हैं।

फॉर्मूला ई भारत में वापसी को उत्सुक, शहरों को इच्छाशक्ति दिखानी होगी - अल्बर्टो लोंगो

मुम्बई । भारत में एक बार फिर रेसिंग के शौकीनों को फॉर्मूला ई के मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। फॉर्मूला ई के सह-संस्थापक अल्बर्टो लोंगो ने कहा है कि ऑल-इलेक्ट्रिक विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जा सकती है पर इसके लिए किसी भारतीय शहर को मेजबानी के लिए दावेदारी करनी होगी। गौरतलब है कि फॉर्मूला ई रेस की हैदराबाद ई-प्री के साथ भारत में शुरुआत हुई थी पर तेलंगाना में सरकार बदलने के साथ ही इसे दी गयी इजाजत रद्द कर दी गयी थी। लोंगो ने जोर दिया कि फॉर्मूला ई अब भी भारत में काफी संभावनां देखती है और अवसरों की तलाश में है।

गौरतब है कि भारत ने हैदराबाद में ई-प्री के साथ फॉर्मूला ई के वैश्विक कैलेंडर पर अपनी शुरुआत की थी, जिसने देश में मोटरस्पोर्ट्स के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। यह रेस वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती पहचान और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। हालांकि, तेलंगाना में सरकार में आये बदलाव के बाद इस रेस को भी बंद कर दिया गया था। वहीं लोंगो ने इस स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, हम भारत वापस पहुंचना चाहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अभी इसको लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। फॉर्मूला ई के लिए यह इतना महत्वपूर्ण बाजार है कि हम निश्चित रूप से वहां वापस जाना चाहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वापसी के लिए फॉर्मूला ई प्रतियोगिता की मेजबानी करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। यह स्पष्ट संकेत है कि चैंपियनशिप सक्रिय रूप से भारत में एक नए मेजबान की तलाश में है जो आवश्यक समर्थन और बुनियादी ढांचा प्रदान कर सके।

यशस्वी ने डिकवेला को आईपीएल अनुबंध का लालच देकर छक्का लगाने उकसाया

गॉल । भारत और श्रीलंका के बीच हुए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन स्लेजिंग भी देखने को मिली। भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंकाई विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को आईपीएल अनुबंध का लालच देकर इतना उकसाया कि वह अपनी एकाग्रता खोकर कैच दे बैठे1 डिकवेला जब खेल रहे थे तो यशस्वी उन्हें उकसाकर कह रहे थे कि अगर तुममें हिम्मत है तो छक्का मारो! अगर तुम छक्का लगाआगे तो तो मैं तुम्हें आईपीएल अनुबंध दिला दूंगा। ये बातचीत स्टंप माइक में भी रिकॉर्ड हो गई, जिससे मैदान पर मौजूद दोनों खिलाड़ियों के बीच की बातें सामने आई हैं।

यश्स्वी के लगातार उकसाने और आईपीएल अनुबंध के लालच से डिकवेला अपना धैर्य खो बैठे और एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच हो गये। उनके आउट होने के तुरंत बाद, जायसवाल ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उनसे कहा, 'तुममें हिम्मत नहीं है!'

यह मामला श्रीलंकाई दूसरी पारी का है जो पांचवें दिन खेली जा रही थी।। पांचवें दिन की सुबह श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिन आक्रमण का शुरु में डटकर सामना किया था। कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलकर भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि स्पिनर रवींद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को कैच आउट करवाकर इस महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ा। इस विकेट के गिरने के बाद ही अनुभवी निरोशन डिकवेला क्रीज पर आए थे, जिनसे उम्मीद थी कि वे बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को स्थिरता प्रदान करेंगे। डिकवेला के क्रीज पर आते ही यश्स्वी ने उनपर दबाव बनाना शुरु कर दिया। डिकवेला ने शुरूआत में स्लिप फील्डर को जवाब देते हुए आत्मविश्वास से कहा, 'हां, मैं छक्का मारूंगा।' लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार बाउंसर फेंककर उन पर दबाव बनाए रखा। डिकवेला ने इस दबाव में आकर तेज गेंदबाज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई।

सचिन के नाम है सबसे अधिक टेस्ट स्थलों पर खेलने का रिकार्ड

मुम्बई । महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकार्ड है पर इसमें एक रिकार्ड सबसे अलग है। सचिन अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंनं अपनी करियर में 59 अलग-अलग मैदानों पर मैच खेले हैं। सचिन को संन्यास लिए एक दशक से अधिक हो गया पर कोई भी बल्लेबाज उनके इस रिकार्ड के करीब नहीं पहुंच पाया है। सचिन ने अपने 24 साल के लंबे टेस्ट करियर में कुल 59 विभिन्न मैदानों पर मुकाबले खेले, जो दुनिया के किसी भी अन्य खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है। यह उपलब्धि इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का 140 साल से भी अधिक पुराना इतिहास रहा है, जिसमें कई महान खिलाड़ियों ने दशकों तक क्रिकेट खेला है पर उनके नाम भी ये रिकार्ड नहीं है।

सचिन का यह कीर्तिमान उनकी अद्वितीय खेल भावना और लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर बने रहने का प्रमाण है। अपने लगभग 24 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने दुनिया के लगभग हर बड़े क्रिकेट खेलने वाले देश में अपने बल्ले का कमाल दिखाया है, जिसने उन्हें यह अनोखा मुकाम हासिल करने में मदद की। एक खिलाड़ी के लिए इतने लंबे समय तक फिटनेस और फॉर्म बरकरार रखना और इतने व्यापक स्तर पर अलग-अलग हालातों में खेलना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे सचिन ने पूरा किया। यही कारण है कि सचिन का यह रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाये।

इस खास सूची में सचिन के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल का नाम आता है, जिन्होंने 58 अलग-अलग वेन्यू पर टेस्ट मैच खेले हैं, यानी सचिन से मात्र एक स्थल पीछे वह रहे। वहीं भारत के राहुल द्रविड़ ने 55 विभिन्न मैदानों पर खेलकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट 52 वेन्यू के साथ चौथे स्थान पर काबिज हैं। इसके अलाव भारत के पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण और महान स्पिनर अनिल कुंबले ने भी 51-51 अलग-अलग मैदानों पर टेस्ट खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर ने 51 स्थलों पर खेला हैं। 50 से अधिक वेन्यू पर खेलने वाले अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने शामिल हैं, जिन्होंने 50-50 मैदानों पर टेस्ट मुकाबले खेले हैं। यह रिकॉर्ड केवल आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सचिन के वैश्विक प्रभाव और खेल के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनका ये रिकार्ड भी उभरते हुए क्रिकेटरों को प्रेरित करेगा।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले में 6-1 से हराया

एमस्टेलवीन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इससे पूल डी में भारतीय टीम ने अपनी स्थिति भी मजबूत की है। दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ इस में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए विरोधी टीम पर दबाव बना दिया। वहीं इससे पहले के मैच में भारती टीम का मुकाबला चीन से 2-2 से बराकर रहा थ। दो मैचों में उसके कुल चार अंक हो गए हैं और गोल अंतर के आधार पर वह पूल में शीर्ष पर पहुंच गयी है। अब भारतीय टीम का पूल का अपन अंतिम मुकाबला गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ होगा।

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम पर मैच की शुरुआती मिनटों से ही अपने हमले शुरु कर दिये। इसका लाभ भी उसे मिला सातवें मिनट में ही भारत को अपना पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला पर दीपिका उसे गोल में नहीं बदल पायी। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बाद और तेजी दिखायी इससे 11वें मिनट में साक्षी राणा के पास पर सुनेलिता टोप्पो ने गोल दागकर भारतीय टीम को 1-0 से आगे कर दिया।

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भी भारतीय टीम ने विरोधी पर दबाव बनाये रखा। परिणाम स्वरुप 17वें मिनट में भारतीय टीम को फिर पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिस पर गोल दागने में नवनीत कौर ने कोई गलती नहीं की और भारत का स्कोर 2-0 हो गया। 25वें मिनट में भारतीय टीम ने एक और गोल दागकर अपनी बढ़त को 3-0 कर जीत पक्की कर दी। इस बार दीपिका से छिटककर निकली गेंद को गोल में डालने में सुशीला चानू ने कोई गलती नहीं की।

भारतीय टीम की बढ़त का सिलसिला तीसरे क्वार्टर में भी जारी रहा। दिपिका ने 38वें मिनट में एक मैदानी गोल कर भारतीय टीम की ओर से चौथा गोल दाग दिय। इसके बाद अगले दो मिनट में ही भारतीय टीम ने दो और गोल दाग दिये। 44वें मिनट में, नेहा से मिली हवाई गेंद पर लालरेम्सियामी ने जबरदस्त शॉट लगाकर गोल दाग दिया। इसके तुरंत बाद, 45वें मिनट में साक्षी राणा ने छठा गोल किया।

दूसरी ओर दक्ष्रिण साउथ अफ्रीका ने भी अंत तक प्रयास किया। 55वें मिनट में उसकी ओर से कायला डी वाल ने पेनाल्टी कॉर्नर से गोल कर दिया। इससे सकार 6-1 हो गया और कोई और गोल नहीं होने से उसे हार का सामना करन पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने चयनकर्ताओं पर उठाये सवाल

मेलबर्न । पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट में टीम को मिली हार पर निराशा जताते हुए कहा है कि अगर ये सीरीज बचानी है ते चयनकर्ताओं को टीम के सेटअप में भी बदलाव करने होंगे। दोनो ही टीमों के दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 अगस्त से शुरु होगा। उन्होंने कहा कि जेक वेदरल्ड को दूसरे टेस्ट से बाहर किया जाना ही पर्याप्त नहीं है। चैपल ने कहा कि अगर आप शुरु में ही गलत खिलाड़ियों को शामिल करते हैं, तो आप अपने को परेशानी में डाल सकते हैं। उनके अनुसार, चयनकर्ताओं ने अपने फैसलों से यह दिखाया है कि वे चीजों को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझते जितना उन्हें समझना चाहिए। मेरे विचार से, चयनकर्ताओं ने ही से ये परेशानी बढ़ायी है। अब उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता भी स्वयं ही तलाशना होगा।

वहीं चैपल ने कहा कि युवा सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास की भी टीम में वापसी होनी चाहिये। उन्हें पिछले साल वेस्टइंडीज के खराब दौरे के बाद बाहर कर दिया गया था। इस पूर्व कप्तान के अनुसार कॉन्स्टास को रेनशॉ के साथ पारी की शुरुआत करनरी चाहिये। इससे ट्रैविस हेड मध्यक्रम में खेल सकेंगे। उन्होंने मार्नस लाबुशेन को नंबर तीन पर खिलाने के फैसले की भी आलोचना की। चैपल के मुताबिक, लाबुशेन पिछले काफी समय से संघर्ष करते रहे हैं, ऐसे में उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ उतारना चाहिये।

उन्होंने ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को नंबर सात पर बल्लेबाजी कराने के फैसल को भी गलत बताया । उन्होंने कहा कि वह शतक लगाने वाला बल्लेबाज है पर उसे सातवें नंबर पर उतारा जा रहा है जिससे कोई लाभ नहीं होगा। युवा खिलाड़ियों कैंपबेल केलावे और ओलिवर पीक को लेकर चैपल ने कहा कि ये दोनो अभी टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं बने हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने कार्यप्रणाली के नियमों में किया बड़ा बदलाव

सीएम बदल सकेंगे मंत्रियों का फैसला

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शासन के कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अब सार्वजनिक हित से जुड़े किसी मामले में मुख्यमंत्री किसी मंत्री के फैसले को बदल सकते हैं या उसे रद्द भी कर सकते हैं. हालांकि, अर्ध-न्यायिक मामलों में मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं होगा. किसी मंत्री के फैसले में बदलाव करने पर मुख्यमंत्री को उसका कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से महाराष्ट्र शासन कार्य संचालन नियम, 2026 में संशोधन किया गया है. नए नियम लागू होने के साथ ही सरकार के भीतर मुख्यमंत्री के अधिकारों को और स्पष्ट किया गया है. प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव को भी विभागों से जानकारी और दस्तावेज मांगने के अधिकार दिए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री राज्य के किसी भी विभाग की फाइल या जरूरी दस्तावेज मंगा सकते हैं. संबंधित मंत्री और विभाग के सचिव को ये दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. इसी तरह मुख्य सचिव भी किसी विभाग के सचिव से आवश्यक जानकारी और दस्तावेज मांग सकेंगे. किसी सरकारी नियम की व्याख्या को लेकर अगर विवाद या भ्रम की स्थिति बनती है, तो संबंधित मामला मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा.

वित्तीय फैसलों पर भी नई व्यवस्था

सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले या सरकारी राजस्व में छूट देने वाले फैसलों के लिए वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी. जमीन, राजस्व, खनिज और वन अधिकारों से जुड़े मामलों में छूट, लीज या लाइसेंस देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसके अलावा नया कानून बनाने, मौजूदा कानून में संशोधन करने या नया नियम लागू करने से पहले उसका मसौदा कानून एवं न्याय विभाग को जांच के लिए भेजना जरूरी होगा.

केंद्र या दूसरे राज्यों से विवाद की स्थिति में तुरंत जानकारी

ऐसे किसी फैसले से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद की स्थिति बनने की आशंका हो, तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को तत्काल देनी होगी. सरकार जरूरत के मुताबिक मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में विशेष अधिकार प्राप्त समितियां भी गठित कर सकेगी.

2022 के हाईकोर्ट फैसले के बाद बदलाव

मुख्यमंत्री के मंत्रियों के फैसलों में हस्तक्षेप के अधिकार को लेकर 2022 में मामला सामने आया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती बैंक की भर्ती से जुड़े फैसले पर हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सवाल उठाए थे. अदालत ने कहा था कि मुख्यमंत्री को मंत्री के फैसले में हस्तक्षेप करने या उसे बदलने का अधिकार नहीं है. अब सरकार ने शासन के कामकाज के नियमों में संशोधन कर मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया है. नए नियमों के तहत सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री अब मंत्रियों के फैसलों में बदलाव या उन्हें रद्द कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कारण लिखित रूप में बताना होगा.

एनटीए का बड़ा फैसला : परीक्षा सुरक्षा के लिए 600 विशेषज्ञ हटाए

केंद्रीय मंत्री को बताया, पूरी टीम में बदलाव

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपनी परीक्षाओं की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने अपनी पूरी परीक्षा टीम में व्यापक बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत अब तक पेपर सेट करने में मदद कर रहे 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। यह कदम शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठकों के बाद उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने निर्देशों में कहा कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और संबंधित बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए जाएं।

एनटीए, जो जेईई-मैंस, नीट-यूजी, क्लेट और यूजीसी-नेट जैसी प्रमुख परीक्षाओं का संचालन करती है, ने अपनी प्रक्रियाओं को अधिक पुख्ता बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इन उपायों से अवगत कराया। अब परीक्षा के पेपर की जांच-पड़ताल को और मजबूत करने के लिए एक चार-स्तरीय प्रश्न-पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी। अगले दो से तीन हफ्तों में 20 से 25 नए अधिकारियों को भी एजेंसी में शामिल किया जाएगा, और भविष्य की नियुक्तियों पर विचार हो रहा है। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर एनटीए अपने वर्तमान ओखला कार्यालय को मिंटो रोड स्थित एक नए, अधिक सुरक्षित परिसर में स्थानांतरित करेगा। नई जगह पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की टीमों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जोशी ने एनटीए को अपनी सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का ऑडिट करने और एक महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है।

तमिलनाडु सरकार के दो अहम फैसले : तीसरे बच्चे पर महिलाओं को मातृत्व अवकाश 365 दिन

चेन्नई,। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिसमें से एक सामाजिक कल्याण से जुड़ी है और दूसरी ने व्यापक विवाद उत्पन्न किया था। राज्य की विजय सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाले मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने का निर्णय किया है, जो पहले दो बच्चों के लिए मिलने वाले अवकाश के बराबर है। विजय सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने राज्य विधानसभा को संबोधित कर बताया कि यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली नीति के अनुरूप है। यह कदम तब आया है जब राज्य में मातृत्व अवकाश की अवधि को पहले भी कई बार बढ़ाया गया है। 2011 में छह महीने, 2016 में नौ महीने और जुलाई 2021 में एक साल किया गया। अब, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, उन्हें भी पूर्ण वेतन के साथ एक साल का मातृत्व अवकाश मिलेगा, जिसके लिए विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किए जाएँगे।

हालांकि, विजय सरकार का एक और कदम व्यापक आलोचना का शिकार हुआ, जिसके बाद तमिलनाडू सरकार को वापस लेना पड़ा। 14 अगस्त को एक अत्यंत ज़रूरी निर्देश जारी किया गया था, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और ज़िला प्रशासन को छात्रों को वामपंथी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

पश्चिम बंगाल में दो दिन में दो होटलों में लगी आग से 18 की मौत, मचा हड़कंप

-कई मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज कराने भारत आए थे, जांच शुरु

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में लगातार दो बड़े होटलों में अग्निकांड से हड़कंप मच गया है। कोलकाता और बीरभूम जिले के धार्मिक स्थल तारापीठ में हुई अलग-अलग आग की दुर्घटनाओं में कुल 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग दोनों मामलों में होटल प्रबंधनों द्वारा फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की गहन जांच कर रहे हैं। होटल में ठहरे कई मेहमान बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। बचाव दल मौके पर पहुंचे और इमारत से कई लोगों को बाहर निकाला। रात 3 बजे के बाद, 9 लोगों को बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर विभाग ने बताया कि सभी मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए शहर में आए थे। अधिकारी इन आरोपों की जांच कर रहे हैं कि होटल में आग से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय और उचित इंतज़ाम नहीं थे। अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सही कारण का पता नहीं लगाया है। जांच जारी है। कोलकाता में आग की यह घटना बंगाल के बीरभूम ज़िले के एक होटल में लगी आग के ठीक एक दिन बाद हुई है। सोमवार को तड़के करीब 4 बजे तारापीठ में चार मंज़िला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई, जब ज़्यादातर मेहमान सो रहे थे। आग की लपटें दूसरी मंज़िल तक फैल गईं, जबकि घने धुएं ने इमारत के ऊपरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई मेहमान अपने कमरों में फंस गए। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें मेघालय के एक परिवार के 5 सदस्य भी शामिल थे। पुलिस ने होटल के मालिक कल्याण पाल समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई होटल में आग से सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच के तहत की गई है।

घटना के समय होटल में 43 लोग ठहरे थे। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती मेडिकल जांच के बाद 34 मेहमानों को छुट्टी दे दी गई, जबकि अस्पताल में इलाज करा रहे एक घायल व्यक्ति की बाद में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। कई मेहमान तीर्थयात्री थे जो पवित्र श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को पूजा-अर्चना करने के लिए तारापीठ आए थे।

मिलावट पर तुकाराम को सीएम फडणवीस का खुला समर्थन, जारी रहेगा एक्शन

मुंबई,। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अभियान को अपना खुला समर्थन दे दिया है। उन्होंने एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे की अगुवाई में जारी कार्रवाई पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देकर कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों से लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है, इसलिए सख्त कार्रवाई बहुत जरुरी है।

मई में पदभार संभालने के बाद से, मुंढे के नेतृत्व में एफडीए टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की है, नोटिस जारी किए हैं और कई प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित किए हैं। हालांकि, उनकी कार्रवाई के तरीकों को लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं। आलोचकों का आरोप है कि मुंढे ने जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती है, जहां प्रतिष्ठानों को सुधार का मौका दिए बिना ही स्टॉक जब्त करने या दुकानें बंद करने जैसे कदम उठाए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एफडीए कमिश्नर मुंढे को मच्छर को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी। इस बीच, तुकाराम मुंढे ने हाल ही में विमल इलायची के विज्ञापन में दिख रहे अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एफडीए कमिश्नर मुंढे का दावा है कि यह विज्ञापन महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पान मसाला के सरोगेट प्रचार के दायरे में आता है, जहां गुटखा और तंबाकू भी प्रतिबंधित हैं। तीनों अभिनेताओं से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। एफडीए कमिश्नर मुंढे ने स्वीकार किया कि इसतरह मामलों में कार्रवाई पहले भी शुरू की जा सकती थी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में बना था और संबंधित विज्ञापन नियम 2018 में जारी होकर जुलाई 2019 से लागू हुए थे।

जनगणना के नाम पर एनआरसी?

नई दिल्ली। भारत में जनगणना महज आबादी की गिनती नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर समझने का सबसे बड़ा माध्यम है। आगामी जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों के दायरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है, क्या जनगणना की प्रक्रिया में सरकार नागरिकता की जांच की दिशा मे आगे बढ़ रही है?

परंपरागत रूप से जनगणना में परिवार के सदस्यों की संख्या, आवास, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, शौचालय, रसोई गैस और इंटरनेट जैसी बुनियादी जानकारियां जुटाई जाती हैं। लेकिन अब आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, बैंक खातों और माता-पिता के जन्म स्थान से जुड़े सवालों को लेकर इस तरह की आशंकाएं बन रही हैं।

सबसे अधिक विवाद माता-पिता से संबंधित जानकारी को लेकर है। लोगों का तर्क है, दशकों पहले जन्मे माता-पिता के जन्मस्थान या जन्मतिथि का प्रमाण जुटाना कई परिवारों के लिए बेहद कठिन हो सकता है। खासकर विभाजन से पहले जन्मे लोगों के मामले में यह सवाल और जटिल हो जाता है। उस समय आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं अस्तित्व में नहीं थीं।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है। जनगणना का उद्देश्य आबादी और सामाजिक-आर्थिक आंकड़े जुटाना है। जनगणना संबंधी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। इसके बावजूद विपक्ष और नागरिक अधिकार समूहों की चिंता है, इतने विस्तृत सवाल भविष्य में नागरिकता से जुड़े किसी दूसरे तंत्र के लिए आधार बन सकते हैं। यही वजह है कि जनगणना और एनआरसी के बीच संभावित संबंध को लेकर बहस तेज हो गई है। बेहतर और व्यापक डेटा से सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, वहीं आलोचकों का सवाल है, निजी और पहचान संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल भविष्य में किस उद्देश्य से होगा।

सीएम विजय का ऐलान : हर विधायक को मिलेगी नई कार

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं तथा जरूरतों का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में रहना जरूरी है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वाहन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सरकार का यह फैसला विधानसभा में विधायकों के लिए वाहनों और जरूरी लॉजिस्टिक्स की सुविधा का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है। वीसीके विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में कहा था कि यदि विधायकों को जरूरी संसाधन और वाहन उपलब्ध नहीं होंगे तो वे अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से विधायकों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री विजय ने विधायक के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों के लिए नई कार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहन सुविधा मिलने से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और जनता से सीधे संवाद के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

जनता से संपर्क में आसानी होगी

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार की ओर से सभी विधायकों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आने-जाने वाले विधायकों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। विधायक नियमित रूप से अपने क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में तेजी ला सकेंगे। विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में अपने क्षेत्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए वाहनों को जरूरी सुविधा बताया था। उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री विजय द्वारा लिया गया यह फैसला सरकार और विधायकों के बीच बुनियादी संसाधनों को लेकर उठाए गए मुद्दे के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

बांग्लादेश ने भारत से लगाई गुहार

बिजनेस वीजा फास्ट ट्रैक करने की मांग

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है. बांग्लादेश ने भारत से अपने नागरिकों के लिए बिजनेस वीजा जल्दी जारी करने की मांग की है. ढाका का कहना है कि दोनों देशों के कारोबारी जितनी आसानी से एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश के मौके उतने ही बढ़ेंगे. बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने ढाका में एक कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी कारोबारियों के लिए भारत का बिजनेस वीजा तेजी से जारी होना चाहिए, ताकि वे ज्यादा बार भारत आ-जा सकें. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के निजी क्षेत्र और कारोबारी समुदायों के बीच बातचीत को और बढ़ाने की जरूरत है. बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत के साथ ऐसा आर्थिक साझेदारी मॉडल बने, जिसका फायदा दोनों देशों को मिले. शमा ओबैद इस्लाम ने व्यापार में आने वाली कई दूसरी दिक्कतों का भी जिक्र किया. इनमें गैर-टैरिफ बाधाएं, सामान की गुणवत्ता और टेस्टिंग से जुड़ी समस्याएं, कागजी प्रक्रिया में देरी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं. उनका कहना है कि इन अड़चनों को दूर करने से दोनों देशों के बीच सामान और सेवाओं की आवाजाही आसान होगी।

पटना में राजभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव हिरासत में

पटना। बिहार में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। आरजेडी ने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक तथा बेरोजगारी के खिलाफ यह मार्च निकाला था। पार्टी ने पिछले महीने सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए मार्च कर रही थी, लेकिन सरकार इससे डर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी बेरोजगारी कम करने, पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते और छात्रों के अधिकारों की आवाज उठाते रहेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र अपने अधिकारों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने सिवान के जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित करने की मांग दोहराई और कहा कि पार्टी तथा बिहार की जनता अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटेगी।

सिंहगढ़ किले पर कपड़ों को लेकर बवाल, पर्यटकों से मारपीट का आरोप, 9 लोगों पर केस

पुणे (ईएमएस)। महाराष्ट्र के पुणे स्थित ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर विवाद के बाद मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने खुद को किला संरक्षण समिति का सदस्य बताते हुए पर्यटकों के पहनावे पर आपत्ति जताई और करीब दो घंटे तक उनके साथ मारपीट और डराने-धमकाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, विवाद 16 अगस्त को उस समय शुरू हुआ, जब सिंहगढ़ किले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। एक परिवार की 8 वर्षीय बच्ची के शॉर्ट्स पहनने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद बहस बढ़ गई और एक युवक के साथ मारपीट की गई। धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि अन्य पर्यटकों को भी कथित तौर पर घेरकर उनके कपड़ों को लेकर सवाल किए गए। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ भी बदसलूकी की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब दो घंटे तक चले घटनाक्रम से किले में मौजूद पर्यटकों के बीच दहशत फैल गई और कई लोग बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।

आरएसएस प्रमुख की अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन यात्रा पर कांग्रेस का आरोप

आईआईटी डायरेक्टर्स को दी गई युवाओं को जुटाने की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ आईआईटी निदेशकों से उनके संस्थानों के पूर्व छात्रों से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि वे अमेरिका में आरएएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे।

भागवत का यह दौरा प्रवासी भारतीयों से जुड़े स्थानीय संगठनों और संस्थाओं के निमंत्रण पर आयोजित किया जा रहा है। आरएसएस ने कहा है कि भागवत का यह दौरा संगठन के शताब्दी वर्ष के दौरान हो रहा है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पहले बताया था कि भागवत 25 अगस्त से इन तीनों देशों की यात्रा करेंगे। उन्हें विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय से जुड़े संगठनों और संस्थाओं ने आमंत्रित किया है। भागवत का यह विदेश दौरा आरएसएस के शताब्दी समारोह के बीच हो रहा है। इस दौरान भारतीय संस्कृति, समाज और आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर समुदाय के लोगों के साथ बातचीत होने की उम्मीद है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे। आरएसएस के मुताबिक, यह दौरा संगठन के शताब्दी वर्ष के दौरान हो रहा है। भागवत को इन देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने आमंत्रित किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पहले बताया था कि भागवत की यात्रा के दौरान वे विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे।

कांग्रेस ने आईटीटी को लेकर उठाया सवाल

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दावा किया कि अमेरिका में भागवत के कार्यक्रमों में आईटीटी के पूर्व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ आईटीटी निदेशकों से संपर्क करने को कहा गया है।

पुलिस द्वारा आरोपियों के वीडियो-फोटो पोस्ट करना निजता के अधिकार का उल्लंघन?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और कई राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। इस याचिका में पुलिस पर आरोप है कि वे गिरफ्तार आरोपियों के वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके उनके निजता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक अपमान और मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जनहित याचिका दायर करने वाले हेमेंद्र पटेल ने वकील गोपाल शंकरनारायणन के जरिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच को बताया कि अक्सर पुलिस अपने आधिकारिक हैंडल पर ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट करती है जिनमें आरोपी हथकड़ी पहने, रस्सियों से बंधे, डंडों से पीटे जाते हुए और दूसरे तरह के दुर्व्यवहार का शिकार होते हुए दिखते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब आरोपियों को सबके सामने घुमाया जाता है और उन्हें चलने में मुश्किल होती है, तो यह कस्टडी में टॉर्चर का देता है। आरोपियों की पहचान जाहिर करने से मीडिया ट्रायल होता है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की पवित्रता पर असर पड़ता है, जो क्रिमिनल ट्रायल में सबूत का अहम हिस्सा होती हैं। बेंच ने केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, क्योंकि याचिका में चंडीगढ़ पुलिस मॉडल को लागू करने की मांग की गई थी। यह मॉडल पुलिस को पीड़ितों, आरोपियों, शिकायतकर्ताओं या गवाहों की पहचान इस तरह से जाहिर करने से रोकता है जिससे उनकी प्राइवेसी, गरिमा और सुरक्षा पर असर पड़े।

भारतीय रेलवे में फिर लौटे डीजल इंजन?

लोको पायलटो की भारी कमी - केग रिपोर्ट ने खोली रेलवे मंत्रालय की पोल

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क के लगभग 99.6 प्रतिशत हिस्से के विद्युतीकरण का दावा किया है। कागजों पर यह बड़ी उपलब्धि है, सवाल यह है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे का संचालन तंत्र मजबूत हुआ है?

मुंबई-पुणे रूट की डेक्कन क्वीन, प्रगति एक्सप्रेस, सिंहगढ़ एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की कमी के कारण कुछ समय के लिए डीजल इंजन से चलाने की खबरों ने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। रेलवे ने बड़ी संख्या में पुराने डीजल इंजन हटाए, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति और उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ पाया।

सबसे गंभीर चिंता लोको पायलटों की कमी है। उपलब्ध आंकड़ों और रेलवे कर्मचारी संगठनों के दावों के अनुसार हजारों पद लोको पायलट के खाली हैं। कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव बढ़ने से थकान और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ा है। सेवानिवृत्त लोको पायलटों को दोबारा काम पर लेने की चर्चा गंभीरता को दर्शाती है।

केग की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में कई स्टेशनों पर पानी, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सेवाओं में कमियां सामने आईं है। इससे स्पष्ट होता है, केवल नए स्टेशन, वंदे भारत ट्रेनें और इलेक्ट्रिफिकेशन ही रेलवे की सफलता का पैमाना नहीं हो सकते हैं। रेलवे के सामने आज तीन बड़ी चुनौतियां हैं। पर्याप्त लोकोमोटिव, प्रशिक्षित स्टाफ और सुरक्षा से जुड़े संसाधन। ट्रैक और स्टेशन आधुनिक हो भी जाएं, उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी और इंजन उपलब्ध न हों, तो आधुनिकीकरण अधूरा है।

रेलवे देश की आम जनता की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। आवश्यकता इस बात की है, इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ मानव संसाधन, सुरक्षा, रखरखाव, यात्री सुविधाओं और इंजन उत्पादन की समान गति से तैयारी की जाए।

थामे से नही थम रहा बच्चो की मौतों का सिलसिला, फिर एक बच्चे ने तोड़ा दम

डिस्चार्ज के 3-4 दिन बाद फिर बिगड़ी तबियत,बच्चे की उखड़ी सांसे : संक्रमण से ग्रसित करीब 40 बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के आदिवासी अंचलों में फैली बीमारी से बच्चों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।जहा बीमारी की चपेट में आकर पहले ही कुछ बच्चे अपनी जान गवा चुके है तो वही कई बच्चे अब भी बीमारी से ग्रसित बताए गए है।उधर बच्चों की मौत के आंकड़ों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने है।इधर संक्रमण से ग्रसित बच्चों की उपचार के दौरान लगातार मौत की खबरें सामने आ रही है। बालाघाट जिला सहित संपूर्ण प्रदेश और देश में गूंज रहे इस मुद्दे के बीच महामारी प्रभावित ग्राम में एक और बच्चे की मौत हो गई।बताया गया कि उक्त बच्चे का जिला अस्पताल में उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था जिसकी गांव में मौत हो गई।हालांकि बच्चे की मौत किस कारण से हुई है,फिलहाल यह स्पष्ट नही हो पाया है।जिसकी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलने की बात विभाग द्वारा कही जा रही है।उधर क्षेत्र में फैली महामारी और बच्चों की मौत के बाद ना केवल स्वास्थ्य सचिव, कमिश्नर ने क्षेत्र का दौरा किया है, बल्कि, अब पूरा प्रशासनिक अमला भी वहां तैनात हो गया है। वर्तमान में अभी भी 40 के करीब बच्चे, जिला अस्पताल में भर्ती बताये जा रहे है।

संक्रमण ने छीनी 3 वर्षीय मासूम की जिंदगी

बालाघाट के बिरसा विकासखंड के ग्राम कुंडेकसा, अडोरी, कोरका, बोंडारी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और उपचार पर तेजी से काम कर रहा है। विषैली बीमारी, खांसी, बुखार, चर्मरोग, मीजल्स, स्कैबीज और मलेरिया जैसे मामलों के सामने आने के बाद विभाग लगातार घरेलू जांच स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ अमला भी बीमारी से हो रही मौतों को रोक नही पा रहा है।इसी बीच जिले के बिरसा विकासखंड अंतर्गत बैगा आदिवासी अंचल, अडोरी पंचायत के उसेकलटोला निवासी बिसन धुर्वे के मासुम बेटे आकाश (3) की मंगलवार को मौत हो गई। इसे मिलाकर क्षेत्र में अब तक 21 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, अभी भी 8 मौत ही बता रहा है।उधर पक्ष विपक्ष भी बच्चो की मौत वाले इस मामले में अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे है।

उपचार के बाद डिस्चार्ज कर भेजा गया था घर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में महामारी फैलने के बाद, आकाश को बुखार आने पर 4 अगस्त को जिला अस्पताल लाया गया था। जहां, उसके चार दिन चले उपचार के बाद 8 अगस्त को उसे छुट्टी दे दी गई थी। जिसके बाद परिजन, उसे लेकर गांव चले गए थे।बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल से घर लौटने के तीन-चार दिन बाद फिर उसकी तबियत खराब हो गई थी। जिसकी मंगलवार को मौत हो गई। हालांकि अभी आकाश की मौत महामारी में फैली बीमारी से हुई है या फिर उसकी,मौत की वजह कुछ और है, यह अभी साफ नहीं है। जिसके लिए उसके शव का पीएम कराया गया है। जिसका अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया।हलाकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गांव में फैली बीमारी जैसे कोई लक्षण, बच्चे में नहीं थे।

मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे है- संजय उइके

मामले को लेकर दुरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बैहर विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने शासन-प्रशासन पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। विधायक ने बताया कि आकाश के इलाज में लापरवाही बरती गई है। जिम्मेदार इस संवेदनशील मामले में लगातार अपनी गलतियों और आंकड़ों को छिपाने की कोशिश में लगे हैं।

मौत की वजह कुछ और हो सकती है- उपलप

सीएमएचओ डॉ. परेश उपलप ने बताया कि मासुम के गर्दन में सूजन थी और उसकी गर्दन जन्म से ही एक तरफ झुकी हुई थी। जिसे बचपन से ही गर्दन रोग था। ऐसे मामलों में दूध या भोजन आहार नली में जाने के बजाय श्वास नली में जाने की समस्या होती है। संभावना है कि खाना या दूध श्वास नली में चले गया होगा। जिससे उसे सास लेने में समस्या या घुटन महसुस हुई होगी। जिससे उसकी मौत की संभावना है।

बिरसा में बीमारी से बच्चों की मौत, जांच में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि

20 अगस्त से 9 माह से 10 वर्ष तक के बच्चों को लगेगी एमआर वैक्सीन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के बिरसा विकासखंड में फैली बीमारी के बीच बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार चिंता बढ़ा रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों में भले ही बीमारी से 8 बच्चों की मौत बताई जा रही हो, लेकिन प्रभावित ग्रामों में पिछले ढाई माह के दौरान अब तक 21 बच्चों की मौत होने की बात सामने आई है। बच्चों में फैली बीमारी को लेकर आईसीएमआर और अन्य संस्थानों द्वारा कराई गई जांच में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट में बच्चों की मौत के प्रमुख कारणों में मलेरिया और मीजल्स संक्रमण को बताया गया है। बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब 20 अगस्त से प्रभावित क्षेत्रों में मीजल्स-रूबेला वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रहा है। जांच में सामने आया है कि नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों में मीजल्स संक्रमण पाया गया है। वहीं एनआईवी पुणे में कराई गई जांच में चांदीपुरा वायरस, वेस्ट नाइल फीवर वायरस और जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस सहित विभिन्न वायरस की जांच निगेटिव पाई गई है। बीमारी की वजह सामने आने के बाद प्रशासन ने अब प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण और स्वास्थ्य निगरानी को और तेज करने की तैयारी की है। प्रभावित गांवों में शुरुआत में तीन बच्चों की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को गांव में बीमारी फैलने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बच्चों की मौत होने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ढाई माह में 21 बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर बीमारी की रोकथाम और प्रभावित परिवारों की स्थिति पर विशेष निगरानी की जा रही है। हालांकि वर्तमान में प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई सहित अन्य विभागों का अमला प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रहा है। कलेक्टर कुमार सत्यम ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में 20 अगस्त से मीजल्स-रूबेला अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत 9 माह से 10 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मीजल्स-रूबेला वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। अभियान की शुरुआत सबसे अधिक प्रभावित और उच्च प्राथमिकता वाले विकासखंडों से की जाएगी। बैहर, बिरसा और परसवाड़ा विकासखंड में 20 से 25 अगस्त तक एमआर कैचअप राउंड संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले बच्चों का दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है। प्रभावित गांवों में बच्चों की पोषण स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा टेक होम राशन उपलब्ध कराने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से गर्म और पका हुआ पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। संक्रमण को आगे फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर ने संक्रमित और प्रभावित बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता होने पर ऐसे बच्चों को आइसोलेट करने के लिए भी कहा गया है। प्रशासन का प्रयास है कि संक्रमित बच्चों के संपर्क में आने से अन्य बच्चों में बीमारी का संक्रमण न फैले और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार निगरानी में रखा जाए। अब 20 अगस्त से शुरू होने वाले एमआर वैक्सीनेशन अभियान पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि के बाद यह अभियान बीमारी की रोकथाम की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

यात्री बस में मचा हड़कंप, स्लीपर सीट पर अर्धनग्न हालत में मिला यात्री का शव

पदमेश न्यूज़। लांजी। हैदराबाद से लांजी के बीच चलने वाली निजी ट्रैवलर्स बस में उस समय हड़कंप मच गया, जब उसी बस की स्लिपर सीट पर बैठे एक यात्री की संदिग्ध अवस्था मे मौत हो गई।यात्री की मौत की जानकारी तब लगी जब हैदराबाद से लांजी पहुंचने के बाद एक यात्री बस से नहीं उतरा। इसपर यात्रियों और बस कर्मचारियों ने जब स्लीपर सीट पर जाकर देखा तो 42 वर्षीय यात्री आशीष पिता अरुण वासनिक का शव अर्धनग्न हालत में पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।स्थानीय लोगो ने मामले की सूचना तत्काल लांजी पुलिस को दी,उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।हालांकि यात्री की मौत कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है।जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

हैदराबाद में मजदूरी का काम करता था आशीष

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैहर निवासी आशीष वासनिक काफी समय से हैदराबाद में रहकर मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त की शाम करीब 5.30 बजे वह हैदराबाद से लांजी आने वाली निजी बस में सवार हुआ था। सफर के दौरान उसकी मौत हो गई। बस के लांजी पहुंचने पर जब वह अपनी स्लीपर सीट से नहीं उठा तो यात्रियों और बस स्टाफ ने उसे जगाने का प्रयास किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जब नजदीक जाकर देखा गया तो वह मृत अवस्था में था।

एक सप्ताह से खराब थी तबीयत

मृतक की भाभी सुनीता वासनिक ने पुलिस को दुरभाष पर बताया कि आशीष की तबीयत करीब एक सप्ताह से खराब चल रही थी। हैदराबाद से रवाना होने से पहले भी परिजनों से उसकी बातचीत हुई थी। शाम को भी फोन पर परिवार से बात हुई थी। इसके बाद बस में सफर के दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि आशीष परिवार में मंझला पुत्र था।

पत्नी और बच्चे पहले ही छोड़ चुके हैं साथ

परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी और बच्चे काफी समय पहले उसे छोड़ चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बैहर से परिजन लांजी के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने भी परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

पीएम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

लांजी पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। बस में यात्रा के दौरान मृतक की किन परिस्थितियों में मौत हुई और मौत से पहले उसकी किसी से बातचीत या अन्य गतिविधि हुई थी या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :**9425138710**, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायलयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट